चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

07 अप्रैल-13 अप्रैल 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

ये कार्ड ख़तरनाक है-5

आधार कार्ड एक विशिष्ट घोटाला

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

यूरोप और अमेरिका सहित हर विकसित देश ने बायोमैट्रिक डाटा पर आधारित विशिष्ट परिचय पत्र देने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्हें ख़तरे का आभास हुआ, उन्होंने यह प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया. भारत एक ऐसा अनोखा देश है, जहां ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर यह प्रोजेक्ट आज भी जारी है. यहां कोर्ट से लेकर संसद समिति तक चीख-चीखकर कह रहे हैं कि आधार प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती. सरकार से जब पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कुल कितना खर्च होगा, तो वह कहती है, पता नहीं. सरकार से जब पूछा जाता है कि लोगों ने जो बायोमैट्रिक डाटा जमा कराए हैं, उन्हें किन-किन कंपनियों और देशों के साथ शेयर किया गया है, तो वह कहती है कि पता नहीं. आधार कार्ड, जिसके बारे में यूपीए सरकार ने बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, वह एक घोटाले के रूप में विकसित होता जा रहा है, जो देश के कई विशिष्ट लोगों की इज्जत तार-तार कर देगा.

मनीष कुमार

कोई साधारण व्यक्ति झूठ बोलकर, झांसा देकर पैसे की हेराफेरी करता है, तो अदालत उसे सजा देती है. देश में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें धारा 420 के तहत सौ या पांच सौ रुपये की हेराफेरी में कई लोग बरसों से जेल में बंद हैं. कई सरकारी अधिकारी जनता के पैसे का उलट-फेर या गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सजा भुगत रहे हैं. देश का बड़ा उद्योगपति हो या प्रधानमंत्री का दोस्त, चाहे वह कोई भी हो, अगर देश की जनता को धोखा देकर जनता के ही पैसे को बर्बाद कर देता है, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल जुर्म है, तो बंगलुरू से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नंदन नीलेकणी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा क्यों नहीं चला? क्या हम ऐसे देश में रहते हैं, जहां अगर कम पैसे की धोखाधड़ी हो, धोखाधड़ी करने वाला कम रसूख वाला हो, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और अगर धोखाधड़ी करने वाला रसूख वाला हो, प्रधानमंत्री का दोस्त हो, मीडिया वाले, टीवी एंकर और संपादक जिसे सलाम ठोंके, तो वह झांसा देकर सरकार के हजारों करोड़ रुपये बर्बाद भी कर दे, फिर भी उसके ख़िलाफ़ एक भी आवाज़ नहीं उठेगी?

नंदन नीलेकणी देश में आधार कार्ड बनाने वाली योजना के जनक हैं. उन्होंने झांसा देकर यह योजना देश पर लादी है. वह देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जो बिना शपथ लिए कैबिनेट मंत्री के बराबर ओहदे पर मौजूद रहे. वह आधार कार्ड बनाने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख रहे. फिलहाल वह बंगलुरू से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनकर. उनके प्रत्याशी बनने के बाद जब हंगामा हुआ, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कुछ ऐसे आदेश जारी किए हैं, जिनसे उनकी परेशानी बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और आधार कार्ड को सबके लिए अनिवार्य बनाने का आदेश सरकार तुरंत वापस ले. न्यायालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह बायोमैट्रिक डाटा किसी दूसरी संस्था को नहीं दे. सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत आतंकवाद और बलात्कार के मामलों में यह डाटा साझा करने की छूट दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड न होने से किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा हासिल करने से वंचित न किया जाए. इसका मतलब यह है कि चाहे रसोई गैस हो या कोई और सेवा, अब बिना आधार कार्ड के भी आप इन सेवाओं को ले सकते हैं. वैसे आधार कार्ड को लेकर एक मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद सरकार एवं नंदन नीलेकणी की और भी किरकिरी हो सकती है. आधार कार्ड विवादों में इसलिए है, क्योंकि चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार ने सबसे पहले आधार कार्ड से होने वाले ख़तरों का खुलासा किया था. हमने यह खुलासा किया था कि किस तरह आधार कार्ड सीआईए और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हमारी और आपकी सारी जानकारी पहुंचाने की साजिश है. समय के साथ-साथ चौथी दुनिया की सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग रही है.

सूचना का अधिकार क़ानून के तहत निकली एक जानकारी के मुताबिक, यह बताया गया है कि बायोमैट्रिक सिस्टम 100 फ़ीसद एक्यूरेट नहीं है और दूसरी बात यह कि आधार कार्ड की विशिष्टता भी काल्पनिक है. यह जानकारी योजना आयोग के साथ करार करने वाली एर्नेस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड और नेटमैजिक सोल्यूशन प्राइवेट

(शेष पृष्ठ 2 पर)

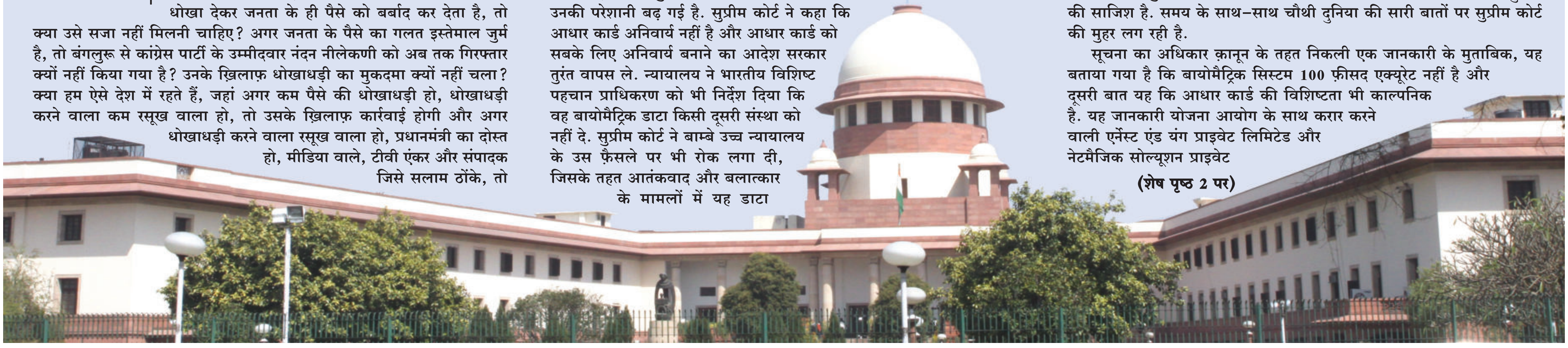

वादे हैं वादों का क्या 03

लड़ाई प्रो-मोदी और एंटी-मोदी वोटों के बीच 05

ब्रू शरणार्थियों के लिए बेमानी है लोकतंत्र का यह महापर्व 07

साई की महिमा 12

आधार कार्ड-एक विशिष्ट घोटाला

पृष्ठ एक का शेष

लिमिटेड ने दी है. इस सूचना के साथ ही आधार कार्ड का आधार ख़त्म हो जाता है. इस कार्ड को लेकर नंदन नीलेकणी ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वे सब झूठे साबित होते हैं. नंदन नीलेकणी ने इस योजना की शुरुआत में दावा किया था कि यह अब तक का सबसे सटीक व अति विशिष्ट कार्ड है और इसकी नकल नहीं की जा सकती. नंदन नीलेकणी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने देश को गुमराह क्यों किया? केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड की योजना लॉन्च की, तो उसकी शान में जमकर कसीदे काढ़े गए थे. बड़े-बड़े दावे हुए कि आधार कार्ड बनने के बाद लोगों को तरह-तरह के पहचान पत्र दिखाने के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन यूपीए सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में धांधली चरम पर है. चंद रुपये खर्च करके कोई भी आधार कार्ड बनवा सकता है. हाल में एक साइट के स्टिंग ऑपरेशन के जरिये यह खुलासा हुआ है कि अवैध बांग्लादेशी चंद रुपये देकर आसानी से आधार कार्ड बनवा लेते हैं और भारत के मान्यता प्राप्त नागरिक बन जाते हैं और फिर मतदान में हिस्सा लेने के लिए वैध हो जाते हैं. जबकि यूपीए सरकार के मंत्री और इस प्रोजेक्ट के सर्वेसर्वा नंदन नीलेकणी ने भरोसा दिलाया था कि कोई भी अवैध प्रवासी हमारे देश का फर्जी पहचान पत्र नहीं बनवा पाएगा और न उसका कोई डुप्लीकेट बन सकता है. आधार कार्ड का प्रोजेक्ट पूरी तरह एक घोटाले की शक्ल ले चुका है. सुप्रीम कोर्ट को अब फ़ैसला करना होगा कि क्या नंदन नीलेकणी पर कोई आपराधिक मामला बनता है या नहीं.

यह एक घोटाला इसलिए भी है, क्योंकि अब आधार कार्ड का तकनीकी और क़ानूनी आधार ही सवालों के घेरे में है. इससे जुड़ी संस्थाओं ने तकनीकी खामियां मानकर उन सारे दावों की पोल खोल दी, जो नंदन नीलेकणी ने अब तक बेचते आए हैं. इस खुलासे के बाद सरकार और प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. हमें यह याद रखना चाहिए कि आधार कार्ड का कोई क़ानूनी आधार ही नहीं है. यह देश का अकेला ऐसा कार्यक्रम है, जिसे संसद में पेश करने से पहले ही लागू करा दिया गया. असलियत यह है कि यूपीए सरकार इस क़ानून को संसद में पास भी नहीं करा सकती है, क्योंकि संसदीय कमेटी ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. संसदीय कमेटी ने कहा है कि आधार योजना तर्कसंगत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है. आधार के ख़िलाफ़ केस करने वाले स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज रहे हैं. जस्टिस के एस पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है. इस पिटीशन पर देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जजों ने सहमति दिखाई है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के किस क़ानून के आधार पर लोगों के बायोमैट्रिक्स को एकत्र किया जा रहा है? देश में मौजूद सारे क़ानून खंगालने के बाद पता चलता है कि ऐसा क़ानून सिर्फ़ जेल मैन्युअल में है. यह सिर्फ़ क़ैदियों का लिया जा सकता है और इसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वह क़ैदी रिहा होगा, उसके बायोमैट्रिक्स से जुड़ी फाइलें जला दी जाएंगी, लेकिन इस योजना के तहत सरकार लोगों की सारी जानकारियां एकत्र कर रही है और विदेश भेजने पर तुली है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया है कि प्राधिकरण लोगों के बायोमैट्रिक डाटा किसी को नहीं दे सकता है. यह जनता की अमानत है और इसे दूसरी एजेंसियों के साथ शेयर करना मौलिक अधिकारों का हनन है.

अब यहां एक टेक्निकल सवाल उठता है. प्राधिकरण ने तो लोगों की सारी बायोमैट्रिक जानकारियां सिर्फ़ शेयर नहीं की हैं, बल्कि उन्हें विदेशी कंपनियों के सुपुर्द कर दिया है. यही आधार कार्ड के काम करने का तरीका है. जितनी भी बायोमैट्रिक जानकारियां हैं, उनकी देखरेख और ऑपरेशन उन कंपनियों के हाथों में है, जिनका रिश्ता ऐसे देशों से है, जो जासूसी कराने के लिए कुख्यात हैं और उन कंपनियों के हाथों में है, जिन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड अधिकारी चलाते हैं. इसका क्या मतलब है? क्या हम जानबूझ कर अमेरिका और विदेशी एजेंसियों के हाथों अपने देश को ख़तरे में डाल रहे हैं? हाल के दिनों में एक खुलासा हुआ था कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी एनएसए जिन देशों के इंटरनेट और फोन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, उनमें पहला नंबर भारत का है. भारत का टेलीफोन और इंटरनेट डाटा इकट्ठा करने के लिए एनएसए ने अपने दो कार्यक्रमों का सहारा लिया है. मजेदार बात यह है कि अमेरिकी सरकार के खुफिया निदेशालय ने भी एक तरह से जासूसी कराने के आरोपों को स्वीकार किया था. निदेशालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि यह उसकी खुफिया नीति का ही एक हिस्सा है. कांग्रेस सरकार को अमेरिका के इस दुस्साहस, ऐसी निगरानी और जासूसी के ख़िलाफ़ कड़ा विरोध जताना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद विरोध करने की बजाय अमेरिकी हरकत को सही ठहराने के लिए उल्टी-पुल्टी दलीलें देने लग गए. सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह जासूसी नहीं है, यह तो महज कंप्यूटर अध्ययन और कॉलों के पैटर्न का विश्लेषण है. अगर यह जासूसी नहीं है, तो सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि जासूसी क्या होती है?

वैसे अमेरिका के जासूसी प्रकरण पर उसकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) के साथ काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने हाल में कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि आज के इन्फारमेंशन वारफेयर में भारत कई देशों के निशाने

फोटो-प्रभात पाण्डेय

पर है. इसलिए भारत के योजना आयोग ने एर्नेस्ट एंड यंग, साफ्रान ग्रुप, एसेन्चर, इन-क्यू-टेल एवं मोंगो डीबी जैसी कंपनियों से करार करके देश की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ मजाक किया है. ये कंपनियां उन देशों की हैं, जिनका गठजोड़ पूरी दुनिया पर निगरानी के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा है. स्नोडेन ने ही अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसी कार्यक्रम का सनसनीखेज ब्योरा मीडिया को लीक किया था. अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए द्वारा संचालित एक्स की स्कोर जासूसी कार्यक्रम 2008 की एक प्रशिक्षण सामग्री में वह नक्शा भी शामिल था, जिसमें दुनिया भर में लगे सर्वर का ब्योरा था. उस नक्शे के मुताबिक, उनमें से एक अमेरिकी जासूसी सर्वर भारत की राजधानी नई दिल्ली के किसी समीपवर्ती इलाके में लगा हुआ प्रतीत होता है. समझने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों को यूआईडी ने हमारी जानकारियां सुपुर्द की हैं, वे वही कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में निगरानी प्रणाली स्थापित करने में माहिर मानी जाती हैं.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद और भारत की आज़ादी से पहले एक नेटवर्क विकसित हुआ था. इसके गठन का एकमात्र उद्देश्य दूसरे देशों की निगरानी करना था. इसमें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इंग्लैंड के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वाटर्स, कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट, ऑस्ट्रेलिया का सिग्नल डायरेक्टोरेट और न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो आदि शामिल हैं. अब इस गुट में कई और देश भी शामिल हो चुके हैं. ऐसे माहौल में भारत को स्वयं को सुरक्षित करने के लिए क़दम उठाने चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल उल्टे फ़ैसले लेते हैं. ऐसी क्या वजह है कि सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है? जबकि संसदीय कमेटी ने भी इसका विरोध किया है. यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नज़र रखने और उनके जैवमापक रिकॉर्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत की और इसे बंद करने का सुझाव दिया. फिर भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि क्या अब तक एकत्र किए गए बायोमैट्रिक डाटा को प्राधिकरण ने किसी विदेशी कंपनी के साथ शेयर किया है या दिया है? अगर ये जानकारियां विदेशी एजेंसियों के हाथ लग चुकी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी निगरानी में आ चुके हैं और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कोई मतलब नहीं है, जिसमें उसने कहा कि ये जानकारियां किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं.

समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां कई देशों में सक्रिय हैं. इनके पास वे तमाम तकनीक उपलब्ध हैं, जिससे ये किसी भी देश की इंटरनेट कंपनियों के डाटा एकत्र कर सकती हैं, सर्वर हैक कर सकती हैं, फोन सुन सकती हैं. इन कंपनियों की पहुंच कई देशों में है और ये किस तरह और किस स्तर पर काम कर सकती हैं, इसी का खुलासा स्नोडेन ने किया था. विदेशी एजेंसियों की कारगुजारी और आधार कार्ड योजना की गड़बड़ियां एक ख़तरे को जन्म देती हैं. उम्मीद यही करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल, 2014 को जब अगली सुनवाई होगी, तो अदालत इन ख़तरों पर भी ध्यान देगी.

समझने वाली बात यह है कि देश में एक विशिष्ट पहचान पत्र के लिए विप्रो नामक कंपनी ने एक दस्तावेज तैयार किया, इसे योजना आयोग के पास जमा किया गया. इस दस्तावेज का नाम है स्ट्रेटिजिक विजन ऑन द यूआईडीएआई प्रोजेक्ट. मतलब यह कि यूआईडी की सारी दलीलें, योजना और उसका दर्शन इस दस्तावेज में है. बताया जाता है कि यह दस्तावेज अब गायब हो गया है. विप्रो ने यूआईडी की ज़रूरत को लेकर 15 पेजों का एक और दस्तावेज तैयार किया, जिसका शीर्षक है, डज इंडिया नीड ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर. इस दस्तावेज में यूआईडी की ज़रूरत को समझाने के लिए विप्रो ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया. इस प्रोजेक्ट को इसी दलील पर हरी झंडी दी गई थी. हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी योजना बंद कर दी. वहां जो जांच हुई, उससे यही साबित हुआ कि यह कार्ड ख़तरनाक है, इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि जब इस योजना की पृष्ठभूमि ही आधारहीन और दर्शनविहीन हो गई, तो फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इसे लागू करने के लिए सारे नियम-क़ानूनों और विरोधों को दरकिनार करने पर आमादा है? जिस तरह फाइल गायब हुई, उसी तरह अब नंदन नीलेकणी भी गायब हो गए हैं. वह अब राजनेता बन गए हैं, ताकि आगे जब इस घोटाले के बारे में बहस हो, तो पूरा मामला राजनीतिक हो जाए. अगर नई सरकार आती है, तो उसे यूआईडी पर पुनर्विचार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार सभी एकत्र बायोमैट्रिक जानकारियां सुरक्षित करनी पड़ेंगी. विदेशी कंपनियों के साथ कौन-कौन से खुफिया करार किए गए, उन्हें जनता को बताना पड़ेगा. कितना पैसा बर्बाद हुआ, यह भी जनता को पता चलना चाहिए और उसे वापस लाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई निजी कंपनी का मालिक और मीडिया द्वारा बनाया गया महापुरुष देश की जनता और सरकार को मूर्ख न बना सके. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 05
दिल्ली, 07 अप्रैल-13 अप्रैल 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चक्रवर्ती के इस्तीफ़े की वजह

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले जब इस्तीफ़ा दिया था, तो उस समय बहुत आश्चर्यचकित हुए थे. उन्होंने अपने इस्तीफ़े की बात किसी को नहीं बताई थी. क्या उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के कारण इस्तीफ़ा देना पड़ा या उनके इस्तीफ़े के पीछे कोई अन्य कारण था? उनके इस क़दम को लेकर चर्चाएं भी कम नहीं हो रही हैं. कुछ मशहूर समीक्षकों का मानना है कि चक्रवर्ती खुद की बात कहने में यकीन करते थे और वर्तमान गवर्नर राजन के पूर्ववर्ती डी सुब्बाराव से बहुत सारे नीतिगत मामलों पर उनका मतभेद भी था. अगस्त 2010 में उनके द्वारा मुद्रास्फीति से निबटने की आरबीआई की मौद्रिक नीतियों पर सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद उनसे कई विभाग भी छीन लिए गए थे. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि चक्रवर्ती ने एक विशेष विदेशी कार्य हासिल करने के लिए इस्तीफ़ा दिया है. चक्रवर्ती के इस्तीफ़े के पीछे चाहे जो भी कारण हो, लेकिन लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे समय में उनके इस्तीफ़ा देने से सरकार असहज हो गई है. सरकार ज़रूर चाहेगी कि चक्रवर्ती की जगह कोई अन्य अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाए, लेकिन यह चुनाव से पहले संभव होता नहीं दिखता. कहने का मतलब यह है कि अब इस पद पर नई सरकार के गठन के बाद ही कोई फ़ैसला हो सकता है. चक्रवर्ती के इस्तीफ़े और आनंद सिन्हा के इसी साल जनवरी में सेवानिवृत्त होने के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के दो पद खाली हैं. ■

कौन होगा अगला कैबिनेट सचिव

कैबिनेट सचिव अजीत कुमार सेठ इसी साल जून महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उसी समय केंद्र में नई सरकार का भी गठन होगा. उन्हें पिछले साल एक साल का सेवाविस्तार दिया गया था, जो यूपीए-2 के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ख़त्म होने वाला है. सूत्रों का कहना है कि सेठ के कार्यकाल का समय जैसे-जैसे नज़दीक आता जा रहा है, इस पद के लिए योग्य अधिकारियों ने लॉबिंग तेज कर दी है. इस पद की दौड़ में भारी उद्योग सचिव सुतानू बेहुरिया, जल संसाधन सचिव आलोक रावत के साथ-साथ कॉरपोरेट मामलों के सचिव नावेद मसूद भी शामिल हैं. बेहुरिया अगर इस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो वह इस साल के अगस्त महीने में सेवानिवृत्त हो जाएंगे. हालांकि, इस पद के लिए अधिकारियों की वरीयता का खास महत्व है, लेकिन सब कुछ नई सरकार और उसकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है. इसलिए इस पर कयासों का दौर ख़त्म होने वाला है. ■

वित्त मंत्रालय में लॉबिंग तेज

वित्त सचिव सुमित बोस की सेवानिवृत्ति इस महीने के अंत में होने वाली है. उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही वित्त मंत्रालय में इस पद के लिए नए चेहरों के बीच सुगबुगाहट तेज होने लगी है. संभावना है कि 1979 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव टकरू को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा. टकरू बोस की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह पर नियुक्त होंगे. सूत्रों का कहना है कि वर्तमान के सभी वित्त सचिवों में सबसे वरिष्ठ और आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम को भी वित्त सचिव बनाया जा सकता है. 1980 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी गुरुदयाल सिंह संधू को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने टकरू के स्थान पर नियुक्त किया है. संधू राजस्थान में शहरी आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव थे. हालांकि अधिकारियों की नज़र वित्त मंत्रालय में नए आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति को लेकर भी है. यह पद रघुराम राजन के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने के बाद से ही खाली है.■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

आलोक कार्यकारी निदेशक बनेंगे

1995 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को जल्द ही एयर इंडिया का कार्यकारी निदेशक (सुरक्षा) नियुक्त जा सकता है. वह इस समय प्रवर्तन निदेशालय में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के निजी सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं. आलोक सिंह बी के मौर्या का स्थान लेंगे, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सात साल पूरे करने के बाद अपने मूल कैडर में वापस जाएंगे. मौर्या ने नवंबर 2012 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था.

अख्तर उपसचिव नियुक्त

2003 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी एहतेशाम अख्तर पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग में उपसचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वह प्रशांत कुमार (आईआरटीएस-1991) की जगह लेंगे, जो एपीपीए पाठ्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं.

अमित भूमि संसाधन विभाग से जुड़े

1996 बैच एवं गुजरात कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी अमित कुमार को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है. वह 1985 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी वासु मित्रा अरोरा का स्थान लेंगे.

कुमार संयुक्त सचिव बने

1984 बैच एवं बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अजय कुमार जल्द ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होंगे. वह ई एस कार से प्रभार लेंगे, जिनका चयन अध्ययन अवकाश के लिए किया गया है.

कुंद्रा मूल कैडर में वापस जाएंगे

1996 बैच एवं एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी एवं वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के निजी सचिव आशीष कुंद्रा अपने मूल कैडर में वापस जाएंगे. वह शीघ्र ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की समयावधि पूरी करने वाले हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

> कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घर का अधिकार की बात कही है. इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के दायरे में सभी शहरी और ग्रामीण गरीबों को शामिल किए जाने की बात कही है. एक बार फिर कांग्रेस ने इन दोनों योजनाओं में ज्यादा पैसे देने का वादा किया है. यानी कांग्रेस यह मान कर चल रही है कि सिर्फ ज्यादा पैसे दे देने भर से किसी योजना को सफल बनाया जा सकता है.

कांग्रेस का घोषणा पत्र

वादे हैं वादों का क्या

पिछले 20 सालों में इसी खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, जिसे वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, की देन है कि आज इस देश में कोयला, पानी, हवा, तरंग में भी लाखों करोड़ों के घोटाले होते है. यही अर्थव्यवस्था है जहां आज क्रोनी कैपिटलिज्म की बात हो रही है. यही प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है जिसने लघु और कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया है. आज जब जरूरत इस बात की थी कि नई आर्थिक नीतियों के विकल्प पर सोचा जाए, कांग्रेस उसी पुरानी अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाना चाहती है जिसने देश की सत्तर फीसदी आबादी को रोजाना 20 रूपये की आमदनी पर जीने को मजबूर कर दिया है.

शशि शेखर

चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती. इसके अलावा, इन वादों को पूरा करने के लिए किसी तरह की नैतिक बाध्यता भी नहीं होती. यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणाएं महज चुनावी लाभ हासिल करने के लिए होते है. एक बार चुनाव में जीत मिल जाए, सत्ता हासिल हो जाए, फिर इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता. कांग्रेस पिछले दस सालों से सत्ता में है. एक बार फिर चुनावी मैदान में है. एक बार फिर कांग्रेस ने घोषणाओं और वादों का पिटारा खोल दिया है. ऐसे में यह देखना जरूरी है कि पिछले चुनाव में किए गए वादें कितने पूरे हुई और अभी के वादों का क्या मतलब है?

2014 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में सेहत का अधिकार को मुख्य रूप से स्थान दिया है. घोषणापत्र के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का तीन प्रतिशत किया जाएगा. जाहिर तौर पर यह एक ऐसा मसला है जिसका कोई विरोध नहीं हो सकता. स्वास्थ्य का अधिकार जनता के लिए मूल अधिकार की तरह ही है. लेकिन क्या कांग्रेस से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2009 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने जिस स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया था, उसे पांच सालों में क्यों नहीं पूरा कर पाई? आखिर पांच साल पुराने वादे को पूरा न कर पाने के लिए कांग्रेस को और पांच साल क्यों चाहिए और क्यों दिया जाना चाहिए? बहरहाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में निवेश एक अच्छी बात है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ पैसा बढ़ा देने से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी स्तर है, की हेल्थ सुधारी जा सकती है. देश में आज सरकारी स्वास्थ्य सेवा की जो संरचना है, उसकी असलियत सब को पता है. पिछले कुछ समय में पंचायत स्तर पर बढ़े भ्रष्टाचार की वजह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर खस्ताहाल हो चुका है. यूपीए 1 व 2 के दौरान भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाए गए. लेकिन उसका हश्र सबको पता है. पोलियो पर जहां भारत ने काबू पाया वहीं कांग्रेस की सरकार पिछले दस सालों में बाल मृत्यु दर, प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत की संख्या, कुपोषण आदि पर लगाम नहीं लगा पाई. आज भी करोड़ों लोगों को साफ पीने का पानी नसीब नहीं है. ऐसे में सिर्फ पैसा बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो जाएगी, इसकी गुंजाइश कम ही है, उल्टे ज्यादा पैसे का अर्थ ज्यादा भ्रष्टाचार के रूप में दिख सकता है.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घर का अधिकार की बात कही है. इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के दायरे में सभी शहरी और ग्रामीण गरीबों को शामिल किए जाने की बात कही है. एक बार फिर कांग्रेस ने इन दोनों योजनाओं में ज्यादा पैसे देने का वादा किया है. यानी कांग्रेस यह मान कर चल रही है कि सिर्फ ज्यादा पैसे दे देने भर से किसी योजना को सफल बनाया जा सकता है. इंदिरा आवास योजना का सच अगर जानना हो तो बिहार या उत्तर प्रदेश के गांवों में देखा जा सकता है. जैसे–जैसे इस योजना के तहत लाभार्थी के लिए ज्यादा पैसा बढ़ता गया, पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों का कमीशन भी बढ़ता गया. हालत यह है कि आज 60 हजार में से 20 हजार रुपये कमीशन देने के बाद ही किसी को इस योजना का लाभ मिल पाता है. यह एक खुला सच है, जिसे हर कोई जानता है. ऐसे में एक बार फिर केवल पैसा बढ़ाने से योजना सफल होगी, ऐसा सोचना सच को न देखने जैसा है. शहरों में जमीन का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, ऐसे में शहरी गरीबों को घर मुहैया कराने के लिए किस तरह की नई तकनीक व योजनाओं की जरूरत है, इस पर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस घोषणापत्र में कुछ नहीं कहा है. यानी कांग्रेस यह मान कर चल रही है कि जनता को सिर्फ यह दिखाया जाए कि फलां–फलां योजना में ज्यादा से ज्यादा पैसे देने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और इससे जनता प्रभावित हो जाएगी.

2014 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने पेंशन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार और उद्यमिता का अधिकार देने की बात कही है. अब जरा कांग्रेस के 2009 के घोषणापत्र को भी देखिए. 2009 में भी कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा देने व नेशन वाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की बात कही थी. अब क्या कांग्रेस इस देश की जनता को यह बताएगी कि आखिर पिछले पांच सालों में ऐसी क्या समस्या आई जिससे कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकी. क्या कांग्रेस को यह नहीं बताना चाहिए कि क्यों जनता उसे इन वादों को पूरा करने के लिए पांच साल और दे?

इस घोषणापत्र में विकास दर को अगले तीन सालों के दौरान आठ प्रतिशत के स्तर पर लाने का आश्वासन दिया गया है. वहीं एक खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने की बात कही है. सबसे दिलचस्प वादा यही है. मसलन, पिछले 20 सालों में इसी खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, जिसे वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, की देन है कि आज इसे देश में कोयला, पानी, हवा, तरंग में भी लाखों करोडों के घोटाले होते है. यही अर्थव्यवस्था है जहां आज क्रोनी कैपिटलिज्म की बात हो रही है. यही प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है जिसने लघु और कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया है. आज जब जरूरत इस बात की थी कि नई आर्थिक नीतियों के विकल्प पर सोचा जाए, कांग्रेस उसी पुरानी अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाना चाहती है जिसने देश की सत्तर फीसदी आबादी को रोजाना 20 रुपये की आमदनी पर जीने को मजबूर कर दिया है. कांग्रेस ने विनिर्माण क्षेत्र में दस प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य, छोटे और मझोले उद्योगों पर जोर देने की बात कही है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मौजूदा अर्थव्यवस्था के रहते हुए छोटे और मझोले उद्योगों को पुनर्जीवीत किया जा सकता है?

कृषि के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने चुनावी वादों की बौछार कर दी है. मसलन, सिंचाई, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, कोल्ड स्टोर और वेयरहाउस में निवेश बढ़ाया जाएगा. लेकिन इस निवेश से छोटे–मंझोले और सीमांत किसानों को कितना फायदा होगा, यह सवाल अनुत्तरित रह जाता है. आज जब देश में कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में देश के आम किसानों को कृषि क्षेत्र में निवेश से कैसे और कितना फायदा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. अगले एक दशक के दौरान बिजली, परिवहन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास में 1000 अरब डालर के निवेश की बात कही गई है वहीं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक लचीली श्रम नीति को बढ़ावा देने की बात भी है. वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव बढ़ाने के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिए जाने का वादा इस घोषनापत्र में किया गया है. इसके अलावा, 18 महीनों के भीतर सभी ग्राम पंचायतों और कस्बों को हाई स्पीड ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की गई है. हालांकि, यह घोषणा यूपीए2 के दौरान भी की गई थी जिसे आज तक पूरा नहीं किया जा सका है.

कांग्रेस ने काले धन को वापस लाने के लिए विशेष दूत की नियुक्ति की बात कही है. लेकिन यह घोषणा कितना बड़ा छलावा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है कि खुद यूपीए 2 ने स्वीट्जरलैंड के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत काला धन के मालिक का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, सरकार के पास ऐसे कई लोगों के नाम भी मौजूद है जिनके पास काला धन है लेकिन जिसे आज तक सरकार ने सार्वजनिक करना जरूरी नहीं समझा. ऐसे में जब कांग्रेस काला धन पर किसी भी तरह का वादा करती है तो इसे क्या समझा जाए? कांग्रेस ने अगले पांच सालों के दौरान दस करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की बात कही है. अब यह सपना कैसे पूरा किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है?

कांग्रेस ने सांप्रदायिक हिंसा विधेयक को जल्द से जल्द पास कराने की बात कही है लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग के सुझावों के मुताबिक आरक्षण पर कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा है. वहीं यूपीए सरकार शुरू से महिला आरक्षण विधेयक की बात करती रही है. इस बार भी इसे पास कराने के लिए वादा किया गया है. लेकिन जब बात इसे पास कराने की आती है तो संसद के भीतर क्या हाल होता है, इसे पूरा देश जानता है. यह अलग बात है कि तेलंगाना बिल को संसद का दरवाजा बंद कर के पास कर दिया जाता है लेकिन महिला आरक्षण विधेय के नाम पर सरकार सर्वसम्मति का इंतजार करती रही. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

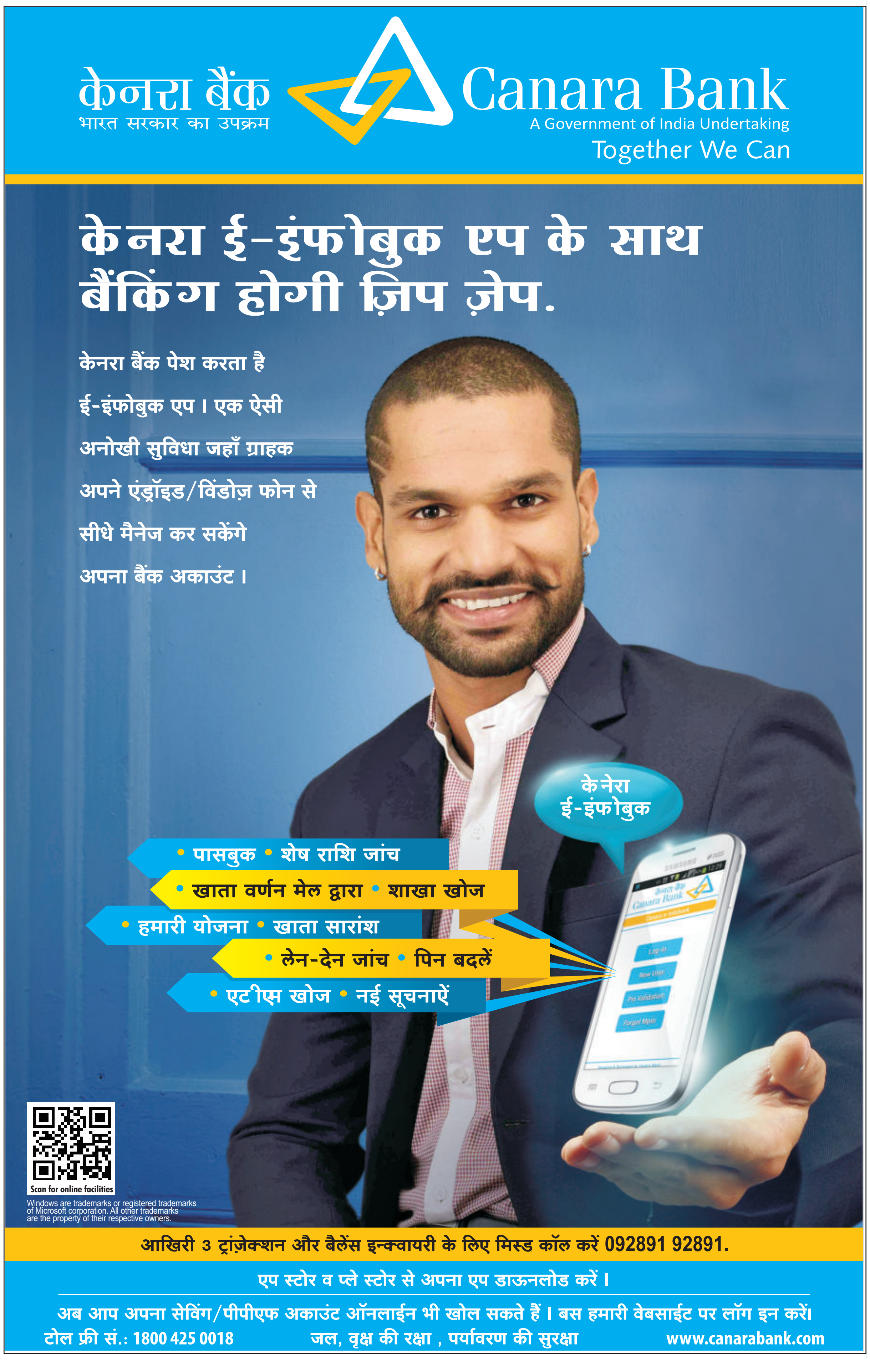

15वीं लोकसभा में राज्य से जो सात मुस्लिम सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनमें बसपा के चार उम्मीदवार, जैसे कैराना से तबस्सुम बेगम, मुजफ्फरनगर से कादिर राणा, संभल से डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क एवं सीतापुर से कैसर जहां और कांग्रेस के तीन उम्मीदवार, जैसे मुरादाबाद से मुहम्मद अजहरुद्दीन, खीरी से जफर अली नकवी एवं फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद थे.

उत्तर प्रदेश

मुसलमान किधर जाएंगे

ए यू आसिफ

यह प्रश्न निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है कि 80 संसदीय सीटों, जिनमें 63 सामान्य एवं 17 सुरक्षित हैं, वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 18.5 प्रतिशत मुस्लिम आबादी 16वीं लोकसभा के चुनाव में क्या रुख अख्तियार करने जा रही है और किधर जा रही है. उल्लेखनीय है कि राज्य के कुल 80 संसदीय क्षेत्रों में कम से कम 45 क्षेत्र ऐसे हैं, जहां जनसंख्या के लिहाज से मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण और असाधारण हैं. राज्य में मुस्लिम वोट राजनीति का रुख तय करने की स्थिति में है. यह अलग बात है कि 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में यहां से मात्र सात मुस्लिम सदस्य निर्वाचित हुए थे, परंतु सामूहिक तौर पर उनके वोट का महत्व कम से कम 45 क्षेत्रों में है. यही कारण है कि पूरे देश की निगाह संसदीय सीटों की सबसे बड़ी संख्या होने के कारण इस राज्य पर रहती है, वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों का निशाना वे क्षेत्र होते हैं, जहां जनसंख्या के लिहाज से मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण हैं.

ज्ञात रहे कि 15वीं लोकसभा में राज्य से जो सात मुस्लिम सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनमें बसपा के चार उम्मीदवार, जैसे कैराना से तबस्सुम बेगम, मुजफ्फरनगर से कादिर राणा, संभल से डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क एवं सीतापुर से कैसर जहां और कांग्रेस के तीन उम्मीदवार, जैसे मुरादाबाद से मुहम्मद अज-हरुद्दीन, खीरी से जफर अली नकवी एवं फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद थे. अतएव यहां इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि इस बार 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम नुमाइंदगी का यह रुझान पिछली बार वाला ही रहेगा या बदलेगा? और क्या 2012 के विधानसभा चुनाव में अधिकतर मुस्लिम वोट पाने वाली सपा मुस्लिम उम्मीदवारों के लिहाज से इस बार अपना खाता खोल भी पाएगी? आम आदमी पार्टी, जिसने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल को खड़ा करके राज्य के मुसलमानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, किसी मुस्लिम उम्मीदवार को इस बार भेज भी पाएगी?

आइए देखते हैं कि इस बार राज्य में मुसलमानों के बीच क्या हो रहा है? देवबंद स्थित मदरसा दारुल उलूम, जिसे इस्लामिक जगत में प्रसिद्धि हासिल है, के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी बनारसी ने एक असाधारण विज्ञप्ति में खुले तौर पर कहा है कि 2014 के संसदीय चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों एवं उम्मीदवारों के मदरसा परिसर में आने पर पाबंदी लागू कर दी गई है. इसके अनुसार, चुनाव पूर्व किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा और न नेताओं या पार्टियों की सफलता के लिए दुआ कराई जाएगी. इस संबंध में यह भी कहा गया है कि दुआ कराने के ध्येय से भी कोई उम्मीदवार इस संस्था में न आए.

उल्लेखनीय है कि आम तौर पर चुनाव के दौरान यह मदरसा राजनीतिज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है और उलेमा से आशीर्वाद एवं दुआ लेने के लिए बड़े-छोटे नेताओं की भीड़ लग जाती है. ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की इच्छा रखने वाले नेताओं को निराशा हाथ लगेगी और मदरसा के इस सख्त निर्णय से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जबरदस्त धक्का पहुंचेगा. कहा जाता है कि दारुल उलूम देवबंद के इतिहास में इस तरह का निर्देश पहली बार जारी किया गया है. यह वही दारुल उलूम है, जिसने स्वाधीनता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसके हजारों उलेमा इस सिलसिले में शहीद भी हुए थे. यहां से जारी किए गए किसी निर्देश को मुसलमानों में बहुत ही महत्व एवं निष्ठा के साथ देखा जाता है. अतएव राज्य में हो रहे संसदीय चुनाव पर इस निर्देश का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा.

प्रश्न यह भी है कि आख़िर इस असाधारण निर्देश का कारण क्या है और इसे जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ग़ौरतलब है कि इस निर्देश को जारी करने के चार दिन पहले 20 मार्च को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया दारुल उलूम देवबंद पहुंचे. दूसरे दिन यह ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मदरसे से समर्थन मांगा और वह उपकुलपति मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी से भी मिले. कहा जाता है कि इस समाचार से मदरसा के कुलपति एवं अन्य ज़िम्मेदार परेशान हो गए और फिर उपरोक्त निर्देश जारी किया गया. ग़ौरतलब यह भी है कि दारुल उलूम में चुनाव के अवसर पर राजनीतिज्ञ हमेशा आते रहे हैं. 25 साल पहले चार मार्च को भी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव यहां पधारे थे और उस समय के तक़रीबन 100 वर्षीय कुलपति मौलाना मरगूबुर्रहमान से आशीर्वाद लिया था और वापस लौटकर उनके साथ खींची गई तस्वीर को घनी आबादी वाले मुस्लिम क्षेत्रों में खूब फैलाकर मुस्लिम मतों को अपने हक़ में करने की चेष्टा की थी. उन दिनों यह ख़बर भी आई थी कि मुलायम ने स्वर्गीय मौलाना एवं दीगर ज़िम्मेदारों से पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से उन दिनों सपा से की गई संधि के संबंध में सफाई पेश की थी. उसके बाद कल्याण सिंह ने भी मदरसा के ज़िम्मेदारों से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, मगर ऐसा संभव नहीं हो सका था. यह बात भी कही जा रही है कि दारुल उलूम के वर्तमान कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी बनारसी से भेंट के बाद यह ख़बर भी गश्त करने लगी कि सपा प्रमुख इस बार भी कुलपति एवं अन्य ज़िम्मेदारों से मिलने मदरसा पधार रहे हैं और इसके लिए मंत्री पद का दर्जा हासिल किए सहारनपुर के प्रसिद्ध व्यापारी एवं सपा वफादार आशु मलिक मदरसा के शिक्षक एवं जमीयतुल उलेमा हिंद के एक धड़े के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की सहायता से कोशिश कर रहे हैं.

प्रश्न यह भी है कि आख़िर इस असाधारण निर्देश का कारण क्या है और इसे जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ग़ौरतलब है कि इस निर्देश को जारी करने के चार दिन पहले 20 मार्च को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया दारुल उलूम देवबंद पहुंचे. दूसरे दिन यह ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मदरसे से समर्थन मांगा और वह उपकुलपति मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी से भी मिले.

इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस निर्देश का निशाना आप नेता के साथ-साथ सपा प्रमुख भी हैं. सपा के लिए एक मुसीबत और हो गई कि बीते 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अखिलेश सरकार को मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि अगर सरकार ने ला-परवाही न बरती होती, तो दंगे रोके जा सकते थे. उच्चतम न्यायालय ने इसी के साथ-साथ राजनीतिक संबंधों से हटकर कुसूरवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और प्रभावितों को सुरक्षा प्रदान करने की हिदायत दी. उसने राज्य सरकार को समय पर सावधान करने में असफल रहने पर केंद्रीय एवं राज्यस्तरीय खुफिया एजेंसियों की भी आलोचना की और निर्देश दिया कि जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए. राज्य के मुसलमान, जो मुजफ्फरनगर एवं उससे लगे हुए क्षेत्रों में भड़के दंगों, प्रभावितों की सहायता करने और उनके असल मुकाम पर पहुंचाने में असफल रही सपा से नाराज़ थे ही, अदालत के इस निर्णय से और भी ज़्यादा छिटक गए.

ऐसा प्रतीत होता है कि दारुल उलूम देवबंद के निर्देश एवं सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फ़ैसले से सबसे ज़्यादा प्रभावित सपा होने जा रही है, जिसका साफ़ मतलब यह है कि सपा उम्मीदवारों को मुस्लिम मत अधिकतर नहीं मिलेगा और यही हाल कमोबेश आम आदमी पार्टी का होगा, जिसके नेता मनीष सिसोदिया के मदरसे में जाने के बाद यह बवाल शुरू हुआ है. स्पष्ट है कि मुस्लिम मत इस स्थिति में अधिकतम कांग्रेस और उसके बाद बसपा को ही जाएगा. विभिन्न क्षेत्रों के मुस्लिम नेताओं एवं अन्य लोगों से हुई बातचीत और मौजूदा स्थिति बताती है कि राज्य में मुस्लिम मतों के मामले में इस बार कांग्रेस सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

तीसरे मोर्चे की सरकार की संभावना बहुत कम

सोलहवीं लोकसभा के चुनाव नतीजे क्या आएंगे, यह एक ऐसा प्रश्न है, जो इस समय हर शख्स के लिए दिलचस्पी का कारण बना हुआ है और इन्हीं नतीजों पर निर्भर होगा केंद्र में आगामी सरकार का प्रारूप. एक आम रुझान यह है कि इस बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है और इस स्थिति में आठवीं बार त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में आएगी. वह त्रिशंकु लोकसभा, जिसने 1989 के चुनाव के बाद सात बार से देश का पीछा नहीं छोड़ा है. ग़ौरतलब है कि 1989 में भारत में पहली बार किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में आई थी और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बाहर से भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार बनाई गई थी. 1991 में भी यही स्थिति रही और तब अल्पमत में रहने के बावजूद कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हाराव के नेतृत्व में सरकार बनाई. फिर 1996 में त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में आई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसी से समर्थन लेकर सरकार न बनाने के कारण दो साल के लिए संयुक्त मोर्चे की सरकार कायम हो गई. 1998 में भी त्रिशंकु लोकसभा का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा. तब वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के अंतर्गत गठबंधन सरकार बनी, मगर एक साल बाद हुए मध्यावधि चुनाव में भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वाजपेयी गठबंधन सरकार चलाते रहे. 2004 में भी त्रिशंकु लोकसभा देश पर सवार रही. तब डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्य पार्टियों के समर्थन से यूपीए के अंतर्गत सरकार बनाई.

अगर आम रुझान सच साबित होता है और 2014 के चुनाव में 8वीं बार त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में आती है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस बार गठबंधन सरकार कौन बनाएगा, कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए या भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए या वामपंथी पार्टियों के प्रभाव में कोई तीसरा मोर्चा? इस बात की भी संभावना है कि यूपीए एवं एनडीए, दोनों को अन्य पार्टियों से समर्थन तो लेना ही पड़ेगा और यह तभी संभव है, जब किसी तीसरे मोर्चे का अस्तित्व में आना संभव न हो. जहां तक किसी तीसरे मोर्चे की बात है, वर्तमान स्थिति में इसकी निर्भरता बड़ी हद तक चुनाव में वामपंथी पार्टियों के प्रदर्शन पर है.

अगर आम रुझान सच साबित होता है और 2014 के चुनाव में 8वीं बार त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में आती है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस बार गठबंधन सरकार कौन बनाएगा, कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए या भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए या वामपंथी पार्टियों के प्रभाव में कोई तीसरा मोर्चा? इस बात की भी संभावना है कि यूपीए एवं एनडीए, दोनों को अन्य पार्टियों से समर्थन तो लेना ही पड़ेगा और यह तभी संभव है, जब किसी तीसरे मोर्चे का अस्तित्व में आना संभव न हो.

इस सिलसिले में उचित यह होगा कि सर्वप्रथम 15वीं लोकसभा में वामपंथी पार्टियों की स्थिति देखी जाए. 15वीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल से कुल 42 सदस्यों में वाममोर्चा के 16 व्यक्ति थे, यानी माकपा के 9, भाकपा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के दो-दो एवं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया का एक. जबकि केरल से कुल 20 सदस्यों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के पांच व्यक्ति थे, जिनमें सीपीएम के चार और केरल कांग्रेस (एम) का एक.

जहां तक पश्चिमी बंगाल की बात है, वहां 2011 में हुए विधानसभा चुनावों में 1977 से काबिज वाममोर्चा के उखड़ने के बाद राज्य में उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है. इसलिए 2014 के संसदीय चुनाव में उसके सदस्यों की संख्या 16 से घटकर आधा दर्जन तक पहुंच सकती है. केरल में तो पिछली बार इसके मात्र पांच सदस्य ही निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे थे, जबकि 2004 में 14वीं लोकसभा में यह संख्या 13 थी. वैसे इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता कि केरल एवं केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस से आम मतदाता दूर हो चला है और इसका फायदा लेने के लिए वहां एलडीएफ आशावान है कि वह अपनी स्थिति बेहतर बनाएगा, मगर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि राज्य में कौन बाजी मारेगा, एलडीएफ या यूडीएफ? सिर्फ़ इतना कहा जा सकता है कि एलडीएफ केरल में अपनी सीटों में बढ़ोतरी अवश्य करेगा और शायद दस सीटों तक पहुंच जाएगा.

ऐसी अवस्था में यह सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि पश्चिम बंगाल में आधा दर्जन और केरल में अधिकतम दस सीटों के बल पर वामपंथी पार्टियां अन्य दलों के समर्थन से तीसरे मोर्चे को अस्तित्व में लाने में कामयाब हो पाएंगी? अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं त्रिपुरा से तो उम्मीद नहीं के बराबर है. ग़ौरतलब है कि पश्चिमी बंगाल में वाममोर्चा के उम्मीदवार सभी 42, त्रिपुरा में 2, अन्य राज्यों में 25, एलडीएफ के केरल में 15 समेत अन्य राज्यों में 88 सीटों पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जी-तोड़ परिश्रम के बावजूद वामपंथी पार्टियां इस स्थिति में नहीं आ पाएंगी कि वे किसी तीसरे मोर्चे को अस्तित्व में लाने में प्रभावी भूमिका अदा कर सकें. स्पष्ट है कि यह सारी स्थिति किसी तीसरे मोर्चे की संभावना को रद्द कर देती है. 2014 के चुनाव के बाद संभावित तीसरे मोर्चे की पार्टियों के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा कि वे यूपीए या एनडीए का रुख करें और केंद्र में किसी गठबंधन सरकार को कायम करने में मदद करें. ■

ए यू आसिफ

feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि रामविलास और रामकृपाल ऐसे नेताओं में हैं, जो किसी भी पार्टी में रहें, उनकी अपनी पहचान होती है. इस मामले में रामविलास टेस्टेड हैं और रामकृपाल का टेस्ट होना है. वह कहते हैं कि बिहार में पिछले कुछ सालों से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर यादव जाति के लोग भाजपा में मिल रहे हैं.

रंजन प्रसाद यादव

पाटलिपुत्र और पटना साहिब सीट

लड़ाई प्रो-मोदी और एंटी-मोदी वोटों के बीच

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि रीतलाल यादव को मनाने पहुंचे लालू यादव ने बिहार को फिर से जंगलराज की याद दिला दी. बहरहाल, रामकृपाल के लिए यह चुनौती है कि वह यादव वोट में किस हद तक सेंध लगा पाते हैं. भाजपा का कोर वोट भूमिहार-वैश्य उनके साथ दिख रहा है, लेकिन यहां भी एक समस्या आ खड़ी हुई है.

सरोज सिंह

बिहार की राजनीति की नब्ज पहचाननी हो, तो पटना में सत्ता के गलियारों में घूमना ज़रूरी है, लेकिन अभी तो इन गलियारों में पटना की दो वीआईपी सीटों यानी पाटलिपुत्र और पटना साहिब की ही चर्चा है. पाटिलीपुत्र में चाचा रामकृपाल यादव और भतीजी मीसा भारती के बीच महाभारत छिड़ा है, तो पटना साहिब में सबकी नज़र शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉगों पर लगी है. पहले इन दोनों सीटों की चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि यहां से लड़ेगा कौन और अब जब चेहरे साफ़ हो गए हैं, तो गरमागरम बहस यह हो रही है कि चाचा और भतीजी की इस जंग में आख़िरी वार कौन करेगा. इसी तरह पटना साहिब को लेकर यह चर्चा आम है कि क्या यह फिल्म स्टार अपना जादू फिर चला पाएगा या खामोश हो जाएगा.

पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो परिसीमन के बाद 2009 में यह सीट अस्तित्व में आई. पहली बार हुए चुनाव में यहां से एनडीए उम्मीदवार के रूप में जदयू के रंजन प्रसाद यादव के सामने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन पहले ही चुनाव में लालू को 23 हजार मतों से हारना पड़ा था. फिलहाल जो तीन प्रत्याशी मैदान में मुकाबले में दिख रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि राजद की ही है. मीसा भारती लालू की विरासत संभालने के लिए मैदान में आई हैं, तो रामकृपाल लालू के सबसे वफादार माने जाते रहे हैं, वहीं रंजन भी लालू के खासमखास रह चुके हैं. लालू ने ही उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया था. कहा जाता है, चूंकि रंजन फिलहाल यहां से सांसद हैं, इस वजह से उन्हें सत्ता विरोधी लहर का शिकार होना पड़ेगा. वहीं इस बार रंजन को भाजपा का साथ भी नहीं मिलेगा. रंजन के साथ सकारात्मक पक्ष यह है कि उनके साथ कुर्मी मतदाता रहेंगे. मालूम हो कि इस लोकसभा सीट के दो विधानसभा क्षेत्र फुलवारी और मसौढी में कुर्मी निर्णायक स्थिति में हैं, वहीं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कुर्मी मतदाताओं की संख्या ठीकठाक बताई जाती है. प्रेक्षकों की मानें तो रंजन कुछ न कुछ यादव वोट खींच सकते हैं, वहीं नीतीश के नाम पर अतिपिछड़ा और महादलित भी उन्हें वोट कर सकते हैं. रही बात भाजपा के रामकृपाल यादव की, तो मजबूत स्थिति में वह भी दिख रहे हैं. इस संसदीय क्षेत्र में रामकृपाल की पकड़ अच्छी मानी जाती है. इस क्षेत्र के कई मतदाताओं से बात होती है, जो रामकृपाल की सहजता एवं सुलभता को बताते हैं. रामदरशन पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं. बोरिंग रोड के एक अपार्टमेंट में गार्ड का काम करने वाले रामदरशन राजनीति में रमे रहते हैं.

रामदरशन कहते हैं, देखिए, रामकृपाल को कखनो खोजिएगा वो मिल जाएंगे, यादव उन्हीं को वोट करेगा. यह कहने पर कि मीसा खुद उम्मीदवार हैं और लालू जमकर उनका प्रचार कर रहे हैं, रामदरशन कहते हैं, लालू की बपौती नहीं हैं न यादव! यह भ्रम निकाल दीजिए. रामदरशन भले ही ज़्यादा पढ़े-लिखे न हों, लेकिन वह क्षेत्र की नब्ज पहचानते हुए मालूम पड़ते हैं. हाल के दिनों में लालू जिस तरह की व्यग्रता के साथ मीसा का प्रचार कर रहे हैं, यह दिखाता है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं यादव मतदाता ही न उनसे खिसक जाएं. इसका नमूना पिछले दिनों देखने को भी मिला. लालू अपने बेटे एवं बेटी मीसा के साथ रीतलाल यादव के घर पहुंचे. उनके पिता से आशीर्वाद लिया. बताते चलें कि रीतलाल अपराधी छवि के व्यक्ति हैं और फिलहाल जेल में हैं. लालू ने रीतलाल को रातोरात पार्टी का महासचिव बना दिया. लालू के इस क़दम की जमकर आलोचना भी हुई.

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि रीतलाल यादव को मनाने पहुंचे लालू यादव ने बिहार को फिर से जंगलराज की याद दिला दी. बहरहाल, रामकृपाल के लिए यह चुनौती है कि वह यादव वोट में किस हद तक सेंध लगा पाते हैं. भाजपा का कोर वोट भूमिहार-वैश्य उनके साथ दिख रहा है, लेकिन यहां भी एक समस्या आ खड़ी हुई है. बरमेश्वर मुखिया के पुत्र इंदुभूषण यहां से खड़े हैं. वहीं आम आदमी पार्टी ने यहां से कुंदन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. यही वजह है कि रामकृपाल के भूमिहार वोटों में सेंध लगने की गुंजाइश दिख रही है. लालू ने पिछले लोकसभा चुनाव में जिस माय समीकरण को साधने की कोशिश में यह सीट हाथ से गंवा दी थी, इस बार भी वह उसी समीकरण पर भरोसा कर रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि रामविलास और रामकृपाल ऐसे नेताओं में हैं, जो किसी भी पार्टी में रहें, उनकी अपनी पहचान होती है. इस मामले में रामविलास टेस्टेड हैं और रामकृपाल का टेस्ट होना है. वह कहते हैं कि बिहार में पिछले कुछ सालों से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर यादव जाति के लोग भाजपा में मिल रहे हैं. भाजपा ने तो 1993 में ही नंदकिशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, आज बीस वर्षों के बाद उसे इसका फ़ायदा मिलेगा. रीतलाल के मामले को लेकर सुमन कहते हैं, लालू को लगने लगा है कि यादव वोट उनसे छिटक रहा है. बिहार में तो माय समीकरण ही सिरियसली चैलेंज्ड है. इस संसदीय सीट के अंतर्गत छह विधानसभा क्षेत्र आते हैं, दानापुर, मनेर, पालीगंज, फुलवारीशरीफ, मसौढी एवं बिक्रम. दानापुर एवं मनेर यादव बहुल क्षेत्र हैं, जबकि पालीगंज एवं बिक्रम भूमिहार बहुल. वहीं फुलवारीशरीफ एवं मसौढी सुरक्षित क्षेत्र हैं. अब तक की स्थिति को देखते हुए पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं.

रही बात पटना साहिब की, तो यह राज्य की हाईप्रोफाइल सीट मानी जा रही है. फिलहाल यहां से भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं. इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारा है. जब तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई थी, बिहारी बाबू नाराज़ चल रहे थे, लेकिन उनके नाम की घोषणा के साथ ही उनका विरोध भी होने लगा है. पिछले दिनों नाम की घोषणा के बाद जब वह पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और जब नामांकन कराने गए थे, तब भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए. इस बात की आलोचना भी हुई थी कि विरोध कर रहे लोगों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा. कांग्रेस ने यहां से इस बार भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता कुणाल और जदयू ने शहर के चर्चित डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा को मैदान में उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ़ से जदयू से इस्तीफ़ा दे चुकी पूर्व मंत्री परवीन अमानुल्लाह मैदान में हैं.

कांग्रेस ने सबसे पहले पटना साहिब सीट के लिए राजकुमार राजन के नाम की घोषणा की थी. बाद में कुणाल को यहां से उम्मीदवार बनाया गया. इस बात को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध देखने को मिल रहा है. हालांकि बिहार कांग्रेस का कहना है कि राजन को मना लिया गया है. वहीं आप की उम्मीदवार परवीन का भी पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है. पिछले दिनों दिल्ली के विधायक मनीष सिसोदिया के आने पर उनका विरोध भी किया गया था. बहरहाल, बिहारी बाबू यहां से सांसद हैं, इस लिहाज से उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, वहीं क्षेत्र में सहज उपलब्ध न होना भी उनके विरोध का एक मुख्य कारण बना हुआ है. इस लोकसभा क्षेत्र में दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा एवं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं. इनमें से दीघा विधानसभा सीट पर जदयू का कब्जा है, वहीं फतुहा एवं बख्तियारपुर सीटें राजद के पास हैं. बांकीपुर, पटना साहिब एवं कुम्हरार सीटों पर भाजपा का कब्जा है.

नए परिसीमन के बाद शामिल हुए फतुहा एवं बख्तियारपुर यादव बहुल इलाके माने जाते हैं. इस लोकसभा क्षेत्र में कायस्थ वोटरों की संख्या भी अच्छी-खासी है. साथ ही यह शहरी मतदाता वाला क्षेत्र माना जाता है. इस लिहाज से भाजपा यहां मजबूत दिखाई पड़ती है. पिछले लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को यहां 3.17 लाख वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर रहे राजद के विजय कुमार को 1.50 लाख. शत्रुघ्न सिन्हा की राह इस बार आसान नहीं दिख रही है. वजह साफ़ है कि वह जनता के लिए सहज उपलब्ध नहीं हो पाते, साथ ही इस बार नीतीश का भी साथ उन्हें नहीं मिल रहा है. इसलिए उन्हें कुर्मी मतदाताओं के मत मिलना संभव होता नहीं दिख रहा है. जिन शहरी मतदाताओं पर भाजपा को भरोसा है, उनमें पिछले आठ सालों में जदयू ने भी सेंध लगाई है. बिहारी बाबू के लिए मुश्किल इसलिए भी है कि इस बार जदयू ने भी कायस्थ जाति के गोपाल सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है.

आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग चार लाख कायस्थ मतदाता हैं. अगर गोपाल सिन्हा कायस्थ मतों में सेंध लगा पाते हैं, तो यह बिहारी बाबू के लिए परेशानी खड़ी करने वाली बात होगी. इसकी संभावना इसलिए भी है कि सिन्हा कायस्थ संगठनों में लगातार सक्रिय भी रहे हैं. प्रेक्षकों की मानें, तो कांग्रेस उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय कर सकने की स्थिति में हैं. कुणाल राजद के आधार वोट के साथ बेदाग छवि वाले नेता हैं. आंकड़ों के लिहाज से इस संसदीय क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या 4.3 लाख है. कुणाल को भरोसा है कि उन्हें मंत्री एवं प्रभावी नेता रह चुके उनके पिता बुद्धदेव यादव की छवि का फ़ायदा मिलेगा. वहीं परवीन के मैदान में आ जाने से शत्रुघ्न के लिए और परेशानी खड़ी हो गई है. जानकारों का मानना है कि परवीन शहरी मतदाताओं को प्रभावित करेंगी और उससे भाजपा को नुकसान होगा. वह मुस्लिम मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकती हैं, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

दोनों सीटों के मद्देनज़र अब तक की गतिविधियों को देखें, तो लड़ाई प्रो-मोदी और एंटी-मोदी वोटों के बीच है. फिलहाल यह साफ़-साफ़ दिखता है कि एंटी-मोदी वोट दो हिस्सों राजद एवं जदयू में बंटता दिख रहा है और उसका फ़ायदा भाजपा को ही मिलेगा. वहीं दोनों सीटों पर राजद ने यादव-मुस्लिम समीकरण को ही साधने की कोशिश की है. जिस तरह से लालू यादव स्वजातीय वोटों को गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वैसे में यह आशंका जायज है कि ग़ैर यादव वोट पोलराइज हो सकता है.■

-साथ में **शशि सागर**

feedback@chauthiduniya.com

अरविंद केजरीवाल का मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी में फतेह हासिल करना ठीक वैसा होगा, जैसे आजकल चांद पर घर बसाने की बात की जा रही है. इसका एहसास अरविंद को पहले ही दिन हो गया होगा. वाराणसी में उनके ऊपर अंडे फेंके गए, स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए, विरोध में नारे लगे.

वाराणसी

मोदी के जाल में केजरीवाल

वाराणसी से चुनाव लड़ने का अरविंद केजरीवाल का फ़ैसला उनकी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. होना तो यह चाहिए था कि केजरीवाल स्वयं चुनाव मैदान में कूदने की बजाय अपने प्रत्याशियों को लड़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते.

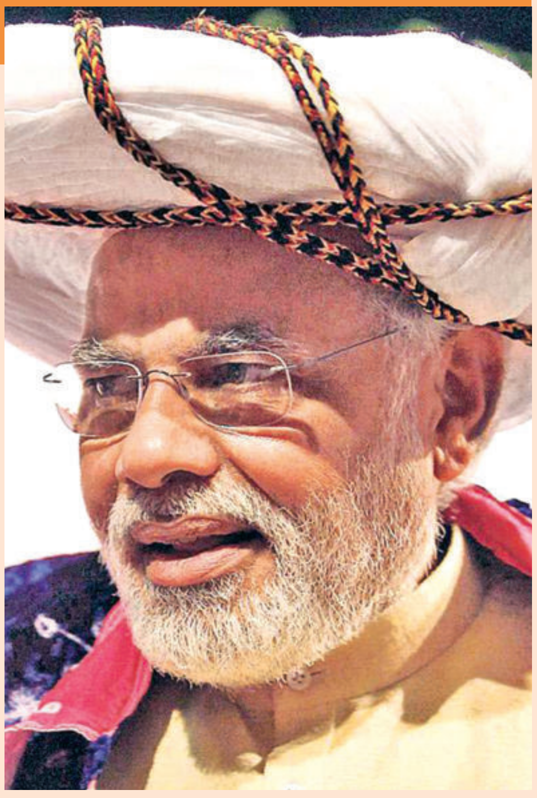

अजय कुमार

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज एवं अब आप के सेनानायक अरविंद केजरीवाल आम चुनाव की बिसात में किस खाने पर खड़े हैं, इसका पता लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही लगेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की महत्ता ठीक वैसे है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी, सपा के लिए मुलायम सिंह यादव, बसपा के लिए मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के लिए चौधरी अजित सिंह अथवा अन्य दलों के शीर्ष नेताओं की. ये सभी नेता अपनी-अपनी पार्टियों को सेनानायक की तरह आगे बढ़ा रहे हैं. इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है कि चुनावी मौसम में सभी दलों के सेनानायकों को हर समय यही चिंता सताती रहती है कि कैसे उनकी जीत सुनिश्चित हो, साथ ही पार्टी के अन्य प्रत्याशियों को भी जिताने के लिए वे एड़ी-चोटी का जोर लगा सकें, ताकि उनकी पार्टी की लोकसभा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ सके. लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह उचित भी लगता है.

अपने मिशन को पूरा करने के लिए तमाम दलों के रणनीतिकारों द्वारा रात-दिन बैठकें की जाती हैं, पार्टी हित से जुड़े मुद्दों को धार दी जाती है, तो वहीं विरोधियों के हमले कुंद करने के लिए नए-नए तीरों से तरकश सजाए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक संगठनों के आकाओं ने संगठन के साथ स्वयं का भी भला करने के लिए सेफ सीट तलाश करके पर्चा भरा है. प्रदेश की चुनावी जंग में पहली बार कूदे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए सेफ सीट समझी जाने वाली वाराणसी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ, कांग्रेस के अघोषित प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव मैनपुरी एवं आजमगढ़ और रालोद अध्यक्ष अजित सिंह बागपत से चुनाव मैदान में उतरे हैं. यहां इन नेताओं की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है, परंतु इससे अलग आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल होश की बजाय जोश से काम लेते हुए अनचाहे मन से ही सही, वाराणसी में मोदी के ख़िलाफ़ कूद पड़े हैं अथवा कहा जाए कि केजरीवाल भाजपा के जाल में फंस गए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.

मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी में फतेह हासिल करना ठीक वैसा होगा, जैसे आजकल चांद पर घर बसाने की बात की जा रही है. इसका एहसास अरविंद को पहले ही दिन हो गया होगा. वाराणसी में उनके ऊपर अंडे फेंके गए, स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए, विरोध में नारे लगे. कुछ लोगों ने तो चुटकी ली, जो बच न पाया खांसी से, वह क्या लड़ेगा काशी से. सवाल यह भी है कि जब वह स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं यहां जीतने नहीं आया हूं, प्रधानमंत्री बनने का मेरा कोई सपना नहीं है, तो फिर काशी की जनता उन्हें क्यों चुनेगी? अरविंद ने सवाल उठाया था कि मोदी दो जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसका जवाब तो सब जानते हैं, लेकिन केजरीवाल को इस बात का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था कि मोदी के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ोदरा की बजाय काशी को क्यों चुना?

केजरीवाल कहते हैं कि मोदी ने गुजरात को तबाह कर दिया. उनके अनुसार, गुजरात में मोदी की जीत की वजह विपक्ष का न होना है. ऐसे में केजरीवाल को बड़ोदरा से लड़ना चाहिए था, ताकि आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात में विपक्ष मजबूत हो सके. यहां तो मोदी और राहुल का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए सपा-बसपा जैसे दल मौजूद हैं ही, जिनके ख़िलाफ़ अरविंद कभी कुछ बोलते भी नहीं हैं. बहरहाल, वाराणसी से चुनाव लड़ने का अरविंद केजरीवाल का फ़ैसला उनकी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. होना तो यह चाहिए था कि केजरीवाल स्वयं चुनाव मैदान में कूदने की बजाय अपने प्रत्याशियों को लड़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते. एक-एक दिन की महत्ता केजरीवाल को समझनी होगी. वह आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते. केजरीवाल आम आदमी पार्टी का

चेहरा हैं, इसलिए उन्हें प्रयास करना चाहिए था कि पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी के संसदीय क्षेत्र में जाकर उसकी हौसला अफजाई करें, जो वह अभी तक नहीं कर पाए हैं.

कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने पहले आयकर विभाग की नौकरी छोड़ी, उसके बाद अन्ना हजारे के आंदोलन से किनारा किया और फिर दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसी तरह वह अपने प्रत्याशियों को भी मझधार में न छोड़ दें. ऐसा लगता है, अरविंद को न तो देश की चिंता है और न वह आम आदमी पार्टी की जीत-हार को लेकर गंभीर हैं, बल्कि उन्हें चिंता है, तो सिर्फ़ अपनी किस्मत चमकाने की. उनका शालीन व्यवहार, आम आदमी जैसा दिखने की हसरत और वीआईपी सुरक्षा न लेने का दावा, सब कुछ खोखला है. दरअसल, केजरीवाल के दो चेहरे हैं, पहला कैमरे के सामने वाला, दूसरा कमरे वाला. कैमरे के सामने केजरीवाल जनता के हीरो दिखते हैं, तो कमरे में वह तानाशाह हो जाते हैं. पार्टी के लिए जो मापदंड उन्होंने तय किए थे, उन्हें वह स्वयं तोड़ रहे हैं. दिल्ली सरकार बनाने-गिराने और लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में मनमानी को लेकर केजरीवाल की काफी फजीहत हो चुकी है. कई प्रत्याशियों ने तो टिकट ही वापस कर दिए. मनमानी की वजह से केजरीवाल के पुराने संगी-साथी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं. केजरीवाल आज विश्वसनीयता के हिसाब से कहीं नहीं टिकते.

हवा का रुख भांपकर पैतरा बदलने वाले अरविंद चाहते हैं कि जनता वैसा ही देखे, जैसा वह दिखाएं. मुद्दों एवं चर्चा के लिए उनके पास केवल मोदी, मुकेश, अदाणी और गुजरात बचे हैं. मोदी को घेरने के चक्कर में ही वह काशी तक पहुंच गए, जबकि मोदी को घेरने के लिए उन्हें पूरे देश में भ्रमण करने की ज़रूरत थी. आज मोदी कोई व्यक्ति मात्र नहीं रह गए हैं, वह मिशन बन गए हैं. मोदी मिशन को रोकने के लिए अरविंद को सभी 543 सीटों पर ध्यान देना चाहिए था. अगर वह काशी में मोदी को हरा भी देंगे, तो बड़ोदरा से तो मोदी निकल ही जाएंगे. वाराणसी में अरविंद की दस्तक को भाजपा के रणनीतिकार आम आदमी पार्टी की एक कमजोर कड़ी मानते हैं. वाराणसी को क़रीब से जानने वालों का कहना है कि दिल्ली और काशी की सियासत में जमीन-आसमान का अंतर है. यहां बीते डेढ़ दशक में भाजपा ने संगठन की बदौलत ही राजनीतिक धार को मजबूती दी है. जब स्वयं नरेंद्र मोदी मैदान में हों, तो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा होना स्वाभाविक है, जबकि आम आदमी पार्टी के अभी क़दम ही पड़े हैं.

वाराणसी की राजनीति पर क़रीब से पकड़ रखने वाले अतुल सक्सेना भाजपा एवं आप का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि काशी नगरी में भाजपा विशाल वटवृक्ष के समान है. उसकी 37 मंडलों में बंटी शहर व जिला इकाई हैं. उसके पास युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति-जनजाति किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक एवं मज़दूर महासंघ मोर्चा जैसे संगठन और एक हजार से अधिक पदाधिकारियों की लंबी-चौड़ी फौज एवं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं. 41 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं. बुनकरों, मज़दूरों, व्यापारियों, कामगारों एवं रेहड़ी वालों यानी सभी को लुभाया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अजय कुमार

सभी दलों को रास आ रहे बाहुबली

बात ज़्यादा पुरानी नहीं है. जब सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए एक अहम फ़ैसला दिया था, तब एक बार तो ऐसा लगा, मानों अब बहुत हुआ, भविष्य में राजनीति से अपराध की छाया मिट नहीं, तो सिमट ज़रूर जाएगी. तमाम दलों के बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तहेदिल से स्वागत किया, दो सांसदों लालू यादव और रशीद मसूद की सदस्यता भी चली गई, लेकिन हत्या, लूट, बलवा जैसे तमाम गंभीर आपराधिक मामलों से घिरे कई बाहुबली एक बार फिर लोकसभा चुनाव के समर में दस्तक देने की तैयारी में है. सिद्धांतों की बात करने वाले विभिन्न दल उन्हें अपने पाले में खींचने को बेताब हैं. सबकी नज़र सीटें बढ़ाने की जुगत पर है. वहीं कई बाहुबली ऐसे भी हैं, जो बड़े दलों से मौक़ा न मिलने पर क्षेत्रीय दलों के सहारे संसद में फिर दस्तक देना चाहते हैं.

डीपी यादव

धनंजय सिंह

अतीक अहमद

बृजभूषण शरण सिंह

मुख़्तार अंसारी

रमाकांत यादव

वाराणसी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो नेपाल की सीमा से सटे तराई की श्रावस्ती लोकसभा सीट से दो बाहुबली एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ताल ठोंकने को तैयार हैं. इलाहाबाद की फूलपुर सीट से संसद का सफर कर चुके बाहुबली अतीक अहमद बसपा राज में भागे-भागे घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही सपा राज आया, वह ताल ठोंकने लगे. सपा ने अतीक को अंततः श्रावस्ती से मैदान में उतार दिया. उधर, बलरामपुर से सांसद रहे रिजवान जहीर को गोंडा से बसपा का टिकट नहीं मिला, तो वह पाला बदल कर पीस पार्टी में चले गए और श्रावस्ती से अतीक के ख़िलाफ़ ताल ठोंकने लगे. सपा और बसपा में रह चुके रिजवान का नया ठिकाना पीस पार्टी है. राम मंदिर आंदोलन से सुर्खियां बटोरने वाले बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह आजकल अपने पुराने घर भाजपा में ताल ठोंक रहे हैं. सपा से होते हुए फिर भाजपा में आए बृजभूषण के लिए उनकी पुरानी पार्टी ने न तो दरवाजे खोलने में देरी की और न टिकट देने में संकोच किया. सपा का टिकट ठुकरा कर भाजपा में आए बृजभूषण को राजनाथ का विश्वास हासिल है. वह क्षत्रिय लॉबी को मजबूत करने के लिए बृज को भाजपा में लाए थे. बृजभूषण शरण सिंह माफिया होना अपनी शान समझते हैं और यहां तक कह चुके हैं कि मैं माफिया हूं, गांधी कैसे हो सकता हूं? मेरे ख़िलाफ़ चालीस केस दर्ज हैं. वह बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं. हत्या व लूटपाट जैसे तमाम गंभीर आरोपों में जेल यात्रा कर चुके और क्षमायाचना पर जेल से बाहर आए दबंग सपा नेता मित्रसेन यादव फैजाबाद लोकसभा सीट से अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं. वह सपा की साइकिल के सहारे संसद पहुंचना चाहते हैं. मित्रसेन यादव बसपा में भी रह चुके हैं.

कांटे से कांटा निकालने की तर्ज पर बसपा ने मित्रसेन के विरुद्ध कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी एवं पूर्व एमएलसी जितेंद्र सिंह उर्फ बब्लू को उतारा है. बब्लू पर आरोप है कि उन्होंने बसपा राज में अपने साथियों के साथ रीता बहुगुणा जोशी के लखनऊ आवास पर आगजनी और लूटपाट की थी. बब्लू ने मायावती के ख़िलाफ़ रीता के एक बयान से नाराज़ होकर तांडव किया था.पूर्वांचल की सियासत माफियाओं को खूब रास आती है. पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड सहित तमाम मामलों के आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी मऊ से, तो उनके भाई अफजाल अंसारी बलिया से ताल ठोंक रहे हैं. मुख्तार ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी से भी ताल ठोंकने का ऐलान कर रखा है. जेल से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे मुख्तार ने फिलहाल वाराणसी से अपनी बीवी अफशा अंसारी का नाम घोषित कर रखा है.

बाहुबली डीपी यादव, उनकी पत्नी, बसपा से निकाले गए धनंजय सिंह एवं लखनऊ के अरुण शुक्ला उर्फ अन्ना भी सफेदपोश होने की चाहत रखते हैं. मुख्तार से लेकर डीपी यादव तक कौमी एकता दल वाले गठबंधन के जरिये संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं. लंबे समय से जेल में बंद मुख्तार कई दलों का दामन थाम चुके हैं. पिछला चुनाव वह वाराणसी से बसपा के टिकट से लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए. बाद में मुख्तार को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. कहीं जुगाड़ न हो पाने के कारण मुख्तार ने अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर ली. वह कौमी एकता दल के संस्थापक बनकर स्वयं तो चुनाव लड़ते ही हैं, अन्य नेताओं को भी टिकट बांटते हैं. पूर्वांचल के बाहुबली मुन्ना बजरंगी जौनपुर से, तो बृजेश सिंह चंदौली से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं. बृजेश की पत्नी एवं बसपा एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह और भतीजा सुशील सिंह भी संसद की सीढ़िया चढ़ने को बेताब हैं. अन्नपूर्णा बसपा, तो सुशील भाजपा से टिकट की जुगत भिड़ा रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए. कहा जा रहा है कि ये तीनों ही लोकसभा चुनाव की जंग चंदौली से जीतने की क्षमता रखते हैं.

बसपा ने सुल्तानपुर से दबंग पवन पांडेय को मैदान में उतार कर भाजपा के वरुण गांधी को चुनौती का रास्ता प्रशस्त किया है. आजमगढ़ का दंगल भी काफी रोचक है. यहां से सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के मैदान में कूदने के बाद हालात काफी बदल गए हैं. यहां के मौजूदा बाहुबली सांसद रमाकांत को मुलायम के कारण दिन में तारे दिखने लगे हैं. दबंग छवि के रमाकांत यादव भाजपा के सांसद हैं. सपा और भाजपा से वह कई बार लोकसभा पहुंच चुके हैं. इस बार फिर वह अपने बाहुबल का एहसास कराने को तैयार हैं, लेकिन मुलायम से मुकाबला आसान नहीं लग रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

मिजोरम के मम्मित ज़िले से आए ब्रू जनजाति अल्पसंख्यक है. मिजो वन्य अधिकारी ललजाउमलियाना की हत्या के बाद ये लोग पलायन करने को मजबूर हुए थे. हालांकि इस घटना के पीछे भूमिगत ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट(बीएनएलएफ) का हाथ था. उस समय बीएनएलएफ पश्चिमी मिजोरम के ब्रू बहुल क्षेत्रों में एक स्वायत्त ज़िला परिषद के निर्माण के लिए और मिजोरम के अंदर एक विद्रोही आंदोलन की अगुवाई कर रहा था.

लोकसभा चुनाव 2014

क्या कश्मीरी अवाम मोदी को पसंद करने लगी हैं?

मोहम्मद हारून रेशी

लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त मोदी लहर चलाने के बाद भाजपा एक मात्र मुस्लिम राज्य यानी जम्मू-कश्मीर की जनता को रिझाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है. जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य, जहां कि मुस्लिम आबादी के बारे में आम राय है कि यह अपने इरादों पर अडिग रहती है. यहां पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के पक्ष में सूबे के एक वरिष्ठ नेता ने अप्रत्याशित बयान दिया. उसके बाद भाजपा के नेताओं ने कश्मीरी जनता के पक्ष में वादों की झड़ी लगानी शुरू कर दी. मोदी के हक़ में बयान देने वाले यह कश्मीरी नेता मीर वाइज़ उमर फ़ारूक़ हैं, जो न केवल पृथकता की मांग करने वाली पार्टियों के गठबंधन हुरियत कांफ्रेंस के एक हिस्से की अगुवाई कर रहे हैं, बल्कि एक सम्माजनक धार्मिक ज़िम्मेदारी भी संभाले हुए हैं. मीर वाइज़ ने इंडिया टुडे को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कांग्रेस के मुक़ाबले में मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार से अधिक उम्मीदें हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल यानी वर्ष 1998 से 2004 में कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण क़दम उठाए गए थे.

दिलचस्प बात यह है कि समस्त भारत में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भाजपा और ख़ासकर नरेंद्र मोदी से नाराज़ है. इसके उलट कश्मीर में उसे समर्थन मिलने की संभावना दिख रही है. यह इस बात का भी सबूत है कि कश्मीरी मुसलमानों और भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले मुसलमानों की विचाराधारा और विचारों में विरोधाभास है.

मीर वाइज़ के इस बयान के बाद भाजपा के कई नेताओं ने उनकी सराहना की. यही वजह है कि बीते दिनों पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कश्मीर समस्या को लेकर वाजपेयी की राह पर चलने का संकल्प लिया. मोदी ने जम्मू के सांबा ज़िले में विजय रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री बनने पर अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करेंगे. मोदी के अनुसार, वह कश्मीरी जनता में मौजूद बेचैनी को दूर करने के लिए मानवता और लोकतंत्र की राह पर चलना चाहते हैं. उनका कहना था कि अगर वाजपेयी पांच वर्ष और प्रधानमंत्री रहते, तो कश्मीर की स्थिति आज बिल्कुल अलग होती और तमाम समस्याएं हल हो गई होतीं.

हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि दरअसल मोदी मीर वाइज़ फ़ारूक़ के उस बयान की सराहना करना चाहते थे, जिसमें अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मोदी को बेहतर बताया था. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2002 में गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के कारण कश्मीर घाटी में अमूमन मोदी को नकारा जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक वरिष्ठ अलगाववादी नेता का यह बयान निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है. दरअसल, इस प्रकार भाजपा देश के मुसलमानों को यह संदेश दे सकती है कि एक ऐसा राज्य जहां के मुसलमान अटल इरादे रखते हैं, वहां भी अब यह आभास हो गया है कि मोदी ही बेहतर शासक साबित हो सकते हैं.

ऐसे समय में जब संसदीय चुनावों की सरगर्मियां चरम पर है, उस वक्त मीर वाइज़ को मोदी के पक्ष में इस प्रकार का बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चौथी दुनिया ने जब यह सवाल मीर वाइज़ से पूछा तो, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से यह एक निर्विवाद सच्चाई है कि वाजपेयी के शासनकाल में कश्मीर समस्या के हल की दिशा में कई असाधारण क़दम उठाये गए थे. मैं समझता हूं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वाजपेयी की राह पर चलते हैं, तो निश्चित ही कश्मीर समस्या के हल के लिए वह असाधारण क़दम उठा सकते हैं. उनके मुताबिक़, नरेंद्र मोदी समस्त भारत में एक बेहतर शासक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अगर वह कश्मीर समस्या शांतिपूर्ण तरीक़े से हल कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो वह एक स्टेट्समैन (राजममर्ज़) की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं.

हालांकि मुस्लिम विरोधी होने के आरोप और गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों का आरोप झेल रहे मोदी एक मुस्लिम बहुल राज्य की जनता के हित में ऐसा क्यों करेंगे? इस सवाल के जवाब में मीर वाइज़ ने चौथी दुनिया को बताया कि, ऐसा नहीं है कि शांति केवल हमें चाहिए. दरअसल, भारत जिस विकास की ओर अग्रसर है, उसे सबसे अधिक शांति की आवश्यकता है. इस देश में वार्षिक रक्षा बजट 37 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुका है, जबकि दूसरी ओर स्थिति यह है कि इस देश की बड़ी आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है. ऐसे में देश के किसी नेता को बदलाव की दिशा में आगे तो आना ही होगा और मेरे ख्याल से मोदी ऐसा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी छवि पर देश की जनता विश्वास करती है.

हालांकि आलोचकों का एक वर्ग इस बात से सहमत नहीं हैं कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले को हल करने के लिए साहस की आवश्यकता है और यह साहसी क़दम देश की एक ऐसी पार्टी ही उठा सकती है, जो विश्वास से भरी हो और जिसे इस बात का डर न हो कि उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा. कांग्रेस तो हर समय सहमी हुई रहती है. बीते वर्ष भाजपा ने कांग्रेस पर आतंकवाद के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाते हुए इतना दवाब बनाया कि कांग्रेस ने जेल से अफ़ज़ल गुरू को निकाल कर फांसी पर लटका दिया, सिर्फ़ यह साबित करने के लिए कि कांग्रेस आतंकवाद के प्रति नरमी नहीं रखती. इसके उलट भाजपा को स्वयं पर विश्वास है. ग़ौरतलब है कि एनडीए सरकार ने अपने शासनकाल में पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता आरंभ की और कश्मीर समस्या के हल के लिए कई महत्वपूर्ण क़दम उठाए थे. अगर यह सब कांग्रेस ने किया होता, तो यही भाजपा हंगामा खड़ा करती. ऐसी परिस्थितियों में मैं (मीर वाइज़ उमर फ़ारूख़) समझता हूं कि कश्मीरियों के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए से अच्छी भाजपा की सरकार अधिक बेहतर साबित हो सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि समस्त भारत में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भाजपा और ख़ासकर नरेंद्र मोदी से नाराज़ है. इसके उलट कश्मीर में उसे समर्थन मिलने की संभावना दिख रही है. यह इस बात का भी सबूत है कि कश्मीरी मुसलमानों और भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले मुसलमानों की विचाराधारा और विचारों में विरोधाभास है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिजोरम

ब्रू शरणार्थियों के लिए बेमानी है लोकतंत्र का यह महापर्व

एस. बिजेन सिंह

चुनाव में जनता के लिए मतदान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिन्हें मतदान से वंचित कर दिया जाए उनके लिए लोकतंत्र के महापर्व का क्या अर्थ रह जाता है? दरअसल, मिजोरम के ब्रू जनजाति पिछले पंद्रह वर्षों से अपनी पहचान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. ग़ौरतलब है कि वर्ष 1997 में एक मिजो वन अधिकारी की हत्या के बाद शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद ब्रू आदिवासी त्रिपुरा के कंचनपुर और पानिसागर के शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन काट रहे हैं. इस घटना के डेढ़ दशक बीत जाने के बाद भी ब्रू जनजाति अपने ही देश में परायेपन के शिकार हैं. ग़ौरतलब है कि सोलहवीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ब्रू आदिवासी शरणार्थियों को पोस्टल मतपत्रों के ज़रिए मत देने का अधिकार दिया जाएगा. हालांकि चुनाव आयोग के इस निर्णय पर मिजोरम के कुछ एनजीओ और युवा संगठनों ने विरोध किया है. इस बाबत उन्होंने रैलियां भी निकाली. इन रैलियों का नेतृत्व यंग मिजो एसोसिएशन (वाइएमए) ने किया.

इस बारे में यंग मिजो एसोसिएशन का कहना है कि, हमने अपना विरोध संदेश निर्वाचन आयोग के समक्ष भेजा है, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बाबत मिजो जिरलाई पॉल (एमजेडपी) के अध्यक्ष, पांच ग़ैर सरकारी संगठनों और युवा निकायों के समन्वय समिति के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर विरोध करने का ऐलान कर दिया है. इन संगठनों की मांग है कि राहत शिविरों में रह रहे सभी शरणार्थियों को लोकसभा चुनाव से पहले मिजोरम वापस भेजा जाए और जो नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए. एमजेडपी के मुताबिक़, ब्रू जनजाति शरणार्थियों ने अपनी मर्जी से वर्ष 1997 और 2009 में मिजोरम छोड़ा था. मिजोरम सरकार द्वारा चलाए गए कई प्रत्यावर्तन कार्यक्रमों के बावजूद भी इन शरणार्थियों ने बिना कोई उचित कारण बताए वापस जाने से इंकार कर दिया. ब्रू जनजाति शरणार्थियों की मानें, तो उस समय वे त्रिपुरा के शिविरों से घर लौटने के लिए मना कर दिया था, जब तक कि उनकी सुरक्षा की गारंटी न दी जाए. हालांकि मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथनहावला ने भी एक महीने पहले चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि सात राहत शिविरों में रहने वाले ब्रू जनजाति शरणार्थियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए. उन्होंने यह बात भी कही थी कि राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट के भाग्य का फ़ैसला पोस्टल वोटिंग के ज़रिए नहीं किया जाना चाहिए.

वहीं, दूसरी तरफ त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशुतोष जिंदल का कहना है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी उत्तरी त्रिपुरा में राहत शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा. उनके मुताबिक़, अप्रैल के पहले सप्ताह तक उत्तरी त्रिपुरा के सात शरणार्थी शिविरों में कम से कम एक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, ताकि यहां के लोग लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग के ज़रिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रू शरणार्थियों ने पहली बार डाक मतपत्र के ज़रिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. पिछले मिजोरम विधानसभा चुनाव में भी उन लोगों ने इसी तरीक़े से मतदान किया था. तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी मिजोरम यात्रा के दौरान यह कहा था कि वर्ष 2010 तक ब्रू शरणार्थियों के घर वापसी का अभियान पूरा कर लिया जाएगा.

वैसे इस संबंध में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि क्या ब्रू विस्थापितों के संगठन राहत शिविरों में मतदान कराने के पक्ष में हैं. हालांकि एमबीडीपीएफ ने चुनाव आयोग से यह शिकायत की थी कि कई योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है. दरअसल, 36000 से अधिक रियांग आदिवासी शरणार्थियों को स्थानीय भाषा में ब्रू कहते हैं. इनमें से 11,500 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था, लेकिन विधानसभा की 40 सीटों में से महज़ 10 निर्वाचन क्षेत्रों में ही इनका नाम शामिल है.

बहरहाल, मिजोरम के मम्मित ज़िले से आए ब्रू जनजाति अल्पसंख्यक है. मिजो वन्य अधिकारी ललजाउमलियाना की हत्या के बाद ये लोग पलायन करने को मजबूर हुए थे. हालांकि इस घटना के पीछे भूमिगत ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट(बीएनएलएफ) का हाथ था. उस समय बीएनएलएफ पश्चिमी मिजोरम के ब्रू बहुल क्षेत्रों में एक स्वायत्त ज़िला परिषद के निर्माण के लिए और मिजोरम के अंदर एक विद्रोही आंदोलन की अगुवाई कर रहा था. उत्तर त्रिपुरा के सब-डिविजन कंचनपुर में छह कैंपों में 35000 शरणार्थी हैं. इतना ही नहीं, ब्रू आदिवासी दक्षिणी असम में भी शरण लिए हुए हैं. राहत शिविरों में रहने वाले इन जनजातियों की हालत काफ़ी दयनीय है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है. इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन लोगों को न तो राजनीतिक अधिकार मिला है और न ही सामाजिक अधिकार. ऐसी सूरत में ब्रू जनजातियों के लिए लोकसभा चुनाव का कोई महत्व नहीं है. स्थानीय ब्रू जनजातियों के अनुसार, अपने ही देश में उन्हें पराया समझा जाता है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रू शरणार्थियों ने पहली बार डाक मतपत्र के ज़रिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. पिछले मिजोरम विधानसभा चुनाव में भी उन लोगों ने इसी तरीक़े से मतदान किया था. तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी मिजोरम यात्रा के दौरान यह कहा था कि वर्ष 2010 तक ब्रू शरणार्थियों के घर वापसी का अभियान पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि चिदंबरम साहब के उन वादों की कोई हकीकत नजर नहीं आ रही है और ब्रू जनजाति आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

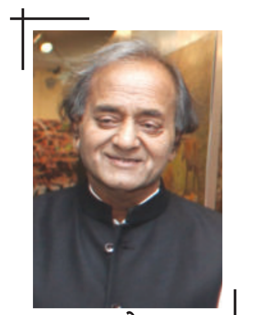

कमल मोरारका

हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार (नरेंद्र मोदी) कश्मीर में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए ख़तरा है. वह कहते हैं कि आज पाकिस्तान के पास तीन एके हैं, एके-47, एके एंटनी-देश के सबसे कमजोर रक्षा मंत्री और एके-49 यानी अरविंद केजरीवाल. यानी भाजपा इस देश में पाकिस्तान की तर्ज पर शासन करना चाहती है. भाजपा जनता के बहुमत से नहीं, बल्कि लोगों को पाकिस्तान का भय दिखाकर सत्ता हासिल करना चाहती है.

पाकिस्तान का भय दिखाकर वोट नहीं मिलने वाला

देश इलेक्शन मोड में पहुंच चुका है. चुनाव के वक्त नेता तरह-तरह के वक्तव्य देते हैं. तरह-तरह की बातें करते हैं, ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके, लेकिन इस सबके बीच कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं, जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता. ये बातें असामान्य हैं और जिनका देश के भविष्य पर अच्छा असर नहीं होने वाला. पाकिस्तान में आम तौर पर यह होता है कि जब वहां के शासक किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो वे अपनी अवाम को भारत का भय दिखाते हैं, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं और यह कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो भारत हम पर हमला कर देगा. भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही. लेकिन, आज जो हम देख रहे हैं, वह शुभ संकेत नहीं है.

हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार (नरेंद्र मोदी) कश्मीर में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए ख़तरा है. वह कहते हैं कि आज पाकिस्तान के पास तीन एके हैं, एके-47, एके एंटनी-देश के सबसे कमजोर रक्षा मंत्री और एके-49 यानी अरविंद केजरीवाल. यानी भाजपा इस देश में पाकिस्तान की तर्ज पर शासन करना चाहती है. भाजपा जनता के बहुमत से नहीं, बल्कि लोगों को पाकिस्तान का भय दिखाकर सत्ता हासिल करना चाहती है. मैं नहीं समझता कि भारत के लोग इतने मूर्ख हैं, जिन्हें इस तरह की बातों से बरगला कर वोट हासिल किया जा सकता है. पाकिस्तान भारत के लिए कोई ख़तरा नहीं है.

जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे इस देश की जनता के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं. विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर शासन और भ्रष्टाचार ख़त्म करने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भाजपा पाकिस्तान का भय दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है. थोड़ी देर के लिए चीन की बात होती, तो समझ में भी आती. हालांकि चीन भी हमारे लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है. ये लोग यह समझाने की कोशिश में है कि अमुक पार्टी सरकार में आ गई, तो देश का भविष्य ख़तरे में पड़ जाएगा. यह हास्यास्पद है. दूसरी तरफ़, हम अपने देश के अन्य संस्थानों को भी देख रहे हैं. उनके रुख को समझना मुश्किल होता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कई आदेश दिए हैं, जिनमें से एक है यूआईडी. पहले ही दिन से यूआईडी कार्ड का मामला ग़ैर-क़ानूनी रहा है. इसके लिए संसद ने कोई क़ानून नहीं बनाया है यानी संसद की इसमें कोई सहमति नहीं थी. यह एक कार्यकारी आदेश भर था. बंगलुरू के सज्जन को हजारों करोड़ रुपये दे दिए गए.

> सुप्रीम कोर्ट को एक क़दम और आगे जाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि सरकारी पैसे की रिकवरी कैसे की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट जैसे ग़ैर ज़रूरी मुद्दों पर अपना समय दे रहा है कि आईपीएल बंद होना चाहिए या कौन टीम खेलेगी या किसे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना चाहिए. क्या यह ठीक है? हमारे पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है और उससे भी खराब पीएम इन वेटिंग हमारे पास है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट है और कोई भी इसके काम में दखलअंदाजी नहीं कर सकता.

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस आधार कार्ड की कोई क़ानूनी अनिवार्यता नहीं है. अब इसके बाद, उन हजारों करोड़ रुपये के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, जो सरकार ने नंदन नीलेकणी को दिए थे? क्या प्रधानमंत्री इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी यह ज़िम्मेदारी लेगी? अब नीलेकणी बंगलुरू से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. सुप्रीम कोर्ट को एक क़दम और आगे जाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि सरकारी पैसे की रिकवरी कैसे की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट जैसे ग़ैर ज़रूरी मुद्दों पर अपना समय दे रहा है कि आईपीएल बंद होना चाहिए या कौन टीम खेलेगी या किसे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना चाहिए. क्या यह ठीक है? हमारे पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है और उससे भी खराब पीएम इन वेटिंग हमारे पास है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट है और कोई भी इसके काम में दखलअंदाजी नहीं कर सकता.

मैं सोचता हूं कि यह देश अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है. जितनी जल्दी चुनाव ख़त्म हो और एक नई सरकार बने, यही बेहतर होगा. मैं समझता हूं कि देश के वरिष्ठ राजनेताओं को पार्टी लाइन से हटकर एक साथ बैठना चाहिए और एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए, जिससे देश में एक अच्छा माहौल बन सके. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पहल करनी चाहिए और विभिन्न राजनीतिक दलों के चार-पांच वरिष्ठ राजनेताओं, जैसे आडवाणी जी, कांग्रेस एवं दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाना चाहिए और इस बात पर आम सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि यह देश अब कैसे चलेगा, चाहे चुनाव के नतीजे जो भी हों? मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि प्रधानमंत्री कौन होगा. हर पांच साल में प्रधानमंत्री आते और जाते रहते हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क अटूट रहना चाहिए. आज यही फ्रेमवर्क टूट रहा है. 2जी घोटाले में हमने देखा कि कैसे नियम-क़ानून को ताख पर रखा गया. आख़िर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? दूरसंचार मंत्रालय के सचिव आईएएस, आईपीएस या विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं. अगर ये लोग क़ानून का पालन नहीं करेंगे, तो देश का हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा. उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही इस सबसे बाहर निकलेंगे और जितनी जल्दी बाहर निकल सके, उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

हामिद शाह हाशमी

पानी का महत्व समझना होगा

आज विश्व में जल का संकट कोने-कोने में व्याप्त है. जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है. हम जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त हम यह भूल जाते हैं कि इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है. जब तक हम जल का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरह इतना ही दोहन करते रहेंगे. इंसान खाने के बगैर तो तीन-चार दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना तीन-चार दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता. तमाम प्राणियों के लिए जल आक्सीजन की हैसियत रखता है. पानी का इस्तेमाल इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भिन्न-भिन्न तरीकों से करता है, जैसे पीने, खाना पकाने और नहाने-धोने में. जल का महत्व वही लोग समझ सकते हैं, जो इसकी कमी से दो-चार हैं. पानी और प्राणियों का चोली-दामन का साथ है.

जम्मू-कश्मीर का जिला पुंछ सरहद पर होने की वजह से हमेशा सुर्ख़ियों में रहता है. यह जिला सीमावर्ती होने की वजह से आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. यहां शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, लेकिन जिले के कुछ इलाकों में पानी की समस्या भी विकराल रूप लिए हुए है. पुंछ की मेंढ़र तहसील से दस किलोमीटर की दूरी पर नाड़मनकोट नामक गांव है. हरे-भरे जंगल और आसमान से बातें करतीं पहाड़ियां इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. इस गांव में पानी की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. यह गांव दस वार्डों में बंटा हुआ है, लेकिन सिर्फ़ वार्डों में ही पानी के टैंक बने हुए हैं. जिन वार्डों में पानी के टैंक हैं, वहां के लोग भी पानी की कमी का रोना रोते रहते हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पानी केवल पहले टैंक तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि उसके आगे की पाइप लाइन खराब है, इसलिए दूसरे एवं तीसरे टैंक तक पानी पहुंचना संभव नहीं है. गांव निवासी रज़िया बी (30) कहती हैं, हम लोग हर रोज़ तक़रीबन आधा किलोमीटर पैदल चलकर चश्मों से पानी लेने जाते हैं और फिर सिर पर पानी के मटके उठाकर घर वापस आते हैं. पानी के मटके रखने की वजह से सिर में दर्द होने लगा है. वह कहती हैं, मैं हुकूमत से सवाल करती हूं कि यह नाइंसाफी हमारे साथ क्यों की जा रही है? क्या हमारे वोट की क़ीमत कम है? अफ़सोस की बात यह है कि 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में भी हमारे देश की महिलाओं को सिर पर पानी ढोकर लाना पड़ता है.

वार्ड नंबर पांच के पंच मोहम्मद सफीर कहते हैं कि इस इलाके की मस्जिद में भी पानी नहीं है. मस्जिद तक पानी पहुंचाने के लिए तक़रीबन 40 पाइपों की ज़रूरत है, लेकिन जब हम इस बारे में संबंधित जूनियर इंजीनियर से कहते हैं, तो वह आज-कल कहकर टाल देते हैं. हमने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के भी दरवाज़े खटखटाए, लेकिन हमारी आवाज़ पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. सफीर कहते हैं कि सरकार की उपेक्षा के चलते हमारा जन्नतनुमा इलाका कर्बला का मैदान बना हुआ है. फरज़ाना बी (14) कहती हैं, सर्दियों के दिनों में हमें एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही चश्मों का पानी सूख जाने से हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तब हमें दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है.

सिंचाई विभाग ने पानी की समस्या से निपटने के लिए जो सुझाव दिए थे, उन पर जिले में कोई अमल नहीं हो रहा है. फरवरी, मार्च, जून एवं जुलाई में इलाके में इतना पानी होता है कि वह दूसरे

इलाकों में सैलाब की स्थिति पैदा कर देता है. अगर सिंचाई विभाग वाटर शेड कायम करे और उस पानी को एकत्र कर लिया जाए तो उसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब इलाके में पानी की दिक्कत होती है. सरकार को ग्रामीण इलाकों के साथ- साथ सरहदी इलाकों की ओर भी जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है. ग्रामीण इलाकों में विकास के पहिए की गति बढ़ाए बिना हम शाइनिंग इंडिया-भारत निर्माण का सपना नहीं देख सकते, क्योंकि देश की तक़रीबन 70 प्रतिशत आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है. (चरखा) ■

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू-कश्मीर का जिला पुंछ सरहद पर होने की वजह से हमेशा सुर्ख़ियों में रहता है. यह जिला सीमावर्ती होने की वजह से आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. यहां शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, लेकिन जिले के कुछ इलाकों में पानी की समस्या भी विकराल रूप लिए हुए है. पुंछ की मेंढ़र तहसील से दस किलोमीटर की दूरी पर नाड़मनकोट नामक गांव है. हरे-भरे जंगल और आसमान से बातें करतीं पहाड़ियां इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. इस गांव में पानी की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.

पाठकों की दुनिया

मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल

मुसलमान केवल राजनीतिक दलों के लिए वोट बनकर रह गए हैं. कांग्रेस, सपा, बसपा एवं अन्य राजनीतिक दल चुनाव आते ही मुसलमानों के लिए बड़े-बड़े वादे करने लगते हैं और चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाते हैं. मुसलमानों को अगर अपना अधिकार चाहिए, तो उन्हें वोट की ताकत समझनी होगी. खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली सपा सरकार के राज में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जिसमें हजारों मुसलमान बेघर हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई- एसआईटी जांच से इंकार करते हुए दंगों के लिए राज्य सरकार को ही ज़िम्मेदार ठहराया और सपा को सुझाव भी दिया. देश के मुसलमान केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपेक्षा के शिकार हैं. वे अशिक्षा, बेरोज़गारी के कारण अपराध की ओर अग्रसर हैं. जब तक मुसलमान शिक्षा और वोट को अपना हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक उनके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है. इसलिए उन्हें विशेष तौर पर शिक्षा और वोट के महत्व को समझते हुए काम करना चाहिए.

-फिरोज खान, *वाराणसी, उत्तर प्रदेश).*

सुविधाओं से वंचित मुसलमान

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. यह देश का पहला ऐसा समाचारपत्र है, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाता है. 24-30 मार्च के अंक में प्रकाशित आलेख-राजनीतिक फोरम बहुत ज़रूरी हमें सचेत करता है. ए यू आसिफ ने सही कहा कि स्वाधीनता के बाद मुसलमान देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों, यहां तक कि भाजपा के भी हिस्सा रहे और निर्वाचित-मनोनीत होकर संसद के दोनों सदनों के अलावा राज्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में अपेक्षित संख्या, तुलना में कम सही, मगर पहुंचे. केंद्र-राज्य सरकारों में भी शामिल रहे और सरकार में मंत्री भी रहे. इसके बावजूद अभी भी मुसलमानों की स्थिति काफी खराब है. जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं. मुसलमानों को राजनीतिक छलावों से बचना होगा और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना होगा.

-असद आग़ा, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

युवाओं को करना है फ़ैसला

24-30 मार्च का अंक मिला. आलेख-एक चुनाव भारत के भविष्य के लिए-मेघनाद देसाई, काफी विचारोत्तेजक है. श्री देसाई ने सही कहा है कि इस बार मतदाता जो बहुमत देने वाला होगा, वह आज़ादी के बाद का ही होगा. सबसे बड़ी बात यह कि इस बार काफी युवा ऐसे हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे. सोलहवीं लोकसभा चुनाव अत्यधिक रोचक होगा. नए मतदाताओं के साथ-साथ आम आदमी पार्टी भी पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लेगी. पुराना भारत, विशेष रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में, जातीय राजनीति और वोट बैंक के मामले में सोचता है. युवा भारत की आकांक्षा हैं और वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं. इस लोकसभा चुनाव में जाति, सांप्रदयिकता और पुराने जो भी मुद्दे हैं, गौण नज़र आएंगे. जो युवाओं के बारे में बात करेगा, खासकर रोज़गार, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर, वही इस चुनाव में जीत हासिल करेगा.

-अंकुर श्रीवास्तव, *दरभंगा, बिहार.*

सोच बदलने की ज़रूरत

24-30 मार्च के अंक में प्रकाशित आलेख-जन्मशती के बहाने उठे सवाल, पढ़ा, अच्छा लगा. अनंत विजय ने अपने इस लेख में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र करते हुए लिखा है कि जातियों का सांस्कृतिक विनाश तब होता है, जब वे अपनी परंपराएं भूलकर दूसरी परंपराओं का अनुकरण करने लगती हैं. जब वे मन ही मन अपने को हीन और दूसरों को श्रेष्ठ मानकर मानसिक दासता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेती हैं. वास्तव में यही हमारी कमजोरी है कि हम अपने सामने जब ताकतवर या बड़ी जाति के लोगों को देखते हैं, तो खुद को उनके बराबर देखने या रखने में कतराने लगते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें इन बेड़ियों से बाहर निकलना होगा. हमें आगे बढ़ना होगा और इसके लिए अपनी मानसिकता बदलनी होगी.

-अभिनव सिंह, *पटना, बिहार.*

व्यक्ति आधारित चुनाव

महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म और उत्पीड़न की ख़बरें आएदिन समाचारपत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं. दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद ऐसी घटनाओं-ख़बरों की बाढ़-सी आ गई है. आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं. कितने भी कठोर क़ानून क्यों न बन जाएं, बिना मानसिकता बदले, ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आएगी. कारण यह है कि मनुष्य में भी एक जानवर बसता है, जो समय के साथ जागता है और अपना शिकार करता है. इसे आप विकृत मानसिकता कहें या कुछ और, कोई अंतर नहीं पड़ता. महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है. इस बार भी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे दब गए हैं. मीडिया हो या कोई और मंच, वहां चर्चा हो रही है, तो केवल व्यक्तियों की. इस बार का चुनाव मुद्दे की बजाय व्यक्ति आधारित हो गया है.

-रेखा यादव, *रांची, झारखंड.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

एम जे अकबर का भाजपा में जाना एक शुभ संकेत

आज मेरी श्री एम जे अकबर से मुलाकात हुई. एम जे अकबर अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने तात्कालिक प्रभाव से उन्हें अपना प्रवक्ता नियुक्त कर दिया. अकबर साहब पत्रकारिता के बड़े आदर्शों में रहे हैं और संभवतः उन कुछ जीवित आदर्शों में हैं, जिन्हें देखकर अंग्रेजी और कुछ हिंदी के पत्रकार भी अपना करियर वैसा ही बनाना चाहते हैं. मेरे मन में सवाल था कि आख़िर एम जे अकबर ने क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद किया. मैं जिन एम जे अकबर को जानता हूं, उनके सिखाए हुए रास्ते पर मेरे सहित चलने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुतों के मन में यह सवाल खड़ा हुआ कि एम जे अकबर क्या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ़ राज्यसभा में जाने के मोह में शामिल हुए, क्या वह मोदी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, क्या उनके मन की ये दोनों ख्वाहिशें दबी रह गईं, जिनमें से एक ख्वाहिश राजीव गांधी ने पूरी नहीं की और उसके बाद राजीव गांधी की जगह संभालने वाले नरसिम्हाराव और सोनिया गांधी ने एम जे अकबर जैसे व्यक्तित्व को बिल्कुल किनारे कर दिया. सवालों की श्रृंखलाएं कभी ख़त्म नहीं होतीं, लेकिन जब एम जे अकबर ने मुझे कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया, तो मेरे सामने इस सत्य को जानने का एक अवसर हाथ आ गया.

मैं एम जे अकबर से जब मिला और अकबर साहब के सवाल के जवाब में मैंने सवाल किया कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर आपको कैसा लग रहा है? एम जे अकबर ने अपने उसी अंदाज में, जिसमें वह हमेशा मिलते हैं, मुस्कराते हुए, बल्कि लगभग हंसते हुए बताया कि वह क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. दरअसल, हिंदुस्तान के मुसलमान परंपरागत रूप से अतिवादी हिंदू ताकतों के ख़िलाफ़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी अतिवादी हिंदू शक्तियों के प्रतीक बन चुके हैं. आज़ादी के बाद से कभी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया. आज़ादी के बाद जनसंघ बना. जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में शामिल हो गया और 78-79 में जब जनता पार्टी टूटी, तो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में सामने आया और तबसे अब तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा है. मान्यता या प्रत्यक्ष दर्शन के अनुसार, न तो भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मुसलमानों को लेना चाहती है और न मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं. भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कुछ मुस्लिम चेहरों को अपने यहां प्रमुखता दी, लेकिन वह सिर्फ़ इसलिए कि कोई भी उस पर सौ प्रतिशत हिंदूवादी होने का आरोप न लगा सके. सिकंदर बख्त, आरिफ बेग और अब शाहनवाज हुसैन और मुख़्तार अब्बास नकवी, ये नाम देश में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरे के रूप में प्रचलित रहे हैं. पहली बार एक ऐसा शख़्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, जिसका नाम एम जे अकबर है. एम जे अकबर भारतीय जनता पार्टी के कभी प्रशंसक नहीं रहे. उनकी दंगों की रिपोर्ट में हमेशा यह सत्य उद्घाटित हुआ कि दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ रहा है.

एम जे अकबर से बातचीत के बाद मुझे लगा कि उनके तेवर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है और वह इस बात पर बिल्कुल साफ़ हैं और मानते हैं कि उनके आने से मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला. वह यह भी मानते हैं कि मुसलमान उन पर हमले करेंगे, जिस तरह सोशल मीडिया में हमले हो रहे हैं. उन पर सार्वजनिक रूप से भी हमले हो सकते हैं, लेकिन एम जे अकबर इस बात के लिए तैयार हैं. मेरी बातचीत में मुझे यह लगा कि एम जे अकबर ने यह फ़ैसला इसलिए लिया, क्योंकि वह चाहते हैं कि मुसलमानों का संवाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सके. साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के असली सवालों के बारे में भी पता चल सके. यह विडंबना की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरों ने उसे मुसलमानों के असली सवालों से कभी रूबरू नहीं कराया. उन्होंने मुसलमानों की बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं कराई. वे जिस तरह की राजनीति चाहते हैं, वैसी बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से की और इस पूरी तस्वीर में एक नया किरदार सामने आया है, जिसका नाम एम जे अकबर है. एम जे अकबर इतिहास समझते हैं, एम जे अकबर मुसलमानों की समस्याओं को समझते हैं और एम जे अकबर मुसलमानों के दर्द को भी समझते हैं.

सारी बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पहली बार नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसा शख़्स गया है, जो भारत के मुसलमानों के इतिहास में दिखाए गए किरदारों को नरेंद्र मोदी को समझा सके और किस तरह उच्च वर्ग के लोगों की आपसी लड़ाई में सामान्य लोगों को शामिल कर लिया गया, यह भी बता सके. साथ ही मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी जीने की चाह रखते हैं, उनके अंतर्विरोधों को भी नरेंद्र मोदी को समझा सके. नरेंद्र मोदी एम जे अकबर पर बहुत भरोसा करते हैं. नरेंद्र मोदी शायद इसलिए एम जे अकबर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एम जे अकबर न तो कभी चापलूस हो पाएंगे, न किसी के प्रभाव में आकर उन्हें गलत जानकारी देंगे. इसके पीछे नरेंद्र मोदी और एम जे अकबर के बीच पिछले दस सालों के बीच हुई मुलाकातें हैं, जिनमें एम जे अकबर के रवैये ने, रुख ने और उनके विश्लेषण ने शायद नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया. अब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए किस तरह अपनी समझ विकसित करते हैं, यह सवाल है.

भारतीय जनता पार्टी के बाहर लोगों का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बारे में कोई अलग समझ नहीं बनाएंगे और उनके इस रुख का पता अमित शाह की बातों एवं व्यवहार से लगता है. अमित शाह का मानना है कि हम मुसलमानों को अलग ढंग से नहीं देखेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के ग़रीब तबके के रूप में देखेंगे और जो योजनाएं ग़रीबों के लिए बनाई जाएंगी, उन्हीं में मुसलमानों को हिस्सा मिलेगा. जबकि मुसलमान यह चाहता है कि उसके लिए वैसी ही विशेष योजनाएं बनें, जैसी दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए बनी हैं. अमित शाह इससे इंकार करते हैं. मेरा भी यह मानना है कि नरेंद्र मोदी इससे इंकार करेंगे, लेकिन अब एम जे अकबर के रूप में मुसलमानों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई है.

> **भारतीय जनता पार्टी के बाहर लोगों का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बारे में कोई अलग समझ नहीं बनाएंगे और उनके इस रुख का पता अमित शाह की बातों एवं व्यवहार से लगता है. अमित शाह का मानना है कि हम मुसलमानों को अलग ढंग से नहीं देखेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के ग़रीब तबके के रूप में देखेंगे और जो योजनाएं ग़रीबों के लिए बनाई जाएंगी, उन्हीं में मुसलमानों को हिस्सा मिलेगा. जबकि मुसलमान यह चाहता है कि उसके लिए वैसी ही विशेष योजनाएं बनें, जैसी दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए बनी हैं.**

भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर यह मानते हैं कि एम जे अकबर उनकी पार्टी में आकर अपनी उस समझदारी से अलग हट जाएंगे, जिसके लिए वह मशहूर हैं, तो मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है. सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को एम जे अकबर के रूप में एक सशक्त, समझदार व्यक्ति मिला है, जो न केवल मुसलमानों के सवालों को, बल्कि ग़ैर मुसलमानों के सवालों को भी बहुत अच्छी तरह समझता है. एम जे अकबर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में जो काम किया, वह उनके अपने लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने संडे, रविवार और टेलिग्राफ में जो काम किया, उसका जवाब कहीं है ही नहीं. हम जिस एम जे अकबर को जानते हैं, वह संडे, रविवार और टेलिग्राफ के एम जे अकबर हैं, जिनकी बेबाक लेखनी ने हिंदुस्तान में उसे नहीं बख़्शा, जो गुनहगार था. इसीलिए एम जे अकबर का भाजपा में जाना एक शुभ संकेत है.

एम जे अकबर को भारतीय जनता पार्टी में जाता देख सेक्युलर फोर्सेज परेशान हुई हैं, लेकिन देश को इससे एक फ़ायदा होने की संभावना है. कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भारतीय समाज के एक दबे-कुचले और लगभग दलितों की स्थिति में पहुंच गए मुस्लिम समुदाय को समझने में आसानी होगी. अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और एम जे अकबर उस सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के सवाल नरेंद्र मोदी के सामने बेबाकी और हिम्मत से रखने वाला एक शख़्स वहां पर है और वह कम से कम अब दंगों की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को दूर रखने में अपनी सारी ताकत लगा देगा. मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में एम जे अकबर का शामिल होना एक समझदार, बेबाक, बेख़ौफ इंसान का शामिल होना है और यह देश के हित में माना जाना चाहिए.■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

साठ के ही दशक के एक और चर्चित व्यक्ति थे, नेविल मैक्सेल, जिन्होंने हाल में सुर्ख़ियां बनाईं. उन्हें 1967 में की गई उनकी उस भयानक भविष्यवाणी के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह भारत का आख़िरी लोकतांत्रिक चुनाव होगा, लेकिन उसी समय यह भुला दिया जाता है कि उन्होंने भारत-चीन विवाद के बारे में क्या लिखा. उनका लिखा हुआ भारतीय पाठकों के लिए रुचिकर नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो लिखा, वह गलत था. अब हाल में उन्होंने 1962 के युद्ध के बारे में एक रिपोर्ट लीक की है, जिसमें शायद ही कोई नई जानकारी है.

भारत को विचार करना चाहिए

दो नामों ने बीते सप्ताह अतीत की याद दिला दी. पचास सालों से लगातार सांसद रहे टोनी बेन का निधन हो गया. वह एक अच्छे एवं दयालु व्यक्ति थे. 1960 के दशक के दौरान वह लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे और तकनीक प्रेमी व्यक्ति थे. उन्होंने देश में शांति के लिए काम किया. उन्होंने यूके का पोस्टल कोड बनाया, जो अंकों की बजाय अक्षरों से बना था. सत्तर के दशक में उनका झुकाव वामदलों की तरफ़ हो गया, जिसकी वजह से लेबर पार्टी में पर्याप्त बिखराव हो गया. इसका नतीजा यह हुआ कि अगले चार चुनावों तक हमें हार का सामना करना पड़ा. समाजवाद के लिए उनका आदर्शवाद उनके शिष्यों के लिए तो मधुर संगीत की तरह था, लेकिन यह वोटरों पर कोई असर नहीं छोड़ पा रहा था. यह टोनी ब्लेयर ही थे, जिन्होंने पुराने नियमों को छोड़ा, जिसकी वजह से लेबर पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ सकी.

यहां पर एक संदेश है कि आपके पुरजोर समर्थक आदर्शवादी होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी सलाहों पर काम करते रहे, तो आपको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा. जब आप हार जाते हैं, तब वे चाहते हैं कि विवादों को और जोर से उठाया जाए, जिससे जनता उनकी आवाज़ सुन सके. आप कह सकते हैं कि सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है या इस बात का वादा भी कर सकते हैं कि प्रत्येक मस्जिद की जगह मंदिर बनवा देंगे, लेकिन वोटर आपको इसके लिए अपना वोट नहीं देगा. जीतने के लिए वोटरों की वास्तविक समस्याओं को समझना होगा.

साठ के ही दशक के एक और चर्चित व्यक्ति थे, नेविल मैक्सेल, जिन्होंने हाल में सुर्ख़ियां बनाईं. उन्हें 1967 में की गई उनकी उस भयानक भविष्यवाणी के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह भारत का आख़िरी लोकतांत्रिक चुनाव होगा, लेकिन उसी समय यह भुला दिया जाता है कि उन्होंने भारत-चीन विवाद के बारे में क्या लिखा. उनका लिखा हुआ भारतीय पाठकों के लिए रुचिकर नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो लिखा, वह गलत था. अब हाल में उन्होंने 1962 के युद्ध के बारे में एक रिपोर्ट लीक की है, जिसमें शायद ही कोई नई जानकारी है. सभी को यह मालूम है कि नेहरू से गलत निर्णय हो गया था और उन्होंने सेना को यह आदेश दिए थे कि चीनी सेना को खदेड़ दिया जाए. जबकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है. सेना की सालों से अनदेखी का नतीजा सामने आ गया था. सिर्फ़ वीरता ही काफी नहीं होती है, बंदूकों में गोलियों की भी ज़रूरत होती है और ऐसे कपड़ों की भी, जो ठंड से हमारी रक्षा कर सकें.

भारत-चीन के बीच का सीमा विवाद भारतीयों के दिल तक जाता है. भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी सीमाओं का निर्धारण तब तक नहीं हो पाया, जब तक अंग्रेजों ने इस काम को पूरा नहीं किया. इसी कारण से भारत की सभी सीमा रेखाओं के नाम ब्रिटिश में ही हैं. भारत-अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, तिब्बत-भारत के बीच मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान-भारत के बीच रेडक्लिफ रेखा. चीनियों ने अंग्रेजों द्वारा खींची गई रेखा को नहीं माना और इस बात की उम्मीद की कि भारत भी आज़ाद होने के बाद उन रेखाओं को नहीं मानेगा. लेकिन, नेहरू अडिग रहे और नए आज़ाद भारत ने उन्हीं सीमाओं को माना, जिन्हें अंग्रेज बनाकर गए थे. चीन का ऐसा मानना है कि इन रेखाओं को थोपा गया था, इस वजह से ये रेखाएं साम्राज्यवादी हैं.

मुद्दे को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम है कि यह शांतिपूर्ण ढंग से हल हो पाएगा. देश अपनी सीमाओं को लेकर वैमनस्य रखते हैं. विशेष रूप से वे देश, जो गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं. वे अपनी सीमाओं में अपना स्वाभिमान देखते हैं. ऐसे देश, जिनमें कई भाषाएं एवं कई क्षेत्र हैं, सीमाएं उन्हें बांधने का काम करती हैं. जरा अपने राष्ट्रगान के बारे में विचार करिए, यह भी पूरे देश की भौगोलिक दृष्टि से व्याख्या करता है. ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने उस अध्याय से कोई सीख नहीं ली. हमारे गुटनिरपेक्ष सहयोगी हमें बचाने के लिए नहीं आए और न सोवियत रूस ही आया. जब समस्याएं बहुत बढ़ गईं, तो हमें अमेरिका के पास जाना पड़ा. हाल में जब रूस ने जनमत संग्रह के नाम पर क्रीमिया को मिला लिया, तो भारत उसे समर्थन देने का इच्छुक नज़र आया.

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर चीन भी अरुणाचल में जनमत के नाम पर ऐसा ही करे, तो भारत को इसके लिए सावधान रहना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि यह नहीं हो सकता. इसके लिए मैक्सवेल ने भारत-चीन सीमा के बारे में क्या लिखा है, उसे पढ़िए. इसके अलावा हाल में ए जी नूरानी ने क्या कहा है, उसे भी पढ़ना चाहिए. जब सीमाएं विवादित हों, तो यह बेहतर होता है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर मिला लीजिए और अपनी सीमाएं सुरक्षित कीजिए. अगर चीन पर्वतों को पार करते हुए भारत में घुस आए, तो रूस हमें बचाने के लिए नहीं आएगा. हाल में अमेरिका के साथ हुए विवाद के बाद तो इस बात पर और भी विचार किया जाना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

> ध्यान देने की बात यह है कि समाज में बेशक ऐसी सोच रखने वाला वर्ग ख़ुद की संख्या के आधार पर ताक़तवर नहीं हो, लेकिन वह ओपीनियन मेकर के तौर पर समाज के बड़े तबके को प्रभावित करने और सामाजिक एजेंडा तय करने की हैसियत ज़रूर रखता है. आम चुनावों में देश की राजधानी के चुनाव नतीजे संख्या के नज़रिए से बड़ा असर भले ही न डाल पाएं, लेकिन उनका अपना राजनीतिक महत्व ज़रूर रहेगा.

उमेश चतुर्वेदी

लोकसभा चुनाव 2014

दिल्ली और एनसीआर में किस करवट बैठेगा ऊंट

पिछले साल चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे. सियासी जानकारों को उम्मीद तो यही थी कि इन चारों राज्यों में भगवा ध्वज अपने पूरे उफान के साथ फहराएगा, लेकिन चार दिसंबर को आए नतीजों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो वह दिल्ली के ही नतीजे थे. सिर्फ़ एक साल पुरानी आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी की 28 सीटों पर क़ब्ज़ा कर लिया. वहीं दिल्ली में भगवाध्वज फहराने की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे ध्वस्त हो गए. तब से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आम चुनावों में आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी में बड़ी बढ़त हासिल हो सकेगी, लेकिन 14 जनवरी, 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल के इस्तीफ़े ने केजरीवाल से दबे–छुपे ही सही उम्मीद लगा बैठे समाज के उस वर्ग को भी झटका लगा, जिसने केजरीवाल को सिर्फ़ व्यक्ति नहीं, राजनीति की दुनिया में आए भाई–भतीजावाद, धार्मिक संतुष्टिकरण और भ्रष्टाचार में बदलाव की प्रवृत्ति के तौर पर देखा था.

ध्यान देने की बात यह है कि समाज में बेशक ऐसी सोच रखने वाला वर्ग ख़ुद की संख्या के आधार पर ताक़तवर नहीं हो, लेकिन वह ओपीनियन मेकर के तौर पर समाज के बड़े तबके को प्रभावित करने और सामाजिक एजेंडा तय करने की हैसियत ज़रूर रखता है. आम चुनावों में देश की राजधानी के चुनाव नतीजे संख्या के नज़रिए से बड़ा असर भले ही न डाल पाएं, लेकिन उनका अपना राजनीतिक महत्व ज़रूर रहेगा. इसीलिए इन पर सियासी पंडितों की नज़र कुछ ज़्यादा ही है. दिल्ली में सात लोकसभा सीटें हैं और इनका क्रमवार विवेचन ज़रूरी है. दिल्ली की सबसे संभ्रांत मानी जाती है दक्षिण दिल्ली सीट. इस सीट पर क़रीब साढ़े पंद्रह लाख मतदाता हैं. पिछले चुनाव में यहां से सिख दंगों के आरोपी रहे दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार के छोटे भाई रमेश कुमार यहां से सांसद हैं. रमेश कुमार एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने दिल्ली प्रदेश के महासचिव और तेज़तर्रार विधायक रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने देवेंद्र सहरावत को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस क्षेत्र में दिल्ली का सबसे पॉश महानगरीय इलाक़ा के साथ ही गांवों का भी इलाक़ा आता है, जिसमें जाट और गुर्जर मतदाताओं की अच्छी–ख़ासी तादाद है. तुगलक़ाबाद से विधायक रमेश बिधूड़ी गुर्जर समुदाय से आते हैं. ज़ाहिर है कि दिल्ली के गांवों में उन्हें इस समुदाय का साथ मिलेगा. इस विधानसभा की दस में से सात सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का क़ब्ज़ा है, जबकि तीनों सुरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी का क़ब्ज़ा है. अगर ज़्यादा समीकरण नहीं गड़बड़ाए, तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में जा सकती है.

दिल्ली की दूसरी सीट पश्चिमी दिल्ली है. कभी बाहरी दिल्ली के तौर पर मशहूर रही इस सीट का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते दिख रहा है. यहां क़रीब 17 लाख वोटर हैं. यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और जाट समुदाय के कद्दावर नेता साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है. प्रवेश फ़िलहाल दक्षिण दिल्ली की महरौली सीट से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं. पश्चिमी दिल्ली की दस सीटों में से पांच पर भारतीय जनता पार्टी का क़ब्ज़ा है. वहीं उसकी सहयोगी अकाली दल के पास एक सीट है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास चार सीटें है. पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी ने दैनिक जागरण के पत्रकार रहे जनरैल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. जरनैल सिंह को दैनिक जागरण ने चिदंबरम पर जूता चलाने के बाद हटा दिया था, जबकि कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा पर ही दांव लगाया है. अगर विधानसभा चुनाव नतीजों को देखें, तो इसी तरह उत्तर पश्चिमी दिल्ली का भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है. यहां से दलित चिंतक और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए उदित राज को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कृष्णा तीरथ को मैदान में उतारा है. कृष्णा यहां की मौजूदा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

इसी तरह आम आदमी पार्टी ने राखी बिड़लान को अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि इस सीट से महेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन महेंद्र सिंह ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहीं राखी बिड़लान पर उन्हें सहयोग नहीं करने के सवाल पर टिकट लौटा दिया था.

यहां क़रीब 18 लाख वोटर हैं. पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों का समीकरण भी एक लिहाज़ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है. फ़िलहाल भाजपा के पास दस में से पांच सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को तीन और कांग्रेस को दो सीटें मिली हैं. दिल्ली की उत्तर–पूर्वी सीट पर भी दिलचस्प मुक़ाबला होना तय है. यहां की दस सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास पांच, आम आदमी पार्टी के पास तीन और कांग्रेस के पास दो सीटें हैं. इसी इलाक़े में किराड़ी विधानसभा सीट भी आती है, जहां से बीजेपी के अनिल झा ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा 49 हज़ार मतों के अंतर से जीत हासिल की है. यहां प्रवासी बिहारी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मशहूर भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद जयप्रकाश अग्रवाल पर विश्वास जताया है. वहीं आम आदमी पार्टी ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्राध्यापक प्रो. आनंद कुमार पर दांव खेला है. समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़े प्रो. आनंद कुमार भी भोजपुरीभाषी है, लेकिन वह मतदाताओं पर कितना असर डाल पाएंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा.

कांग्रेस ने क़रीब 16 लाख वोटरों वाली पूर्वी दिल्ली सीट पर मौजूदा सांसद संदीप दीक्षित, तो भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवार महेश गिरी पर दांव आजमाया है. वहीं आम आदमी पार्टी ने गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी को मैदान में उतारा है. हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों का गणित आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहा है. जहां की दस में से पांच सीटों पर आम आदमी पार्टी का क़ब्ज़ा है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास तीन और कांग्रेस के पास दो सीटें हैं. भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरी सीट नई दिल्ली मानी जा रही है. भाजपा ने यहां से सुप्रीम कोर्ट में वकील और पार्टी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को मैदान उतारा है. कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने खोजी पत्रकार आशीष खेतान को अपना उम्मीदवार बनाया है. क़रीब पौने चौदह लाख वोटरों वाली इस लोकसभा सीट की दस विधानसभा क्षेत्रों में से सात सीटों पर आम आदमी पार्टी का क़ब्ज़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज़ तीन सीटों से ही संतोष करना पड़ा था. कांग्रेस को अजय माकन की साफ़ छवि का भरोसा है, तो आम आदमी पार्टी को अपने पुराने करिश्मे का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष खेतान को यहां का वोटर जानता तक नहीं है. ग़ौरतलब है कि शाजिया इल्मी यहां से उम्मीदवार बनना चाहती थीं. हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया. ध्यान देने योग्य यह है कि इसी इलाक़े की सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सीट भी आती है, जहां से फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल विधायक हैं.

लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सबसे हाईप्रोफाइल सीट चांदनी चौक बन गई है. जहां से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्षवर्धन, आम आदमी पार्टी से पूर्व पत्रकार आशुतोष और कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल मैदान में हैं. क़रीब साढ़े चौदह लाख वोटरों वाली इस लोकसभा सीट की दस विधानसभा क्षेत्रों में से आम आदमी पार्टी के पास चार, भारतीय जनता पार्टी के पास तीन, कांग्रेस के पास दो और जनता दल यूनाइटेड के पास एक सीट है. आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वह यहां से करिश्मा दिखा सकती है. वहीं हर्षवर्धन के सहारे बीजेपी भी जीत की उम्मीद पाले बैठी है. कपिल सिब्बल भी ख़ुद को यहां से दोहराने की कोशिश में हैं, लेकिन जिस तरह यहां की गलियों में आशुतोष का विरोध हुआ, उससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के लिए यहां से राह आसान नहीं है.

> दिल्ली की दूसरी सीट पश्चिमी दिल्ली है. कभी बाहरी दिल्ली के तौर पर मशहूर रही इस सीट का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते दिख रहा है. यहां क़रीब 17 लाख वोटर हैं. यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और जाट समुदाय के कद्दावर नेता साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है. प्रवेश फ़िलहाल दक्षिण दिल्ली की महरौली सीट से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं. पश्चिमी दिल्ली की दस सीटों में से पांच पर भारतीय जनता पार्टी का क़ब्ज़ा है. वहीं उसकी सहयोगी अकाली दल के पास एक सीट है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास चार सीटें है. पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी ने दैनिक जागरण के पत्रकार रहे जनरैल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. जरनैल सिंह को दैनिक जागरण ने चिदंबरम पर जूता चलाने के बाद हटा दिया था, जबकि कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा पर ही दांव लगाया है.

दिल्ली में यूं तो गुड़गांव और गाज़ियाबाद की सीटें नहीं आती हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी से नज़दीक होने और हाईप्रोफाइल उम्मीदवारों के चलते ये दोनों सीटें भी महत्वपूर्ण हो गई हैं. गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव और बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने राव धर्मपाल को मैदान में उतारा है. गुड़गांव–रेवाड़ी नाम वाली यह सीट यादव बहुल मानी जाती है और तीनों ही पार्टियों ने इसी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने जाक़िर हुसैन को उम्मीदवार बनाकर करीब 18 लाख वोटरों वाली इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं के सहारे मैदान में है. शहरी बहुल सीट और आम आदमी पार्टी का चेहरा माने जाने वाले योगेंद्र यादव के चलते यहां मुक़ाबला दिलचस्प हो गया है. हालांकि अब तक माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत के पक्ष में ही पलड़ा भारी है.

गाज़ियाबाद के क़रीब साढ़े तेइस लाख वोटरों पर भी लोगों की निगाह है. यहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, कांग्रेस ने सिने अभिनेता राजबब्बर, आम आदमी पार्टी ने पूर्व पत्रकार शाजिया इल्मी, समाजवादी पार्टी ने सुधन रावत और बहुजन समाज पार्टी ने मुकुल उपाध्याय को मैदान में उतारा है. वैसे गाज़ियाबाद आम आदमी पार्टी की जन्मभूमि माना जाता है. पार्टी के तीनों प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और कुमार विश्वास यहीं के बाशिंदे हैं. पार्टी गठन से लेकर दिल्ली में सरकार बनाने व चलाने की तमाम रणनीतियां गाज़ियाबाद में ही बनीं. यहां आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की जन्मभूमि पर असर दिखाने की है. फ़िलहाल यहां की पांच विधानसभा सीटों में से चार पर बहुजन समाज पार्टी का क़ब्ज़ा है. हालांकि इस बार मुख्य मुक़ाबला भाजपा उम्मीदवार जनरल वीके सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर के बीच माना जा रहा है. इसकी बड़ी वजह है इन दोनों का अपना कद और व्यक्तित्व.

बहरहाल, चुनाव नतीजों का ठीक–ठीक आकलन कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन यह तय है कि स्थानीय मुद्दों की बजाय इस बार दिल्ली समेत उसकी आस–पास की सभी सीटों पर राष्ट्रीय मुद्दे ही असर डालेंगे और इसकी बड़ी वजह इनका शहरी क्षेत्र होना है. वैसे एक बात तय मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो उत्साह दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान देखा गया था, उसमें कमी तो नज़र आ ही रही है. ■

uchaturvedi@gmail.com

अगर हम यूक्रेन पर भारत के रुख़ की बात करें, तो पाएंगे कि भारत ने एक प्रकार से रूस का समर्थन ही किया है. तभी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि चीन और भारत ने यूक्रेन संकट के बारे में संयत और सही रवैया अपना कर रूस को राहत प्रदान की है. आज विश्व बहुत तेजी से एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय राष्ट्र की तरफ़ बढ़ रहा है. ऐसे में भारत को भी कूटनीति का परिचय देते हुए इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि वह इन राष्ट्रों की ख़ेमेबंदी में पीछे न रह जाए.

रूस का क्रीमिया पर अधिकार

शीत युद्ध के आसार

रूसी संसद के मंच पर रूस के साथ क्रीमिया की विलय संधि पर जब हस्ताक्षर हो रहे थे, तो उस समय अमेरिका और पश्चिमी देश बेचारे बने सब कुछ होता देख रहे थे. अंतत: रूस ने अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना क्रीमिया का विलय कर ही लिया. यह एक युगांतकारी घटना थी, जो आने वाले दिनों में विश्व के देशों को नए शीत युद्ध के अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाएगी. संभावना इसकी भी है कि इस घटना के बाद दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ़ अग्रसर होगी. इस घटना का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद हाशिये पर चला गया रूस अब मुख्य धारा में आकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए नई चुनौती बन गया है.

राजीव रंजन

रूस द्वारा क्रीमिया के विलय की कार्रवाई की दुनिया भर में निंदा हो रही है. अमेरिका ने भी रूस की इस कार्रवाई का कड़ा प्रतिरोध शुरू कर दिया है. इस मुद्दे पर रूस की उग्रता और विरोधी देशों की तनातनी के कारण विश्व जिस तरह से सुलग रहा है, उससे शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है. आने वाला समय इन देशों के बीच अशांति और अस्थिरता का दौर लेकर आएगा, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता. हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से विश्व किसी भी देश के मुद्दे पर दो फाड़ होने जा रहा है. कभी अफगानिस्तान, तो कभी इराक, तो कभी अन्य किसी देश के लिए विश्व के देश गुटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

सबसे बड़ी बात है कि यह गुटबाजी किसी देश की हित रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस देश से अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए होती है. यह विश्व के किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है. दूसरी बात यह है कि अगर वैश्विक देशों का यही रवैया रहा, तो आने वाला समय पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक हो सकता है और तीसरे विश्व युद्ध से कतई इंकार नहीं किया जा सकता. ऐसा नहीं कि क्रीमिया संकट पहली बार विश्व के सामने आया है. पश्चिमी देशों की तनातनी रूस के साथ पहले भी हो चुकी है. 160 साल पहले 25 मार्च, 1854 को विश्व के प्रमुख अख़बार द इकोनॉमिस्ट ने जब रूस के साथ पश्चिमी देशों की तनातनी की ख़बर प्रकाशित की थी, तो उसके मात्र 3 दिनों बाद ही ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी थी. तो क्या आज के हालात फिर से विश्व युद्ध की तरफ़ इशारा कर रहे हैं? हालांकि आज की तारीख में युद्ध इतना आसान नहीं है, लेकिन रूस के जिद्दी स्वभाव के कारण इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है.

क्रीमिया पर रूस के कब्जे से पूरे विश्व का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ताना-बाना बिखर गया है. हालात ये हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्रीमिया को रूस में मिलाए जाने के मुद्दे पर मास्को के ख़िलाफ़ पश्चिमी देशों की एकजुटता का आह्वान किया है. ओबामा जब हेग गए, तो वहां उन्होंने जी-7 देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें इस बारे में चर्चा की गई कि शीत युद्ध के बाद से पूर्व-पश्चिम के इस सबसे बड़े गतिरोध के हल के लिए क्या क़दम उठाए जाएं? रूस को लेकर इन देशों में इतनी नाराज़गी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एवं शीर्ष आर्थिक शक्तियों ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के ख़िलाफ़ दबाव बनाने के लिए जून में सोची में प्रस्तावित जी-8 शिखर बैठक के स्थान पर ब्रसेल्स में जी-7 की शिखर बैठक बुलाए जाने की बात कही और उसमें रूस को शामिल न करने पर भी विचार किया गया. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इस फ़ैसले पर मुहर लगाई. जी-7 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि जब तक रूस अपने रवैये में बदलाव नहीं करता है, तब तक हम जी-8 शिखर बैठक में भाग नहीं लेंगे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जून 2014 में सोची के बजाय ब्रसेल्स में जी-7 देशों की बैठक होगी. कुछ देश पहले से ही रूस को संगठन से बाहर करने की राय दे रहे थे, लेकिन जर्मनी जैसे देशों का कहना है कि रूस अब भी संगठन का सदस्य है. हालांकि यह कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्विक देशों द्वारा वार्ता के मंच को कभी ध्वस्त नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा होता है, तो संघर्षरत देशों से वार्ता की रही-सही गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी और बेवजह की तनातनी बढ़ेगी.

सवाल यह कि ये देश रूस पर किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं? अगर ये देश रूस पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि इनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का अंजाम क्या होगा? क्या ये रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे या किसी अन्य तरह का प्रतिबंध. जिस अंदाज में पश्चिमी देशों ने रूस को सतर्क किया है कि वह आगे कोई कार्रवाई न करे, क्योंकि उसके अंजाम खराब हो सकते हैं. ऐसे में चिंता इस बात की भी है कि अगर विश्व के देशों के बीच तनातनी बढ़ती है, तो वह किस हद तक जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या रूस पर कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता बचा है? रूस या अन्य देश आपस में मिलकर क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? क्रीमिया के मुद्दे पर रूस लगातार उग्र रुख अख्तियार किए हुए है. अगर रूस चाहता, तो आज जो हालात हैं, वे नहीं होते, क्योंकि विश्व के देशों द्वारा लगातार चेतावनी देने के बाद भी रूस ने उनकी बात पूरी तरह से अनसुनी कर दी. क्या रूस कुछ मुद्दों पर शांति से काम नहीं ले सकता? हालांकि, रूस कह रहा है कि वह पश्चिमी देशों के साथ लगातार संपर्क में बना रहना चाहता है, लेकिन रूस की नीतियां उसकी कथनी और करनी में फर्क बता रही हैं.

क्रीमिया के मुद्दे पर दुनिया के औद्योगिक देशों और रूस के बीच तनातनी के कारण जी-8 का अस्तित्व ख़त्म हो गया है. इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरी मार पड़ने वाली है. जापान के शेयर जिस तेजी से लुढ़क रहे हैं, यह उसका ताजा उदाहरण है. इसके अतिरिक्त अमेरिका का डाउ जोन्स भी नीचे गिरकर बंद हुआ था. विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के राजनीतिक संकट का प्रभाव पूरे विश्व पर और अधिक देखने को मिलेगा. इस बीच यूरोप की साझा मुद्रा यूरो पर भी एशियाई बाज़ारों में विपरीत असर पड़ रहा है. यूरो का मूल्य कमजोर पड़ रहा है. भारतीय रुपया भी यूरो के मुकाबले थोड़ा चढ़ा है, हालांकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होकर 60.4 फ़ीसद तक पहुंच गया है.

क्रीमिया पर रूस के कब्जे से पूरे विश्व का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ताना-बाना बिखर गया है. हालात ये हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्रीमिया को रूस में मिलाए जाने के मुद्दे पर मास्को के ख़िलाफ़ पश्चिमी देशों की एकजुटता का आह्वान किया है. ओबामा जब हेग गए, तो वहां उन्होंने जी-7 देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें इस बारे में चर्चा की गई कि शीत युद्ध के बाद से पूर्व-पश्चिम के इस सबसे बड़े गतिरोध के हल के लिए क्या क़दम उठाए जाएं? रूस को लेकर इन देशों में इतनी नाराज़गी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एवं शीर्ष आर्थिक शक्तियों ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के ख़िलाफ़ दबाव बनाने के लिए जून में सोची में प्रस्तावित जी-8 शिखर बैठक के स्थान पर ब्रसेल्स में जी-7 की शिखर बैठक बुलाए जाने की बात कही और उसमें रूस को शामिल न करने पर भी विचार किया गया.

रूस का यूरोप के अंदर बहुत महत्व है, क्योंकि यूरोप में गैस की कुल खपत का 25 फ़ीसद रूस से आता है. इस तरह से यहां खर्च होने वाली ज़्यादातर गैस रूस से ही सप्लाई की जाती है. ऐसे में रूस पर ज़्यादा दबाव डालने से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा. विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से यूरो नीचे जाएगा, क्योंकि मध्य यूरोप ज़्यादातर गैस रूस से लेता है और यूरो जोन का रूस के साथ गहरा आर्थिक संबंध है. दूसरी तरफ़ यूक्रेन रूस एवं दूसरे यूरोपीय देशों के बीच की अहम कड़ी है. आधी से ज़्यादा गैस सप्लाई पाइप लाइन यूक्रेन से गुजरती है. लिहाजा, सप्लाई बंद होने से यूरोपीय देशों में गैस महंगी हो सकती है. साथ ही यूक्रेन गेहूं और मक्के का बड़ा निर्यातक है. गेहूं और मक्के का निर्यात रुकने से अनाज के दाम बढ़ेंगे. ऐसे में किसी तरह की पाबंदी सीधे यूरो को प्रभावित करेगी.

क्रीमिया संकट पर संयुक्त राष्ट्र संघ का रवैया पहले उत्पन्न संकटों की तरह उदासीन है. सीरिया हो या अफगानिस्तान, इराक हो या विश्व के अन्य देश, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सार्थकता कभी सिद्ध नहीं की. यह बात समय-समय पर उठती रहती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है और ये देश इस वैश्विक संस्था के मार्फत अपना उल्लू सीधा करते हैं. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की मांग की है. मून को विश्वास है कि रूस और यूक्रेन के संबंध बहाल करने का एकमात्र मार्ग राजनीतिक समाधान है. सवाल यह उठता है कि क्रीमिया को रूस द्वारा मिला लेने के बाद यह बातचीत कितनी सार्थक होगी, बातचीत किस मुद्दे पर होगी, यह पूरी दुनिया को पता है. मतलब यह कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ विद्रोही या संघर्षरत देशों की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेगा, तब तक उसके आदेश को ये देश ठेंगे पर रखकर चलते रहेंगे. रूस न कल कमजोर था और न आज कमजोर है. चूंकि वह एक परमाणु संपन्न देश है, इसलिए अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों को भी रूस की नीतियों, उसके क़दमों एवं निर्णयों का खुलकर विरोध करने में सौ बार सोचना पड़ता है. दूसरी तरफ़ रूस को भी अपनी और सामने वाले की ताकत पता है, इसीलिए वह किसी की परवाह नहीं करता और अपनी मनमानी करता रहता है. आज उसने यूक्रेन को लेकर मनमानी की है, लेकिन कल भी उसने सीरिया मामले पर हस्तक्षेप किया था, तो उस समय अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह रूस के क़दमों का सीधा विरोध दर्ज कर सके.

अब बात करते हैं रूस के मुद्दे पर भारत के रुख की. क्रीमिया संकट पर भारत ने एक प्रकार से रूस का समर्थन ही किया है. तभी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि चीन और भारत ने यूक्रेन संकट के बारे में संयत और सही रवैया अपना कर रूस को राहत प्रदान की है. आज विश्व बहुत तेजी से एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय राष्ट्र की तरफ़ बढ़ रहा है. ऐसे में भारत को भी कूटनीति का परिचय देते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह इन राष्ट्रों की खेमेबंदी में पीछे न रह जाए. रूस ने भले ही भारत की तारीफ़ में कसीदे काढ़े हों, लेकिन भारत को यह ध्यान रखना होगा कि रूस द्वारा उसकी तारीफ़ पश्चिमी देशों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसी रही होगी. इसलिए भारत को चाहिए कि वह उचित कूटनीति का प्रयोग करते हुए न तो किसी के बहुत क़रीब जाए और न किसी से बहुत दूर. मतलब यह कि भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, खास तौर पर तब, जब दो राष्ट्रों के बीच कोई मामला हो, उदासीनता का परिचय दे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं

किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, लेकिन उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था, वह सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हुई है. इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, लेकिन बाबा ने आज्ञा नहीं दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया.

एक बार...

एक फूल से प्रसन्न हो जाते हैं साईं बाबा

चौथी दुनिया ब्यूरो

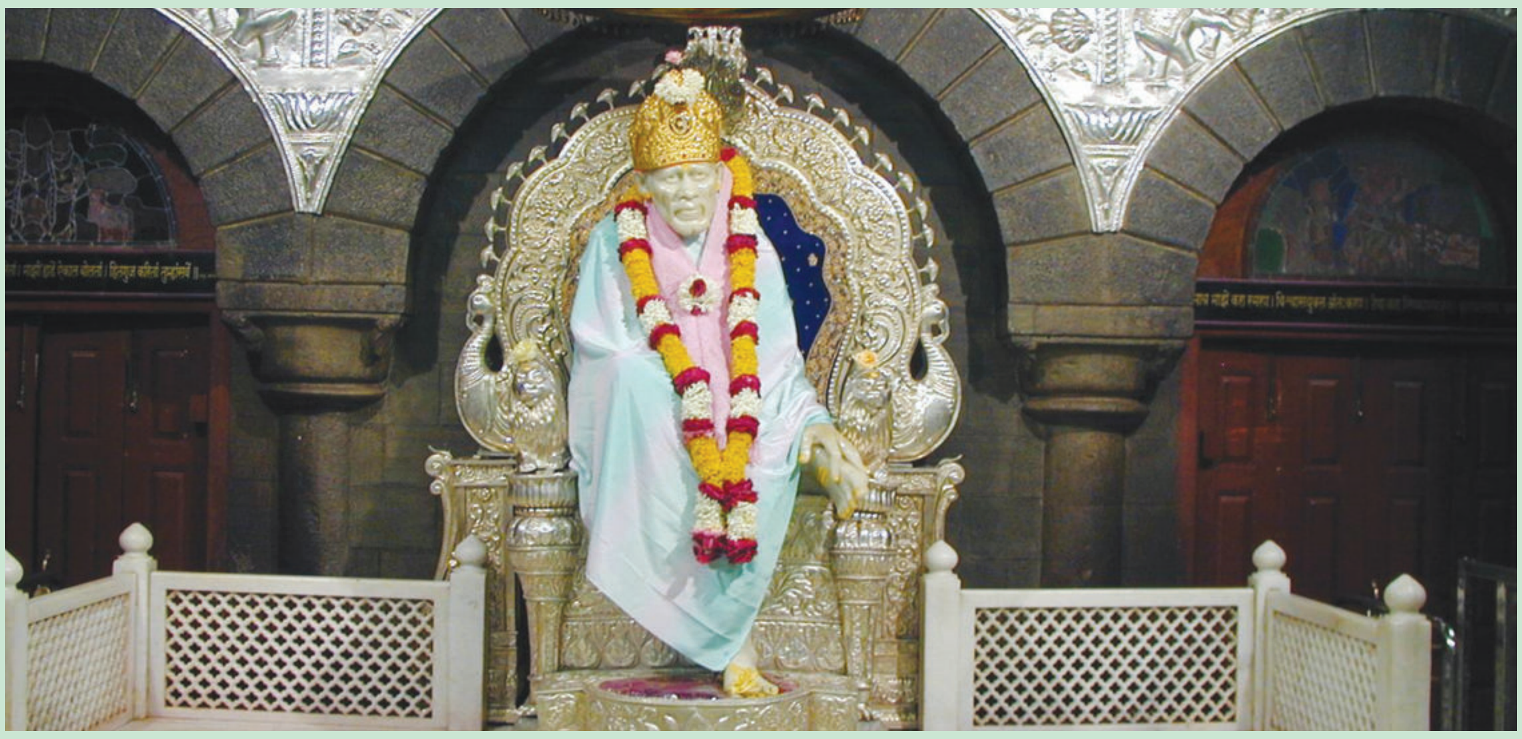

शिरडी के साईं बाबा गुरु, योगी एवं फकीर थे. हिंदू और मुसलमान उन्हें संत कहते हैं और उनकी भक्ति करते हैं. कई भक्त उन्हें शिव का अवतार भी मानते हैं. वहीं कुछ उन्हें संत कबीर का रूप मानते हैं. साईं बाबा ने प्रेम, क्षमा, मदद, सेवा, संतोष, मन की शांति और ईश्वर एवं गुरु के प्रति भक्ति का नैतिक पाठ पढ़ाया. साईं बाबा ने अपना जीवन भक्तों के नाम कर दिया. वह अपने भक्तों से प्रेम करते थे, उनके साथ सभी त्योहारों में शामिल होते थे और धूमधाम से त्योहार मनाते थे. वह हिंदू भक्तों के साथ रामनवमी, दीवाली एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और मुस्लिम भक्तों के साथ मुहर्रम एवं ईद मनाते थे. भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध अंत:करण वाले भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं. बाबा के जो भक्त सचमुच उन्हें कुछ भेंट करना चाहते हैं और यदि वे ऐसा करना भूल जाते हैं, तो बाबा उन्हें दूसरे व्यक्ति द्वारा याद दिलाते हैं और भेंट चढ़ाने के लिए कहलवाते हैं. बाबा भेंट प्राप्त कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

रामचंद्र ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी भी पूजा नहीं की थी. उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है. अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और दफ्तर चले गए. दोपहर को घर लौटने पर जब वह भोजन के लिए बैठे, तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइए से इस संबंध में प्रश्न किया. उसने बताया कि आज विस्मृतिवश वह नैवेद्य अर्पण करना भूल गए.

साईं बाबा ने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं. बाबा के रामचंद्र नामक एक भक्त थे. उनकी पत्नी और पुत्र भी बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे. एक बार उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र एवं उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, लेकिन उनका पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत नहीं हो रहा था. उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना-समाजी हैं. वह साईं बाबा के पूजनादि का उचित ध्यान न रख सकेंगे, लेकिन पिता ने आश्वासन दिया कि पूजन यथाविधि होता रहेगा. मां एवं पुत्र ने शुक्रवार की रात्रि को शिरडी के लिए प्रस्थान किया. दूसरे दिन शनिवार को बाबा के भक्त रामचंद्र ने सुबह उठकर, स्नानादि करके पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा, जैसे मेरा पुत्र करता रहा है, लेकिन कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना. ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री अर्पित की, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दी गई. उस दिन की शाम और अगला दिन रविवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया. सोमवार को उन्हें दफ्तर जाना था. वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया.

रामचंद्र ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी भी पूजा नहीं की थी. उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है. अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और दफ्तर चले गए. दोपहर को घर लौटने पर जब वह भोजन के लिए बैठे, तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइए से इस संबंध में प्रश्न किया. उसने बताया कि आज विस्मृतिवश वह नैवेद्य अर्पण करना भूल गए. यह सुनकर वह तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा से सिर झुकाकर क्षमायाचना करने लगे और बाबा से उचित पथ-प्रदर्शन न करने एवं पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे. उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि यह पत्र बाबा के श्रीचरणों पर रखकर उनसे कहे कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं.

यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी, तभी बाबा ने उनकी पत्नी से कहा, मां, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था. द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, लेकिन वहां देखा कि भाऊ (रामचंद्र) मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं. अत: आज मैं भूखा ही लौट आया हूं. किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, लेकिन उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था, वह सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हुई है. इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, लेकिन बाबा ने आज्ञा नहीं दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया. उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ, उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की. दूसरे दिन एक-दूसरे के पत्र उन्हें डाक द्वारा मिले. रामचंद्र बाबा का चमत्कार समझ गए और नियमित रूप से बाबा की पूजा करने लगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश,
पिन-201301
ई-मेल feedback@ chau-thiduniya.com

पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ

जहां पांडवों ने किए शिव के दर्शन

धर्मेंद्र सिंह

केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है. केदारनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं. यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के बीच खुलता है. केदारनाथ मंदिर पत्थरों से कत्यूरी शैली में बना हुआ है. इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था. उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ दो मुख्य तीर्थ स्थान हैं और दोनों के दर्शनों का बहुत महत्व है. मान्यता है कि जो भक्त केदारनाथ का दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसे यात्रा के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती. केदानाथ के साथ-साथ नर-नारायण के दर्शन का फल समस्त पापों का नाश करके जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है.

केदारनाथ मंदिर छह फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है. मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए रास्ता बना है. प्रांगण में बाहर भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित है. प्रात:काल ज्योतिर्लिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर घी का लेप लगाया जाता है, धूप-दीप जलाकर आरती की जाती है. इसके बाद ही भक्तगण दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं. संध्या के समय भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है. उन्हें अनेक प्रकार से सजाया जाता है, लेकिन उस समय भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन केवल दूर से कर सकते हैं. केदारनाथ मंदिर के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं.

इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि हिमालय पर्वत के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर-नारायण नामक ऋषि तपस्या करते थे. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, तो नर-नारायण ने भगवान शिव से वहीं सदा वास करने के लिए वर मांग लिया. भगवान शिव ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने का वरदान दिया. वहीं पंच केदार की कथा के अनुसार, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वह उनसे नाराज थे. पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी गए, लेकिन भोलेनाथ उन्हें वहां नहीं मिले. पांडव उन्हें खोजते-खोजते हिमालय तक जा पहुंचे. भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे. पांडव भी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए केदार पहुंच गए. भगवान शिव ने उन्हें देखकर बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जा मिले, पर पांडवों को संदेह हो गया था.

भीम ने विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर फैल गए. अन्य सभी पशु तो निकल गए, लेकिन शिव जी बैल के रूप में पैर के नीचे से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए. भीम वृष का रूप धारण किए भोलेनाथ को पकड़ने के लिए झपटे, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान होने लगे. तब भीम ने बैल की पीठ पर निकला हुआ त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया. भक्तों के सभी कष्ट दूर करने वाले भगवान शिव पांडवों की भक्ति और उनका दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए. उन्होंने उसी समय पांडवों को दर्शन दिया और उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की. केदारनाथ में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप बैल की पीठ पर निकला हुआ त्रिकोणात्मक भाग जैसा है, जिसकी पूजा की जाती है.

कहा जाता है कि भगवान शिव जब अंतर्ध्यान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर वाला भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है. इसी तरह शिव की भुजाएं तंगुनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए. इन मंदिरों समेत केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है. दीपावली के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं. मंदिर में दीप जलाकर रखा जाता है, जो 6 महीने तक जलता रहता है. पुरोहित ससम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं. 6 माह बाद मंदिर का कपाट खुलता है और उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है. भगवान शिव की महिमा से दीपक 6 माह तक जलता रहता है और कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ़-सफाई मिलती है, जैसी पुजारी छोड़कर जाते हैं. केदारनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पापों एवं दु:खों का अंत हो जाता है और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है.

कैसे जाएं:-

केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आप बस, रेल और हवाई यात्रा कर सकते हैं. यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, तो देश के किसी भी एयरपोर्ट से आप देहरादून जाएं. वहां से बस या टैक्सी द्वारा केदारनाथ जा सकते हैं. रेलमार्ग से जाना चाहते हैं, तो देश के किसी भी प्रमुख रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश जाएं, फिर वहां से आप बस या टैक्सी द्वारा केदारनाथ पहुंच सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

पंडित जी की परीक्षा

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक शहर में एक विद्वान पंडित रहते थे, उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी. एक गांव में उन्हें मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया. वह गंतव्य की ओर जाने के लिए एक बस में चढ़े और किराया देकर सीट पर बैठ गए. कंडक्टर ने किराया काटकर बचे हुए पैसे उन्हें वापस कर दिए. उन पैसों में कंडक्टर ने दस रुपये अधिक दे दिए. पंडित जी ने सोचा कि वह दस रुपये कंडक्टर को वापस कर दें, पर अगले ही पल उनके मन में विचार आया कि आख़िर यह कंपनी वाले लाखों रुपये कमाते हैं. इसे भगवान की भेंट समझ कर अपने पास ही रख लेता हूं. वह इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे कि उनका गंतव्य आ गया. बस से उतरते हुए उन्होंने कंडक्टर को दस रुपये दिए और कहा, भाई तुमने पैसे वापस करते समय दस रुपये अधिक दे दिए थे. कंडक्टर ने मुस्कराते हुए कहा, आप गांव के मंदिर के नए पुजारी हैं न? पंडित जी के हामी भरने पर कंडक्टर ने कहा, मेरे मन में कई दिनों से आपका प्रवचन सुनने की इच्छा है. आपको बस में देखा, तो ख्याल आया कि आपकी ईमानदारी की परीक्षा ले लेते हैं. आपका आचरण भी आपके प्रवचन जैसा है. यह कहकर कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी. पंडित जी ने बस से उतर कर दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, तेरा लाख-लाख शुक्र है, जो तूने मुझे बचा लिया. मैंने तो दस रुपये के लालच में तेरी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी, पर तूने सही समय पर मुझे सद्बुद्धि दे दी.

शिक्षा : लालच में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

गूगल सर्च में भी नरेंद्र मोदी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. नरेंद्र मोदी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में तो छाए ही हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रकाशन की दुनिया की बात करें, तो वहां भी नरेंद्र मोदी का दबदबा नज़र आता है. किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर में आप किताबों के सेक्शन में जाकर नरेंद्र मोदी सर्च करेंगे, तो कम से कम तीन पेज खुलेंगे और आपके सामने मोदी पर लिखी दर्जनों किताबें होंगी. हर भाषा और अलग-अलग मूल्य की. यही हाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद किताबों की दुकान से लेकर पॉश इलाके के बुक स्टोर का है.

किताबों में लोकप्रिय मोदी

अनंत विजय

लोकसभा चुनाव सिर पर हैं. सियासी बिसात पर हर तरह की चालें चली जा रही हैं. सियासत के इस खेल में प्यादे से लेकर वजीर एवं बादशाह तक पूरी तरह से मशरूफ हो चुके हैं. हर दल किसी न किसी तरह अपनी गोटी फिट करना चाह रहा है. इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अब तक हुए चुनाव से अलग है. इस चुनाव में सोशल मीडिया राजनीतिक दलों के प्रचार के एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और दोनों अपने मतदाताओं से इसके जरिए लगातार संपर्क में रहते हैं. सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर तो नरेंद्र मोदी सभी दलों के नेताओं से काफी आगे हैं. ट्वीटर पर उनके तक़रीबन छत्तीस लाख फॉलोवर हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के लगभग सोलह लाख. अभी हाल में जारी हुए आंकड़ों के हिसाब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मेंशनिंग में नरेंद्र मोदी अपने प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं से काफी आगे हैं.

गूगल सर्च में भी नरेंद्र मोदी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. नरेंद्र मोदी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में तो छाए ही हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रकाशन की दुनिया की बात करें, तो वहां भी नरेद्र मोदी का दबदबा नज़र आता है. किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर में आप किताबों के सेक्शन में जाकर नरेंद्र मोदी सर्च करेंगे, तो कम से कम तीन पेज खुलेंगे और आपके सामने मोदी पर लिखी दर्जनों किताबें होंगी. हर भाषा और अलग-अलग मूल्य की. यही हाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद किताबों की दुकान से लेकर पॉश इलाके के बुक स्टोर का है. हर जगह पाठकों की रुचि और उनके खर्च करने की क्षमता के मद्देनज़र नरेंद्र मोदी पर लिखी किताबें मौजूद हैं. यह भी नहीं है कि मोदी पर लिखी किताबें किसी एक भाषा में प्रकाशित हो रही हों. हर भाषा के लेखक ने मोदी के इर्द- गिर्द किताबें लिखीं. यहां तक सुदूर दक्षिण में तमिल में नरेंद्र मोदी की जीवनी छपी है और जानकारों के मुताबिक, तमिल में भी यह किताब खूब बिक रही है.

ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ मोदी के प्रशंसकों ने ही किताबें लिखी हैं, उनके धुर विरोधियों ने भी मोदी और उनकी राजनीति को केंद्र में रखकर किताबें लिखी हैं. हिंदी के लेखक जगदीश्वर चतुर्वेदी ने मोदी की फासीवादी रणनीति को अपनी किताब-नरेंद्र मोदी और फासीवादी प्रचार कला में परखा है. मोदी और उनकी नीतियों की आलोचनात्मक किताबें संख्या के लिहाज से बेहद कम हैं. अब सवाल यही उठता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बाज़ार में मोदी और उन पर केंद्रित किताबों की बाढ़ क्यों आ गई है? इन वजहों की पड़ताल के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. लोकसभा चुनाव की आहट को महसूस करते ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए यत्न शुरू कर दिए थे. हम मान सकते हैं कि मोदी की सद्भावना यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी. मोदी की टीम ने उनके इमेज मेकओवर को लेकर खासी रणनीति बनाई थी.

2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड और उसके बाद के सांप्रदायिक दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी मीडिया के निशाने पर रहे हैं. उनके हर क़दम को मीडिया ने कसौटी पर कसा. इसके अलावा मोदी का विवादित व्यक्तित्व, आलोचकों का उन पर तानाशाह होने का आरोप, समर्थकों द्वारा श्रमपूर्वक बनाई गई उनकी विकास पुरुष की छवि और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में चल रही किंवदंतियों ने भी लेखकों को उन पर लिखने के लिए कच्चा माल मुहैया कराया. कई लेखकों ने श्रमपूर्वक नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनके कामों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से उसे इस शख्सियत को समझने के लिए एक गंभीर प्रयास माना गया. 2013 में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब-नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स छपकर आई, तो लोगों ने बहुत उत्सुकता से उसे पढ़ा. नीलांजन की इस किताब में भी मोदी के पिता की चाय की दुकान और उनके चाय बेचने का जिक्र है.

किताब में बताया गया है कि मोदी का बचपन किस तरह से कठिनाइयों में बीता. बाद में जब मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए, तो पहले उन्हें हेडगेवार भवन में दफ्तर की साफ़-सफाई का काम दिया गया और जब वहां के लोगों को लगा कि मोदी अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकते हैं, तो उन्हें चाय बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई. नीलांजन ने इस किताब में मोदी से जुड़े कई व्यक्तिगत एवं दिलचस्प प्रसंग लिखे हैं, लेकिन मोदी के जीवन का एक लंबा कालखंड इस किताब में नहीं है. इस किताब से नीलांजन मुखोपाध्याय को काफी प्रसिद्धि मिली. बाद में तो मोदी का बचपन में चाय बेचना उनके प्रचार का एक हिस्सा भी बना. कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बदजुबानी के बाद मोदी ने पूरे देश में चाय पर चर्चा जैसा कार्यक्रम तक शुरू कर दिया.

नीलांजन की किताब छपने के आसपास ही वरिष्ठ पत्रकार किंशुक नाग की किताब-द नमो स्टोरी, अ पॉलिटिकल लाइफ छपकर आई. इस किताब की भी व्यापक चर्चा हुई. इन दोनों किताबों की बिक्री ने प्रकाशन जगत को न सिर्फ़ चौंकाया, बल्कि उन्हें मोदी पर किताबें छापने के लिए उकसाया भी. प्रकाशन के कारोबार से जुड़े लोगों को मोदी पर लिखी किताब में मुनाफे का सौदा नज़र आया. नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजी में लिखी किताबों के अन्य भाषाओं में अनुवाद छपने लगे. पिछले कुछ दिनों में हिंदी के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन ने नरेंद्र मोदी पर तक़रीबन आधा दर्जन से ज़्यादा किताबें छापीं. बाल पाठकों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी के जीवन पर ग्राफिक उपन्यास-भविष्य की आशा नरेंद्र मोदी छापा गया. प्रभात प्रकाशन के निदेशक पियूष कुमार का दावा है कि मोदी से जुड़ी किताबों की खासी मांग है, लिहाजा वह इसे छाप रहे हैं. दूसरी वजह है कि लोकसभा चुनाव के पहले देश की जनता में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में जानने की उत्सुकता भी है.

इस पूरे वातावरण को देखते हुए कुछ लेखकनुमा लोगों को भी संभावना नज़र आई और वे भी इसे भुनाने में जी-जान से जुट गए. यहां पाठकों को याद दिलाते चलें कि जब नब्बे के दशक में बिहार के नेता लालू यादव का डंका बजा करता था, तो उन पर भी काफी किताबें छपी थीं. कई लेखकों ने तो लालू चालीसा तक लिख डाली थी. लालू चालीसा लिखकर अपने नेता का ध्यान खींचने वाले एक शख्स तो चालीसा की महिमा और उसके आशीर्वाद से संसद तक जा पहुंचे थे. इसीलिए लोगों को अब नरेंद्र मोदी में संभावना नज़र आई और वे तरह-तरह से मोदी पर किताबें लिखने लगे. कई लोगों ने विभिन्न समय पर मोदी पर लिखे अलग-अलग लेखों को संपादित करके एक लंबी भूमिका के साथ किताब बना दी और उसे बाज़ार में पेश कर दिया.

मोदी की लोकप्रियता को भुनाने और मोदी तक पहुंचने के लिए लोगों को यह रास्ता आसान लगा और वे इसमें जुट गए. प्रकाशक तो बाज़ार को भुनाने में लगे ही हैं और प्रकाशन जगत के लिए यह शुभ संकेत है कि बाज़ार को ध्यान में रखकर काम हो रहा है. मोदी की दर्जनों जीवनी छापने वाले प्रकाशकों को यह याद दिलाना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की कोई प्रामाणिक जीवनी बाज़ार में नहीं है. मोदी पर जितनी किताबें बाज़ार में हैं या फिर छपकर आने वाली हैं, उससे यह संकेत तो मिलता ही है कि नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जिनके बारे में पाठक सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं और इसी चाहत को भुनाकर बाज़ार मुनाफा भी कमा रहा है. प्रकाशन जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद अगर सबसे ज़्यादा जीवनियां किसी भारतीय राजनेता की बाज़ार में हैं, तो वह हैं नरेंद्र मोदी. ■

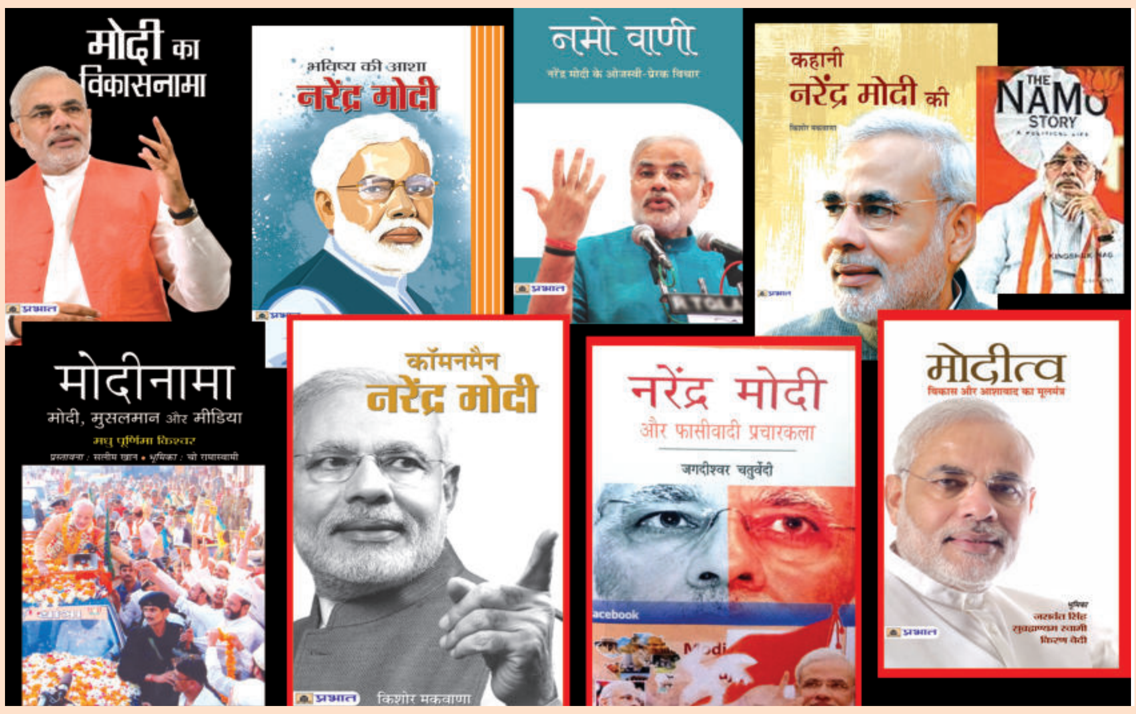

(लेखक आईबीएन-7 में डिप्टी एडिटर हैं)
anant.ibn@gmail.com

कविताएं

एक पुरुष की अनकही

शबनम खान

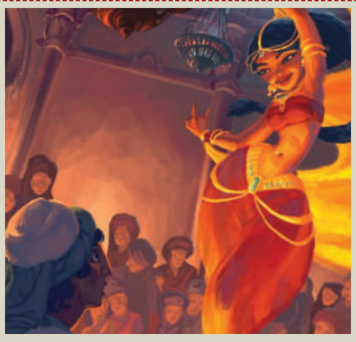

तुम, मेरे अस्तित्व को
खुद के अस्तित्व पर ओढ़े,
समेटे अपनी इच्छाओं को
मेरी इच्छाओं में,
हिस्सा बन गई हो
मेरे जीवन का.
सदा मुस्कुराती तुम
कभी-कभी
इतराती भी हो,
तुम्हें मेरे साथ का
कुछ घमंड-सा हो चला है.
पर सच कहूं,
यह घमंड तुम्हारा
मुझे मेरे संपूर्ण
होने का एहसास
दिलाता है,
तुम पर अपना
मालिकाना हक़
समझने लगा हूं.
तुम मुझे मेरी
संपत्ति-सी लगती हो,
चाहता हूं,
मेरी पकड़ तुम पर
हमेशा बनी रहे.
तुम बनके मेरी रहो
जन्मों के लिए,
कुछ तो हो
जो केवल मेरा हो,
चाहे फिर मैं
किसी और का भी हो जाऊं.
जानता हूं तुम
कुछ न कहोगी,
मेरे साये में ऐसे ही
जीती रहोगी,
न मैं रहूं संग तो
खुद की नियति को रोओगी.
बस, तुम्हारा यही हाल
मैं देख नहीं पाऊंगा,
इसलिए तुम्हें संग रखूंगा
लेकिन सुनो,
तुम्हारे संग न रह पाऊंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

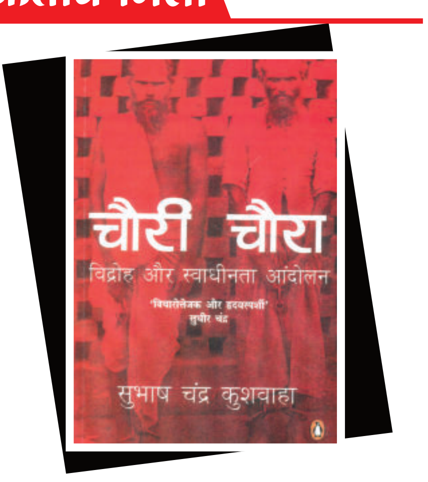

पुस्तक	लेखक
चौरी चौरा	सुभाष चंद्र कुशवाहा
प्रकाशक	**मूल्य**
पेंगुइन बुक्स, दिल्ली	225 रुपये

किसी भी देश का इतिहास उसकी भावी पीढ़ी का रास्ता तैयार करता है. अगर इतिहास ही भ्रामक हो, तो वह किसी को भी दिग्भ्रमित कर सकता है. भारत के स्वाधीनता संग्राम का जब इतिहास लिखा गया, तो उसमें कई प्रसंगों-घटनाओं के वे असली नायक दर्ज होने से रह गए अथवा कर दिए गए, जिन्होंने जाति-धर्म की सारी सीमाएं लांघकर ब्रिटिश हुकूमत को सपने में भी डरने को विवश कर दिया था. चौरी चौरा का किसान विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे असल कारण क्या थे, इस संबंध में अनेक बार रोशनी डालने के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आ सकी. वह सच अक्षरश: देश के सामने आए, इसी प्रयास का नतीजा है, पुस्तक-चौरी चौरा, जिसके लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा ने अपनी मेहनत एवं समर्पण के बल पर कई ऐसे तथ्यों को आपस में पिरोने का काम किया है, जो सिर्फ़ जनसामान्य ही नहीं, बल्कि शासक वर्ग की भी आंखें खोलने में कामयाब होंगे.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

स्त्री विमर्श पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज

प्रत्यूष चंद्र मिश्र

अरुण नारायण के अतिथि संपादन में निरंजना का दूसरा अंक हिंदी पत्रिकाओं में एक प्रस्थान बिंदु की तरह आया है. स्त्रियों के सृजन, संघर्ष एवं साझेदारी पर केंद्रित होने और कई उत्कृष्ट रचनाओं के चलते इसे निरंजना के एक यादगार अंक के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए. जैसा कि संपादकीय में अरुण नारायण ने उल्लेख किया है कि यह अंक संयुक्त बिहार में आज तक की स्त्री के कई रूपों एवं उनकी अर्थछवियां पकड़ने की कोशिश है. इसी के तहत खंड 3 में बिहार में स्त्री मताधिकार: कांटों की राह से मंजिल तक एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी आलेख है. इस पूरे आलेख से गुजरते हुए और बिहार विधानमंडल में महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान स्थिति देखते हुए पितृसत्ता की जकड़ को वर्तमान समय तक साफ़ देखा जा सकता है. तथ्यात्मक रूप से सुदृढ़ और गंभीर विश्लेषण के साथ ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की हड़बड़ी से बचने की कोशिश इस आलेख में साफ़ देखी जा सकती है.

लैंगिक विभेद पर रविंद्र कुमार पाठक का आलेख यह व्याकरण किसने बनाया, भाषा एवं व्याकरण के पुरुषवादी वर्चस्व पर एक गंभीर विमर्श है. रविंद्र का साफ़ मानना है कि भाषा की लिंगभेदी प्रवृत्ति अधिक सभ्य जातियों की भाषाओं में अधिक स्पष्ट होती है और कम सभ्य या असभ्य प्राय: जातियों की भाषाओं में कम स्पष्ट या अस्पष्ट. वह इसका सीधा-सा कारण बताते हैं कि स्त्री को दोयम दर्जे में डालने वाली विचारधारा (पितृसत्ता) सभ्यताकृत या सांस्कृतिक है, और जो जातियां प्रकृति के निकट होती हैं, वे स्त्री-पुरुष के बीच विभेद करने वाली मानसिकता से कम ग्रस्त या मुक्तप्राय: होती हैं. चारदीवारी के भीतर-बाहर खंड के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण आलेख शामिल किए गए हैं. नक्सल, महिला जेल और डायरी-मेरी टेलर, बोधगया का भूमि संघर्ष-केलकर गाला, बिहार में दासप्रथा एवं महिला उत्पीड़न-डॉ. ए के विश्वास और स्त्री गाथा की महज एक पंक्ति-रोज केरकेट्टा आदि आलेख इस पूरी पत्रिका के वैचारिक पक्ष को खासा मजबूत बनाते हैं. स्त्री के सवाल को लेकर कोई पत्रिका इतने विस्तार में बहुआयामी सामग्री पाठकों के समक्ष रखे, ऐसा हिंदी में दुर्लभ है.

चारदीवारी के भीतर-बाहर खंड के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण आलेख शामिल किए गए हैं. नक्सल, महिला जेल और डायरी-मेरी टेलर, बोधगया का भूमि संघर्ष-केलकर गाला, बिहार में दासप्रथा एवं महिला उत्पीड़न-डॉ. ए के विश्वास और स्त्री गाथा की महज एक पंक्ति-रोज केरकेट्टा आदि आलेख इस पूरी पत्रिका के वैचारिक पक्ष को खासा मजबूत बनाते हैं.

खंड 5 के अंतर्गत आधी हकीकत पूरा फ़साना में एक महत्वपूर्ण आलेख संजीव चंदन का है, जिसमें उन्होंने समकालीन लेखन के स्त्री स्वर को बहुत बारीकी से रेखांकित किया है. खंड 6 के अंतर्गत वाणी दास का किशन पटनायक पर आलेख-मेरे हमसफर: मेरे हमनवा और महासुंदरी देवी पर रविंद्र कुमार दास का आलेख-इतिहास हुआ मिथिला चित्रकला का एक अध्याय रोचक है. वैचारिक पक्ष के साथ ही स्त्री अस्मिता के सवाल को लेकर कुछ बेहतरीन कविताएं एवं कहानियां इस अंक की जान हैं. उतनी दूर मत ब्याहना बाबा-निर्मला पुतुल, इस स्त्री से डरो-कात्यायनी, अनब्याही बेटियां-पूनम सिंह और पार्वती योनि-नेहा नरुक्का आदि कविताएं स्त्री के सवाल को कई कोनों से जांचती-परखती हैं. इसके अलावा स्त्री विमर्श की कुछ पुरानी, लेकिन बेहतरीन कविताएं इस अंक में शामिल हैं. जैसे छतों पर लड़कियां-आलोक धन्वा, पृथ्वी किसलिए घूमती रही- अरुण कमल, साध्वियां-कुमार अम्बुज, हम औरतें-वीरेन डंगवाल, ईश्वर-अजित आज़ाद, घर एक दु:खांत कथा-रमण कुमार सिंह और किलकारी-सतीश नूतन आदि महत्वपूर्ण कविताएं हैं. जिस कविता का उल्लेख विशेष तौर पर किया जाना चाहिए, वह है मुसाफिर बैठा की कविता-एक बिटिया की जन्मकथा. एक पिता की संवेदना के साथ ही स्त्रियों की दासता की कहानी बड़ी वैचारिक प्रौढ़ता से इस कविता में कही गई है.

खंड 7 में कुछ चुनी हुई कहानियां शामिल की गई हैं, जिनमें रवींद्रनाथ ठाकुर की दृष्टिदान, रामधारी सिंह दिवाकर की रंडियां, अश्विनी कुमार पंकज की अथ हुदूड़ दुड़गम: असुर हत्या कथा एवं शंभू पी सिंह की जनता दरबार आदि प्रमुख हैं. दृष्टिदान भारतीय साहित्य की एक कालजयी कहानी है, वहीं रंडियां अपनी सशक्त शैली के कारण हमारे समय से मुठभेड़ करती है. नीलिमा सिन्हा की कहानी-बुद्धिजीवी बैकुंठ के डेफोडिल्स कहीं से भी स्त्रियों के किसी विषय से संबंधित नहीं है. इस कहानी को सिर्फ़ स्त्रियों के सृजन एवं साझेदारी के आधार पर शामिल किया गया है. निरंजना के इस पूरे अंक से गुजरते हुए विषय के चयन, सामग्री एवं डिज़ाइन पर सूक्ष्म संपादकीय दृष्टि का मुरीद हो जाना पड़ता है. कहीं-कहीं प्रूफ की कमी अखरती ज़रूर है, लेकिन अतिथि संपादक अरुण नारायण इस अंक के संपादन से संभावनाओं का नया द्वार अवश्य खोलते हैं, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

कंपनी का दावा है कि यह बल्ब एंड्रॉयड 4.3 या इससे अधिक एंड्रॉयड वर्जन के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकता है. अगर 10 वॉट के इस बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, तो यह 10 साल से ज़्यादा समय तक काम करेगा.

एलजी लाएगी स्मार्ट बल्ब

जानी-मानी कोरियाई कंपनी एलजी इलेक्ट्रानिक्स ने एक ऐसा बल्ब पेश किया है, जो आईफोन और एंड्रॉयड फोन के साथ कनेक्ट हो सकता है. यह कंपनी का पहला स्मार्ट बल्ब है, जो वाई-फाई और ब्लूटुथ के जरिये कनेक्ट हो जाएगा. जब आपकेफोन पर कोई कॉल आएगी, तो यह स्मार्ट बल्ब ब्लिंक करने लगेगा. कंपनी का दावा है कि यह बल्ब एंड्रॉयड 4.3 या इससे अधिक एंड्रॉयड वर्जन के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकता है. अगर 10 वॉट के इस बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, तो यह 10 साल से ज़्यादा समय तक काम करेगा. पार्टी मोड पर यह बल्ब स्मार्ट फोन से आने वाले म्यूजिक के मुताबिक ब्राइटनेस मेंटेन करेगा. ■

मोटोरोला लॉन्च करेगी स्मार्ट वॉच

स्मार्ट वॉच मोटो-360 नाम से बाज़ार में उतारने वाली है. यह अन्य स्मार्ट वॉच के मुकाबले काफी अलग और बेहतर डिजाइन के साथ उपलब्ध होगी.

सैमसंग, सोनी, एलजी, हुआवई एवं पेब्बल आदि के बाद अब अब मोटोरोला ने भी स्मार्ट वॉच लॉन्च करने का फ़ैसला किया है. अन्य कंपनियों को टक्कर देने के लिए मोटोरोला अपनी स्मार्ट वॉच मोटो-360 नाम से बाज़ार में उतारने वाली है. यह अन्य स्मार्ट वॉच के मुकाबले काफी अलग और बेहतर डिजाइन के साथ उपलब्ध होगी. इसमें आप नोटिफिकेशनंस, मैसेज एवं अलर्ट्स देख सकते हैं. इसमें गूगल वॉयस सर्च और नेविगेशन के अलावा कई अन्य फीचर्स हैं. यह कंपनी की पहली डिवाइस होगी, जो एंड्रॉयड वियर प्लेटफॉर्म पर काम करेगी. यह वायरलेस की तरह चार्ज होगी. मोटो-360 में विशेष तौर से स्मार्ट फोन के लिए बनाया गया एंड्रॉयड 4.3 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसका डिस्प्ले 1.8 इंच का है. यह स्मार्ट वॉच वाटरप्रूफ है. फिलहाल इसकी क़ीमत का खुलासा नहीं किया गया है.■

एलजी के नए हैंडसेट

एलजी ने अपना हैंडसेट एलजी एल-90 और एलजी एल-70 भारत में लॉन्च कर दिया है. एलजी इन्हें लॉन्च करने की घोषणा पहले कर चुकी थी. एलजी एल-90 क्वाडकोर से चलता है, जिसकी क़ीमत है 17,499 रुपये और एलजी एल-70, जो डुअल कोर प्रोसेसर से चलता है, उसकी क़ीमत है 14,500 रुपये. दोनों मॉडल एंड्रॉयड 4.4 किटकैट ओएस पर आधारित हैं. एलजी एल-90 डुअल सिम हैंडसेट है, जिसमें कोर्टेक्स ए-7 1.2 क्वाडकोर प्रोसेसर है. एलजी एल-90 में 1 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरेज एवं 32 जीबी माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट है. इसकी आईपीएस एलसीडी स्क्रीन 4.7 इंच की है, जिसमें प्रॉटेक्स के लिए गोरिल्ला ग्लास है और उसका रेजोल्यूशन 960 गुणा 540 पिक्सल है. इसमें 8 एमपी रियर कैमरा है, जिसमें एलईडी फ्लैश है. फ्रंट में 1.3 एमपी कैमरा है. इसमें 3जी, 2जी, वाई-फाई, जीपीएस एवं ब्लूटुथ आदि फीचर्स हैं. इसकी बैटरी 2450 एमएएच की है, जिसका वजन 126 ग्राम और मोटाई 9.7 मिमी है. इसमें वही हार्डवेयर है, जो मोटो जी में है. एलजी एल-70 स्नैपड्रैगन 200 1.2 जीएचजेड डुअल कोर कोर्टेकेस प्रोसेसर से चलता है. यह डुअल सिम हैंडसेट है, जिसमें 4.5 इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रेजोल्यूशन 800 गुणा 400 पिक्सल है. इसका रियर कैमरा 8 एमपी का है, जबकि फ्रंट 1.3 एमपी का. इसमें वे सभी फीचर्स हैं, जो दूसरे वाले हैंडसेट में हैं, लेकिन इसकी बैटरी 2100 एमएएच की है. ■

कंपनी ने यह कैमरा टू-पीस डिवाइस के तौर पर पेश किया है. दोनों पीस एक केबल से जुड़े हुए हैं और इसमें एक लैंस और एक कंट्रोल यूनिट है, जिन्हें शरीर के अलग-अलग अंगों पर पहना जा सकता है.

आइबॉल किंग 1.8 डी

यह अपने यूएसबी एवं ब्लूटूथ विकल्पों के साथ फाइल्स को आसानी से ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है. इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो महत्वपूर्ण कॉल्स रिकॉर्ड और मेमोरी कार्ड में सेव करने की सुविधा देती है.

अपने खोजपरक एवं नवीनतम तकनीकी उत्पादों के लिए मशहूर ब्रांड आइबॉल उपभोक्ताओं के लिए 1.8 इंच के डिस्प्ले वाला अपना नवीनतम फीचर फोन किंग 1.8 डी शीघ्र लॉन्च करेगा. अनेक विशिष्ट खूबियों के अतिरिक्त इसमें मल्टीमीडिया संबंधी अनेक गुण मौजूद हैं. यह एक स्पेशल चैंबर्ड स्पीकर से सुसज्जित है, जो न सिर्फ़ बहुत तेज, बल्कि स्पष्ट एवं विकार मुक्त ध्वनि उपलब्ध कराता है. इसमें 1800 एमएएच की बैटरी है, जिसके जरिए उपलब्ध पावर बैकअप 20 घंटे के संगीत एवं 10 घंटे के वीडियो प्लेबैक को सुनिश्चित करता है. यह 360 घंटे के स्टैंडबाई और 15 घंटे का टाक टाइम उपलब्ध कराता है. किंग 1.8 डी डब्लूएपी फंक्शनलिटी एवं जीपीआरएस सपोर्ट से सुसज्जित है. यह अपने यूएसबी एवं ब्लूटूथ विकल्पों के साथ फाइल्स को आसानी से ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है. इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो महत्वपूर्ण कॉल्स रिकॉर्ड और मेमोरी कार्ड में सेव करने की सुविधा देती है. इसमें लगे कैमरे की क्वालिटी काफी शॉर्प है और इसका स्क्रीन कहीं अधिक चमकदार. किंग 1.8 डी में एफएम है और एफएम रिकॉर्डिंग की सुविधा भी. इसमें ड्यूल लैंग्वेज सपोर्ट यानी अंग्रेजी एवं हिंदी की व्यवस्था है. इसमें मोबाइल ट्रैकर एवं प्राइवेसी प्रोटेक्शन विकल्प है. यह अनचाहे नंबर्स को ब्लैक लिस्ट करने के साथ-साथ नंबर्स को प्वाइट लिस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है. किंग 1.8 डी-साउंड की क़ीमत केवल 1099 रुपये है. ■

निसान की छोटी कार डैटसन गो

जापान की वाहन निर्माता कंपनी निसान ने अपने डैटसन ब्रांड की डैटसन गो नामक छोटी कार लॉन्च की है. इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत दिल्ली में 3.12 से 3.70 लाख रुपये के बीच होगी.

डटसन गो में 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन है, जिसे निसान माइक्रा की तर्ज पर बनाया गया है. यह कार एक लीटर में 20 किमी चलेगी. यह उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो पहली बार और कम क़ीमत वाली कार खरीदते हैं. इस कार में आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं. डैटसन गो भारतीय बाज़ार में शेवरले स्पार्क, मारुति सेलेरियो, मारुति ऑल्टो और हुंडई आई-10 जैसी कारों का मुकाबला करेगी. इसमें माइक्रा एक्टिवा वाला इंजन लगाया गया है, जो 1198 सीसी का है और 5000 आरपीएम पर 67 बीएचपी की पावर देता है. यह कार 5 सीटर है, जिसमें 5-स्पीड मैन्युअल गियर बॉक्स हैं. यह कार केवल पेट्रोल इंजन में ही उपलब्ध होगी.

इसमें मोबाइल डॉकिंग सॉल्यूशन है, जो म्यूजिक प्लेयर को रिप्लेस करता है. इसकी लंबाई 3,785 एमएम, चौड़ाई 1,635 एमएम, ऊंचाई 1,484 एमएम और व्हीलबेस 2,450 एमएम है.■

पैनासोनिक का वियरेबल कैमरा

पैनासोनिक ने दुनिया का पहला वियरेबल कैमकॉर्डर (एचएक्स-ए 500) लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि एचएक्स-ए 500 एक्शन पहला लाइटवेट, स्ट्रैप-ऑन कैमकॉर्डर डिवाइस है. यह 25 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से 4 के रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींच सकता है. ब्लर-फ्री स्लो मोशन में फ्रेम की स्पीड प्रति सेकंड 50 या 100 फ्रेम तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फ्रेम की स्पीड बढ़ने के साथ-साथ रेजोल्यूशन कम होता जाएगा. कंपनी ने यह कैमरा टू-पीस डिवाइस के तौर पर पेश किया है. दोनों पीस एक केबल से जुड़े हुए हैं और इसमें एक लैंस और एक कंट्रोल यूनिट है, जिन्हें शरीर के अलग-अलग अंगों पर पहना जा सकता है. दोनों पीस अलग-अलग रखकर भी काम लिया जा सकता है. इस कैमरे को स्मार्ट फोन से कनेक्ट किया जा सकता है. इसकी स्क्रीन व्यूफाइंडर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है. यह वाटर रेसिस्टेंट है, इसे पानी में 3 मीटर की गहराई में 30 मिनट तक डुबोकर रखा जा सकता है. एक्शन कैम की बिक्री मई में शुरू होगी. इसकी क़ीमत लगभग 35,940 रुपये है.■

जीएम इंडिया की क्रूज सेडान

जानी-मानी कंपनी जनरल मोटर्स इंडिया ने शेवरले क्रूज सेडान कार का नया मॉडल लॉन्च किया है. इसमें नई स्वचालित ट्रांसमिशन प्रणाली है. बगल में लगे शीशे पर मुड़ने के लिए संकेत देने वाले बल्ब हैं. नई सेडान कार में 2000 सीसी वीसीडीआई इंजन है. सामने एवं पीछे के बंपर और हेडलाइट्स में भी बदलाव किया गया है. इसे भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

गावस्कर बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने एन. श्रीनिवासन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है. गावस्कर आईपीएल खत्म होने तक बीसीसीआई की कमान संभालेंगे और आईपीएल से जुड़े कामों को देखेंगे. सुप्रीमकोर्ट ने आईपीएल की किसी भी टीम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन 27 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आईपीएल की जांच पूरी होने तक राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर रोक लगनी चाहिए. आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनील गावस्कर को बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने हुए एन. श्रीनिवासन को बीसीसीआई के कामकाज से दूर कर दिया है. अभी आईपीएल होने तक गावस्कर ही टूर्नामेंट के काम का जिम्मा संभालेंगे, जबकि बोर्ड का बाकी कार्य सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के जिम्मे होगा. आईपीएल के बाद वाइस प्रसिडेंट शिवपाल यादव बीसीसीआई का कामकाज देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनील गावस्कर से कहा है कि वह बीसीसीआई के साथ कॉमेंट्री के लिए किए गए करारों को तोड़ना होगा. दरअसल बीसीसीआई का तर्क था कि गावस्कर ने कॉमेंट्री के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसे में हितों के टकराव का मामला बनता है. इसी वजह से अब गावस्कर को कॉमेंट्री के लिए किया गया करार तोड़ना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आईपीएल टीम पर रोक नहीं लगाई है. सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी पर लगाए गए आरोपों पर भी सफाई दी. बीसीसीआई ने कहा कि वकील हरीश साल्वे द्वारा धोनी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं. साल्वे ने उन पर गुरुनाथ मयप्पन को बचाने का आरोप लगाया था. सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीसीसीआई अंतरिम अध्यक्ष के रूप काम के लिए गावस्कर को भुगतान करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गावस्कर का नाम इसलिए सुझाया था क्योंकि वे सीधे तौर पर क्रिकेट में सक्रिय हैं. उनकी छवि अन्य की तुलना में ज्यादा बेदाग है. फिक्सिंग के कारण क्रिक्रेट की बिगड़ती छवि सुधारने के लिए गावसकर से श्रेष्ठ दूसरा नहीं. गावस्कर की नियुक्ति के बारे में जब जांच समिति की अगुवाई कर रहे जस्टिस मुकुल मुद्गल से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी इस फैसले को जायज ठहराया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गावस्कर बीसीसीआई को काफी अच्छे से चला पाएंगे क्योंकि वह क्रिकेट को काफी अच्छे से समझते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कहा कि सलामी बल्लेबाज होने के नाते वह किसी भी भूमिका के लिए तैयार हैं. गावस्कर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का अंतरिम अध्यक्ष बनने को तैयार हैं. इन सबके बावजूद बीसीसीआई ने कोर्ट से अपील की कि श्रीनिवासन को जुलाई से अन्तरराष्ट्रीय क्रिकट परिषद के अध्यक्ष पद पर काबिज होने की अनुमति दी जाए.■

लिम्बाराम शिष्य के हाथों हुए ठगी का शिकार

लिम्बाराम ने अपने शिष्य का इंतजार किया और उससे सम्पर्क करने का प्रयास भी किया. थक हार कर अपने शिष्य के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया है लिम्बाराम ने कहा कि वह तीरंदाजी सीखने के लिए आ रहा था.

आज ऐसा हो गया है कि एक शिष्य अपने गुरु को ठग रहा है. ऐसा ही कुछ हुआ तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पद्मश्री से सम्मानित तीरंदाज लिम्बाराम के साथ. लिम्बाराम का ही एक शिष्य तीरदांजी अकादमी खोलने के लिए पद्मश्री का प्रमाणपत्र और पांच लाख रुपये लेकर फरार हो गया. ज्योतिनगर थाना पुलिस के अुनसार तीरदांज लिम्बाराम ने अपने शिष्य प्रवीण शर्मा के खिलाफ हनुमानगढ़ में तीरदांजी अकादमी खोलने का झांसा देकर चार लाख रुपये नकद, एक लाख रुपये का चेक और पद्मश्री सम्मान में मिला प्रमाण पत्र हड़पने का मामला दर्ज करवाया है. रिपोर्ट के अनुसार लिम्बा राम से प्रशिक्षण ले रहे प्रवीण शर्मा ने वर्ष 2008 में अपने गुरु लिम्बाराम को हनुमानगढ़ में तीरदांजी अकादमी खोलने के लिए राजी कर जमीन खरीदने के लिए चार लाख रुपये और बाद में एक लाख रुपये का चेक ले लिया. पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि आरोपी प्रवीण शर्मा अकाडमी की मंजूरी के लिए वर्ष 2011 में लिम्बा राम से पद्मश्री का प्रमाण पत्र लेकर फरार हो गया. उन्होने बताया कि लिम्बाराम

ने अपने शिष्य का इंतजार किया ओर उससे सम्पर्क करने का प्रयास भी किया. थक–हार कर अपने शिष्य के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया है लिम्बाराम ने कहा कि वह तीरंदाजी सीखने के लिए आ रहा था. लिम्बाराम के अनुसार प्रवीण ने कहा कि गुरुजी हनुमानगढ़ में तीरंदाजी अकादमी खोलने के लिए सस्ती कीमत पर जमीन दिलवा दूंगा. मैंने उसकी मांग के अनुसार चार लाख रुपये नकद और एक लाख रुपये का चेक दे दिया. लिम्बा राम के कहा कि कुछ महीनों बाद उसने अकाड्दमी की मंजूरी के लिए मेरा पद्मश्री का प्रमाण पत्र मांगा जिसे मैंने दे दिया. तभी से वह नहीं मिल रहा है. आखिरकार मैं हार कर में पुलिस में मामला दर्ज करवाने को मजबूर हुआ हूं.■

सवाल पूछने पर टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर ने लगाई रोक

आईपीएल को लेकर सुप्रीमकोर्ट के कड़े तेवर ने बीसीसीआई के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं और मीडिया का सामना करने से भी डरे हुए हैं. भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर डॉक्टर आर.एन.बाबा ने इस मामले में सवाल पूछने पर रोक लगा दिया है और मीडिया से कह दिया है कि सिर्फ टी–20 वर्ल्ड कप से जुड़े सावल ही पूछे जाएं. भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बार फिर प्रेस कांफ्रेंस में नहीं आए. भारतीय मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर बाबा को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को मालूम है कि आईपीएल विवाद से जुड़े सवालों पर रोहित जवाब नहीं दे सकेंगे. रोहित ने कहा कि मेरा पूरा फोकस टी–20 वर्ल्ड कप पर है. विदेशी पत्रकारों ने रोहित से जरूर पूछा कि क्या भारत में हुए घटनाक्रम का टीम पर असर पड़ेगा. इस पर रोहित ने कहा कि हमारा काम खेल पर फोकस करना है. हम यहां आईपीएल जीतने आए हैं. फिलहाल हमारा फोकस उसी पर है. यह पूछने पर कि क्या खिलाड़ियों ने आपस में इस बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि नहीं मैंने कहा ना कि हमारा फोकस सिर्फ टी–20 वर्ल्ड कप पर है.

भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और इंडिया सीमेंट्स के उपाध्यक्ष धोनी का इस मामले से सीधा ताल्लुक है, लेकिन वह अनिवार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए. डॉक्टर बाबा ने बाद में कहा कि अब से धोनी भारत के हारने के बाद ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे.■

अजय माकन का समर्थन नहीं करेंगी मैरीकॉम

वर्ल्ड चैपिंयन मुक्केबाज मैरीकॉम ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय माकन का समर्थन करने से मना कर दिया है. मैरीकॉम ने कहा कि पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री के बारे में उनका बयान बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं था. माकन के चुनाव अभियान में रेडियो जिंगल और वीडियो क्लिप शामिल हैं, जिसमें मैरीकॉम सहित विभिन्न खिलाड़ी खेल मंत्री के तौर पर उनके द्वारा किए काम की बात कर रहे हैं. भारतीय चुनाव आयोग ने मैरीकॉम को पत्र जारी कर कहा था कि वह भविष्य में किसी राजनीतिक व्यक्ति से न जुड़ें और राजनीतिक पार्टी की सदस्य न बनें. मैरीकॉम भारतीय चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकॉन हैं. ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरीकॉम ने अपने जवाब में कहा कि उनका इरादा बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं था, लेकिन वह एक व्यक्ति के तौर पर मंत्री के रूप में माकन के कार्य की सराहना कर रही थीं.■

कोहली तोड़ेंगे सबसे ज्यादा रिकार्ड

भारतीय पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनते जा रहे विराट कोहली विश्व क्रिकेट में किसी अन्य क्रिकेटर से ज्यादा रिकॉर्ड बनाएंगे. कपिल का कहना है कि यदि कोहली चोटों से दूर रहते हैं तो सचिन तेंदुलकर के करियर ग्राफ से भी बेहतर कर सकते हैं. कपिल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोहली किसी दूसरे खिलाड़ी से ज्यादा रिकॉर्ड बनाएंगे. मैं तुलना नहीं करता. जैसे दूसरा डॉन ब्रैडमैन नहीं हो सकता है उसी तरह दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, लेकिन हां कोहली में अपार प्रतिभा है. यह 24 वर्ष उम्र के खिलाड़ी को देखते हुए शानदार है और शायद वह तेंदुलकर के रिकॉर्ड से बेहतर कर सकता है. अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से बेहतर होना ही चाहिए. उन्होंने कहा कि कोहली ने दिखा दिया है कि उसमें किसी अन्य से ज्यादा काबिलियत और प्रतिभा है. अगर वह 32 या 34 वर्ष तक इसी फिटनेस के साथ और बिना चोटों के खेलता है, तो वह उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां, न तो विवियन रिचडर्स और न ही सचिन तेंदुलकर के नाम कोई रिकॉर्ड होगा.■

वर्ल्ड कप तक नियमों में कोई बदलाव नहीं

रिचडर्सन ने कहा कि 2015 वर्ल्डकप तक नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने खासकर चार फिल्डर्स के नियमों को लेकर कहा था कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कभी–कभार बिना पावरप्ले वाले ओवरों में चार फील्डर्स के सर्कल के बाहर खड़े होने के मौजूदा वनडे नियम के बारे में शिकायत की थी, लेकिन आईसीसी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2015 वर्ल्ड कप के अंत तक नियमों में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है. आईसीसी के मुख्य कार्यकारी डेव रिचड्र्सन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम वर्ल्ड कप से पहले किसी भी बदलाव पर विचार नहीं करने जा रहे हैं. वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी क्रिक्रेट समिति दोबारा इन नियमों की समीक्षा करेगी. जैसा कि मैंने कहा कि हम 50 ओवर के मैच को और आक्रामक बनाना चाहते थे, ताकि यह टी–20 क्रिकेट के रोमांच से प्रतिस्पर्धा कर सके. यह पूछने पर कि यह नियम बॉलर्स के लिए एक तरह से काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है तो उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ बॉलर अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं.

साउथ अफ्रीका के लिए 42 टेस्ट और 122 वनडे मैच खेलने वाले रिचडर्सन ने कहा यह कहना जल्दबाजी होगी. मुझे लगता है कि गेंदबाजी और फील्डिंग के पहलू को देखते हुए इससे मैच में आक्रामकता बढ़ी है. हां, रन प्रति ओवर भले ही बढ़ गए हैं और सपाट पिच पर कभी कभार बॉलर्स को भी काफी मुश्किल होती है. लेकिन सर्वश्रेष्ठ बॉलर अब भी बॉलिंग में शीर्ष पर है और सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष पर हैं. हमें सिर्फ अपनी धारणाओं में बदलाव करने की जरुरत है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भूत से नहीं, इंसानों से डरती हैं सनी

पोर्न स्टार के रूप में प्रसिद्धि पाने के बाद बॉलीवुड में प्रवेश करने वाली सनी लियोन अब अच्छा अभिनय कर दर्शकों का दिल जीतना चाहती हैं. हाल में रिलीज उनकी फिल्म रागिनी एमएमएस-2 में उनके काम और ख़ूबसूरती को ख़ूब सराहा जा रहा है. इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना-बेबी डॉल...काफी पसंद किया गया. सनी को उम्मीद है कि उन्हें बॉलीवुड में धीरे-धीरे मेनस्ट्रीम भूमिका वाली फिल्में मिलेंगी.

सन्नी का असली नाम केरेन मल्होत्रा है. पोर्न फिल्मों में करियर बनाने से पहले सनी एक जर्मन बेकरी जिफ्फी लुब में काम करती थीं. उसके बाद वह एक पैसा निवेश करने वाली कंपनी में काम करने लगीं, पर सनी को उस काम में मजा नहीं आया. ऑरेंज काउंटी में नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान वह अपनी एक डांसर फ्रेंड के संपर्क में आईं. उस फ्रेंड ने सनी को एक एजेंट जॉन स्टीवंस से मिलाया. जॉन ने सनी की मुलाकात जे एलेन से कराई. एलेन पेंटहाउस मैगज़ीन में चित्रकार थे, जहां उन्हें पोर्न फिल्मों में काम करने की प्रेरणा मिली. केरेन ने पोर्न फिल्मों के लिए अपना नाम सनी चुना. लियॉन नाम बाद में उन्हें बॉब ग्सियोनी ने दिया, जो पेंटहाउस के पूर्व मालिक थे. सनी पॉपुलर टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस से सुर्ख़ियों में आईं. उन्हें पहला ब्रेक महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जिस्म-2 में दिया. इस फिल्म में सनी लियोन ने जमकर अंग प्रदर्शन किया. उनकी दूसरी फिल्म है जैकपॉट. हालांकि, रागिनी एमएमएस-2 में उन्होंने पहले की फिल्मों की तुलना में बेहतर अभिनय किया है.

36 वर्षीय सनी लियोन ने लंबे समय तक ब्वॉयफ्रेंड रहे डेनियल से शादी कर ली. डेनियल और सनी एक पार्टी में मिले थे और डेनियल को उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया. डेनियल ने सनी से कई बार मिलने के लिए कहा, लेकिन सनी उन्हें लगातार नज़रअंदाज करती रहीं. बहुत मिन्नतें करने के बाद वह डेनियल से मिलने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन निर्धारित जगह पर वह काफी देर से पहुंचीं, क्योंकि उन्हें तब डेनियल में कोई दिलचस्पी नहीं थी. कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि डेनियल ही वह इंसान हैं, जिनके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हैं. दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक पल भी एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते. डेनियल ने भी अपने करियर की शुरुआत एडल्ट फिल्मों से की थी और अब वह एडल्ट फिल्में प्रोड्यूस करते हैं. डेनियल एवं सनी अच्छे दोस्त है, बिजनेस पार्टनर हैं और पति-पत्नी भी.

डेनियल सनी के बिजनेस, शेड्यूल, शूटिंग, प्रमोशन एवं इवेंट्स देखते हैं और इन मौक़ों पर सनी के साथ रहते हैं. सनी मानती हैं कि डेनियल से शादी करना उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़ूबसूरत पल था. डेनियल कहते हैं कि पोर्न स्टार से शादी करना एक बड़ा फ़ैसला है, लेकिन उन्हें कोई ऐतराज नहीं है कि उनकी बीवी एक पोर्न स्टार है. वह सनी के लिए काफी प्रोटेक्टिव हैं. सनी कहती हैं कि डेनियल की राय उनके लिए काफी मायने रखती है. वह डेनियल से स्क्रिप्ट और किरदार पर डिस्कस करने के बाद ही कोई फ़ैसला लेती हैं. सनी कहती हैं कि हम चौबीसों घंटे साथ होते हैं, हम एक-दूसरे के बिना रहने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते. डेनियल की मौजूदगी सनी को एनर्जी देती है और वह काम पर ज़्यादा फोकस कर पाती हैं. उनकी फिल्म रागिनी एमएमएस-2 भूत-प्रेत की कहानी है, पर सनी कहती हैं कि वह भूत-प्रेत पर यकीन नहीं करतीं, लेकिन उन्हें मानने से इंकार भी नहीं करतीं. रीयल लाइफ में वह भूत-प्रेत से ज़्यादा इंसानों से डरती हैं. वह कहती हैं कि आपके साथ रहने वाले इंसान के मन में क्या छिपा है, उसे आप कभी नहीं समझ सकते. बॉलीवुड में वह आमिर की बहुत बड़ी फैन हैं. वह कहती हैं कि उन्हें बचपन से ही दूसरों की सेवा करना अच्छा लगता है. अगर वह अभिनेत्री नहीं होतीं, तो नर्स होतीं. सनी लियोन गोलगप्पों की बहुत शौकीन हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

डेनियल सन्नी के बिजनेस, शेड्यूल, शूटिंग, प्रमोशन एवं इवेंट्स देखते हैं और इन मौक़ों पर सन्नी के साथ रहते हैं. सन्नी मानती हैं कि डेनियल से शादी करना उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़ूबसूरत पल था. डेनियल कहते हैं कि पोर्न स्टार से शादी करना एक बड़ा फ़ैसला है, लेकिन उन्हें कोई ऐतराज नहीं है कि उनकी बीवी एक पोर्न स्टार है. वह सन्नी के लिए काफी प्रोटेक्टिव हैं.

36 वर्षीय सन्नी लियॉन ने लंबे समय तक ब्वॉयफ्रेंड रहे डेनियल से शादी कर ली. डेनियल और सन्नी एक पार्टी में मिले थे और डेनियल को उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया. डेनियल ने सन्नी से कई बार मिलने के लिए कहा, लेकिन सन्नी उन्हें लगातार नज़रअंदाज करती रहीं. बहुत मिन्नतें करने के बाद वह डेनियल से मिलने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन निर्धारित जगह पर वह काफी देर से पहुंचीं, क्योंकि उन्हें तब डेनियल में कोई दिलचस्पी नहीं थी. कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि डेनियल ही वह इंसान हैं, जिनके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हैं.

किताब लिखेंगी दिव्या

पत्रकार एवं लेखक ख़ुशवंत सिंह का पिछले दिनों 99 साल की अवस्था में निधन हो गया. अपने बेबाक लेखन के लिए मशहूर रहे ख़ुशवंत सिंह की किताब-ट्रेन टू पाकिस्तान पर बनी फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कुछ समय पहले उनसे मुलाकात की थी. दिव्या कहती हैं कि वह अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे और उनसे हुई मुलाकात वह कभी भुला नहीं पाएंगी. दिव्या बताती हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान के बाद से ख़ुशवंत सिंह से उन्हें गहरी आत्मीयता हो गई थी. कुछ महीने पहले दिव्या ख़ुशवंत सिंह से मिलने खास तौर से मुंबई से दिल्ली आई थीं, तब उनकी उनसे काफी बातें हुईं. बकौल दिव्या, वह एक जिंदादिल इंसान थे, उन्होंने मुझे तोहफे में एक किताब भी दी, जिस पर एक ख़ूबसूरत संदेश लिखा था. मेरे लिए वह एक ख़ास और अमूल्य तोहफा है. दिव्या अब एक किताब लिखने वाली हैं. वह यह किताब ऐसे कई किस्से जुटाकर लिखेंगी, जो उन्होंने ख़ुशवंत सिंह से हुई मुलाकातों के दौरान सुने, देखे और समझे. वह कहती हैं, हमने राजनीति से लेकर जीवन दर्शन तक, हर विषय पर बात की और ख़ुशवंत सिंह ने जीवन के प्रति एक अलग नज़रिया विकसित करने में मेरी मदद की. ■

स्कैम का पर्दाफ़ाश करेंगे पुलकित

छोटे पर्दे के कई सितारों ने बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का लोहा मनवाया. छोटे पर्दे के एक और सितारे हैं पुलकित सम्राट, जो आजकल बड़े पर्दे पर धमाल मचा रहे हैं. पुलकित एकता कपूर के लोकप्रिय धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की. बिट्टू बॉस के बाद फुकरे में उनके काम की काफी सराहना हुई. इसके बाद वह सलमान की जय हो, में भी नजर आए. अब वह सलमान की बहन अलवीरा के पति अतुल अग्निहोत्री की फिल्म ओ तेरी, में नजर आएंगे. दरअसल, सलमान ने अतुल को कॉमनवेल्थ घोटाले पर फिल्म बनाने को कहा. अतुल को सलमान का आइडिया अच्छा लगा और बना डाली फिल्म ओ तेरी. अब सलमान के घर की फिल्म हो तो स्वाभाविक है कि पुलकित को कोई न कोई रोल तो मिल ही जाएगा. दरअसल, पुलकित सलमान की मुंहबोली बहन के ब्वॉयफ्रेंड हैं. वह ख़ुद को ख़ुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें सलमान का सपोर्ट मिला हुआ है. पुलकित की 2013 में रिलीज फिल्म फुकरे हिट हो चुकी है. वह मानते हैं कि फुकरे की सफलता से उन्हें फायदा हुआ. ओ तेरी में पुलकित का किरदार एक टीवी जर्नलिस्ट प्रताप का है. उनके साथ हैं ख़ोजी रिपोर्टर आनंद उर्फ एड्स (बिलाल अमरोही). दोनों रातोंरात किसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं. इस चाहत में वे हर दिन बेतुकी और बिना सिर-पैर की ख़बरों को शूट करके चैनल हेड मॉनसून (सारा जेन डियास) के सामने पेश करते हैं. मॉनसून इनकी बिना सिर-पैर की रिर्पोटिंग से तंग आकर उन्हें जॉब से निकाल देती है. अब वे किसी ऐसे ख़बर कि तलाश में हैं, जो उनकी नौकरी वापस दिला सके. तभी कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान बन रहे एक ब्रिज के टूटने घटना उनके सामने आती है. वे इस घोटाले को उजागर करने में लग जाते हैं. इस किरदार में जीवंतता लाने के लिए पुलकित ने दिल्ली के कई टीवी जर्नलिस्ट की लाइफ को रीड किया. वह इस भूमिका में छोटे-मोटे ख़बरों के पीछे भागते दिखाई देंगे, पर अनजाने में वह एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करते नजर आएंगे. ■

हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए

गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री नंदा 25 मार्च की सुबह बाथरूम में गश खाकर गिर पड़ीं और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई. फिल्मों में सह-अभिनेत्री की भूमिकाओं में उन्हें काफी पसंद किया गया. उनकी पहचान छोटी बहन के रूप में थी, लेकिन बाद में वह मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्में करने लगीं. नंदा ने शादी नहीं की और अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार के साथ ही बिता दी. हालांकि, अधेड़ उम्र में उस जमाने के सफलतम फिल्मकार मनमोहन देसाई को उनसे प्यार हुआ. दोनों की पसंद-नापसंद अलग होते हुए भी मनमोहन देसाई ने उनका मन अंततः जीत लिया. 1992 में क़रीब 53 साल की उम्र में नंदा और देसाई ने शादी का फ़ैसला किया, लेकिन सगाई के कुछ समय बाद ही देसाई ने छत से कूद कर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या की वजह यह मानी गई कि देसाई लंबे समय से कमरदर्द से परेशान थे, लेकिन वह स्थायी इलाज के लिए शल्य चिकित्सा कराने को तैयार नहीं हो रहे थे. कहा यह भी जाता है कि उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं और वह वीडियो की चोरी से भी आहत थे. उन्हें लगता था कि एक दिन फिल्म उद्योग ख़त्म हो जाएगा. शायद इसीलिए उन्होंने अमर-अकबर-एंथोनी के राइट्स बेच दिए. 8 जनवरी, 1939 को मुंबई में जन्मी नंदा के पिता मास्टर विनायक मराठी रंगमंच के लोकप्रिय कलाकार थे. पिता विनायक चाहते थे कि उनकी बेटी अभिनेत्री बने, लेकिन नंदा की अभिनय में दिलचस्पी नहीं थी. वह सेना में जाना चाहती थीं. पिता के बहुत कहने पर वह एक फिल्म में लड़का बनने को तैयार हुईं. पिता की मृत्यु के बाद घर की ज़िम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं और फिर न चाहते हुए भी उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा. उनके अंकल थे उस जमाने के मशहूर फिल्मकार वी शांताराम. शांताराम ने अपनी फिल्म दीया और तूफान में नंदा को कास्ट किया. युवावस्था में नंदा ने दक्षिण भारत के एक सुपर स्टार राजेंद्र कुमार अभिनीत एक फिल्म में छोटी बहन की भूमिका निभाई. नंदा ने पिता के बाद अपनी परिवारिक ज़िम्मेदारियां बख़ूबी निभाईं. कुछ दिनों पहले ही कैंसर से पीड़ित उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी. नंदा ने लंबे समय तक अपनी बीमार बहन की सेवा की. भाई जयप्रकाश का करियर संवारने में, उन्हें निर्देशक बनाने नंदा का विशेष योगदान रहा. अपने करियर के सुनहरे दौर में उन्होंने पाली हिल बांद्रा, मुंबई में भव्य बंगला बनाया था, लेकिन परिवार की ज़रूरतें पूरी करने की ख़ातिर उसे बेचकर वह वरसोवा के फ्लैट में रहने लगीं. नंदा ने किसी एक छवि में बंधकर काम नहीं किया. यश चोपड़ा की राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने अपने पति का कत्ल करने वाली बेवफा पत्नी की भूमिका निभाई. उन्होंने अधिकतर बहन या प्रेमिका की भूमिकाएं कीं. नंदा ने 60-70 के दशक में कई सफल फिल्में कीं. उन्होंने देव आनंद के साथ काला बाज़ार, हम दोनों एवं तीन देवियां, शशि कपूर के साथ नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे एवं जब-जब फूल खिले और राजेश खन्ना के साथ द ट्रेन समेत कई यादगार फ़िल्मों में काम किया. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

07 अप्रैल-13 अप्रैल 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

बिहार – झारखंड

भारी पड़ेगी नाराजगी

जब अपने ही रूठ कर साथ छोड़ने लगते हैं तो किसी भी दल के लिए मुश्किल की अवस्था आ जाती है. बिहार में प्रत्येक दल अपनों की नाराजगी से परेशान है. सत्ताधारी जदयू भी इसकी चपेट से बाहर नहीं है. पार्टी के कई बड़े नेता बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं. सभी की अपनी-अपनी परेशानियां हैं. वहीं भाजपा और राजद भी अपने नेताओं के क्रोध से अछूते नहीं हैं. बगावत करने वाले नेता दूसरे दलों का दामन भी थाम रहे हैं.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

बिहार की चालीस लोकसभा सीटों के लिए हर दल ने अपने सूरमाओं का ऐलान तो कर दिया पर इस प्रकिया में बड़े और ताकतवर नेताओं की उपेक्षा ने इन दलों को कई सीटों पर भारी संकट में डाल दिया है. चुनाव प्रचार चरम पर है और ऐसे में इन रूठे नेताओं की बयानबाजी से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. स्वाभाविक तौर पर इसका पूरा फायदा विरोधी उठा रहे हैं और चुनावी समर में अपनी पैठ गहरी कर रहे हैं. अभी सबसे ज्यादा घमासान सत्ताधारी दल जदयू में मचा है. नीतीश सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह, वृषिण पटेल और रमई राम के अलावा पूर्व सांसद साबीर अली और मोनाजिर हसन अलग-अलग कारणों से बेहद खफा हैं जिसका बुरा असर पार्टी के चुनाव प्रचार पर हो रहा है. गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह नहीं चाहते थे कि जमुई से स्पीकर उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ें. लेकिन उदय नारायण चौधरी की जिद के कारण नीतीश कुमार ने नरेंद्र सिंह की भावनाओं का ख्याल नहीं किया और उदय को प्रत्याशी बना दिया. अपनी जन्मभूमि और राजनीतिक कर्म भूमि में उपेक्षा से नरेंद्र सिंह बेहद खफा हो गए. पार्टी के हित में उन्होंने गुस्से को चुपचाप पी जाना ही बेहतर समझा, लेकिन जदयू के ही कई नेता इनकी इस चुप्पी को घोखेबाजी समझने लगे. पटना दरबार में भी यह बात पहुंचाई जाने लगी कि नरेंद्र सिंह चुनाव के मौके पर धोखा कर सकते हैं. बताया जाता है कि इस तरह की खबरों से नरेंद्र सिंह बेहद आहत हो गए और उनके सब्र का बांध जमुई के खैरा में मुख्यमंत्री की सभा में टूट गया. भरी सभा में नरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि धोखा देना मेरे संस्कार में नहीं है मुख्यमंत्री जी. मैं जो करता हूं सीना ठोंक कर सामने से करता हूं. उन्होंने कहा, नीतीश जी आप जान लीजिए जिस दिन मैं विरोध कर दूंगा उस दिन आपके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी.

अगर आप हार गए तो मेरे माथे पर बेल मत फोड़िएगा. मेरे खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है. लोग उदय नारायण चौधरी को नक्सलवादी कह रहे हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र सिंह के आवास पर उन्हें मनाने गए थे. बताया जाता है कि नरेंद्र सिंह मान भी गए थे पर कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को यह समझाने का प्रयास किया कि नरेंद्र सिंह पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लान बी तैयार रखना होगा. दरअसल नरेंद्र सिंह इसी प्लान बी से भड़क गए. गौरतलब है नरेंद्र सिंह जमुई लोकसभा क्षेत्र के सबसे मजबूत नेता हैं और उनके दो पुत्र सुमित सिंह चकाई से और अजय प्रताप जमुई से विधायक हैं. इसके अलावा प्रदेश भर में राजपूत बिरादरी में नरेंद्र सिंह की काफी इज्जत है. यह सभी जानते हैं कि आज भी ऑफ द रिकार्ड जदयू के बहुत सारे विधायक नरेंद्र सिंह को अपना नेता मानते हैं खासकर राजपूत विधायकों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है. नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की सभा में खुली चुनौती देकर मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार का ही जोर नहीं चलता है.

दूसरी तरफर नरेंद्र सिंह ने आगे की राजनीति के लिए अपने को सबसे आगे खड़ा कर दिया. सभा में नरेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगे इससे यह बात भी साफ हो गई कि नीतीश कुमार का करिश्मा कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है और उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता अब खुलकर अपनी बात रखने में झिझक नहीं रहे हैं. जान-अनजाने नरेंद्र सिंह की इस बेबाकी का सीधा चुनावी फायदा जमुई से लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान को मिल रहा है. नरेंद्र सिंह समर्थक मतदाताओं को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र सिंह की उपेक्षा कर उदय नारायण चौधरी को टिकट दे दिया. ऐसे में अपने नेता के मान सम्मान के लिए वे न चाहते हुए भी चिराग पासवान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं. कोई खुलकर तो कोई परदे की पीछे से इस काम में लगा नजर आ रहा है. नरेंद्र सिंह की नाराजगी का असर बगल की बांका सीट पर दिखाई पड़ रहा है. राजपूत मतदाता पहले से ही पुतुल सिंह के साथ थे और अब नरेंद्र सिंह के नए प्रकरण के बाद तो वे पूरी आक्रमकता से भाजपा प्रत्याशी के साथ हो गए हैं. बिहार की दूसरी सीटों पर भी इसका असर देखा जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि समय रहते नीतीश कुमार कैसे अपने इस बड़े नेता को मना पाते हैं.

रमई राम

साबिर अली

वृषिण पटेल

> **नीतीश सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह, वृषिण पटेल और रमई राम के अलावा पूर्व सांसद साबीर अली और मोनाजिर हसन अलग-अलग कारणों से बेहद खफा हैं जिसका बुरा असर पार्टी के चुनाव प्रचार पर हो रहा है. गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह नहीं चाहते थे कि जमुई से स्पीकर उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ें. लेकिन उदय नारायण चौधरी की जिद के कारण नीतीश कुमार ने नरेंद्र सिंह की भावनाओं का ख्याल नहीं किया और उदय को प्रत्याशी बना दिया.**

इससे पहले पूर्व राज्यसभा सदस्य और शिवहर से जदयू के प्रत्याशी साबिर अली ने नीतीश कुमार की मुस्लिम वोट पाने की हसरत में पलीता लगा दिया. सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने साबिर अली को दोबारा राज्यसभा भेजने का वायदा किया था लेकिन अपने कुछ सलाहकारों की बात मान उनका टिकट काट दिया और शिवहर से उन्हें चुनाव लड़ने का फरमान सुना दिया. नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि मैंने पांच बार साबिर अली से पूछा कि आप शिवहर से लड़ेंगे या नहीं? साबिर ने एक बार भी मना नहीं किया. टिकट लेकर दिल्ली में बैठ गए. हमें लग गया कि दाल में कुछ काला है, इसलिए टिकट वापस ले लिया गया. इस मामले पर साबिर अली का कुछ अलग ही नजरिया है. वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे साथ धोखा किया है. मुझे राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया गया पर टिकट काट दिया गया क्योंकि मैं मुसलमान का बेटा हूं. अगर मैं भी जाति से कुर्मी होता तो मेरा टिकट नहीं कटता. साबिर अली ने नीतीश कुमार के खासमखास आर-सीपी सिंह पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि दलाली का कारोबार चरम पर है. अगर आरसीपी सिंह की घर की तलाशी ली जाए तो कम से कम पांच सौ करोड़ मिलेंगे. साबिर अली ने कहा कि मैंने पार्टी से कुछ लिया नहीं बल्कि पार्टी को कुछ दिया ही है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सिस्टम को दोषी बताते हुए परवीन अमानुल्लाह ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले जमशेद असरफ ने भी इस्तीफा दिया था. मोनाजिर हसन को टिकट न देने का मामला भी तूल पकड़ रहा है. शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ बस धोखा करते हैं. मोनाजिर हसन को टिकट नहीं देकर उन्होंने यह बात साबित भी कर दी. गौरतलब है कि मोनाजिर बेगूसराय से चुनाव टिकट चाहते थे पर गठबंधन के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी.

लेकिन बताया जा रहा है कि मोनाजिर चुप नहीं बैठे हैं बल्कि अपने हिसाब से अपनी चाल चल रहे हैं. शिवहर ऐसे भी जदयू के लिए कठिन सीट थी अब ऐन मौके पर साबिर के हट जाने के बाद तो यहां की राह और भी दुरुह हो गई है. शिवहर की सीट का सीधा असर सीतामढ़ी पर भी पड़ रहा है. यहां के मुसलमान मतदाता भी अब उहापोह की स्थिति में आ गए हैं. इसी तरह नीतीश सरकार के दो और बड़े मंत्री रमई राम और वृषिण पटेल अब अपना ही राग अलाप रहे हैं. वृषिण पटेल ने तो एक बार इस्तीफा देने का मन भी बना लिया था लेकिन बाद में संभलते हुए कहा कि वह वैशाली में प्रचार नहीं करेंगे. यही हाल रमई राम का भी है. हाजीपुर से टिकट के लिए आश्वस्त थे पर ऐन मौके पर निराशा हाथ लगी. सभी जानते हैं कि रमई राम चुप बैठने वाले नहीं है. रमई राम व वृषिण पटेल की नाराजगी वैशाली व तिरहुत के इलाके में जदयू को काफी नुकसान पहुंचा रही है. यही हाल राजद का भी है.

रामकृपाल यादव के खफा होने से यादवों में काफी प्रतिक्रिया है. रामकृपाल अब लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के खिलाफ खड़े हैं. इसी तरह रामबदन राय को मुंगेर का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और मुंगेर से खड़े हो गए. काराकाट में सत्यनारायण यादव ने राजद प्रत्याशी कांति सिंह को परेशान कर दिया है. सत्यनारायण यादव की अपने समाज में गहरी पैठ है और वे जितना मजबूत हो रहे हैं कांति सिंह की स्थिति उतनी ही कमजोर हो रही है. इसका सीधा फायदा रालोसपा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को मिलता नजर आ रहा है. अपने नेताओं की नाराजगी भाजपा भी झेल रही है. अवनीश सिंह ने जदयू का दामन थाम लिया और मोतिहारी से कूद पड़े. भाजपा के राधामोहन सिंह इस कारण परेशानी में हैं. इसी तरह लाल मुनी चौबे के कारण बक्सर में अश्विनी चौबे को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. चंद्र मोहन राय की नाराजगी भी भाजपा को खल रही है. देखा जाए तो हर दल अपने नेताओं की नारजगी से परेशान है. अब यह पार्टी के आलाकमान पर है कि वे कैसे इस नारजगी से हो रहे नुकसान की भरपाई कर पाते हैं. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर चुनावी राह का बेहद कठिन होना तय है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

बच्चों का घोषणा पत्र जारी

पिछले दिनों पटना के यूथ हॉस्टल में शोषण मुक्ति अभियान के तहत बच्चों का जन घोषणा पत्र जारी किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना जेजे बोर्ड के पूर्व सदस्य केडी मिश्रा ने की. अभियान के संयोजक सुदामा सिंह ने इस दौरान कहा कि सत्ता पक्ष और साथ ही विपक्ष को भी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों की संख्या चालीस प्रतिशत है लेकिन उनकी संख्या के हिसाब से बजट में उन्हें स्थान नहीं मिलता है. साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए जो कानून बनाया गया है, उसे अच्छी तरह लागू भी नहीं किया जा रहा है. शोषण मुक्ति अभियान ने सभी लोकसभा क्षेत्र में बैठक कर बच्चों, महिलाओं व आम जनता के सहयोग से जन घोषणा पत्र तैयार किया है. कार्यक्रम में सभी दल के प्रतिनिधि मौजूद थे. वक्ता के रूप में सेव द चिल्ड्रेन के विपिन कुमार, तारकेश्वर सिंह, ज्योतिमणि, मुख्तारुल हक, अरुण दास, राकेश, उमेश, गीरी बाबू, लक्खी कुमारी, नेहा, बिट्टू, प्रेम, विक्की आदि उपस्थित थे. धन्यवाद ज्ञापन संतेंद्र शांडिल्य ने किया.

– अमृता कुमारी

कार्यशाला आयोजित

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम खेती की समस्या व उसके उत्पादन में भारत में वृद्धि को लेकर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित प्रसार शिक्षा निदेशालय सभा भवन में दो दिवसीय एआईसीआरपी द्वारा 16वीं वार्षिक कार्यशाला–2014 का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि सेन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के कुलपति डॉ. एस.एन.पुरी ने मशरूम की उपयोगिता व इसके उत्पादन में किसानों, वैज्ञानिकों की तकनीकी जरूरतों पर प्रकाश डाला. वक्ताओं ने मशरूम को स्वास्थ्य वर्धक, आमदनी देने वाला बताया. बिहार में 2 से 3 हजार टन के बीच मशरूम की खेती होती है. मशरूम को शाकाहारी भोजन बताते हुए सोलन के डीएमआर डायरेक्टर डॉ. मंजीत सिंह ने कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल तैयार की जाएगी. मशरूम में वी कॉम्प्लेक्स व विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. बिहार सरकार द्वारा किसानों को मशरूम उत्पादन में सहयोग करने के लिए वैज्ञानिकों ने सराहना की. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉ. आर. के. मित्तल ने मशरूम उत्पादन में विश्वविद्यालय द्वारा शोध पर विशेष ध्यान दिए जाने का भरोसा दिलाया. आगत अतिथियों का स्वागत डायरेक्टर रिसर्च डॉ. वी. पी. सिंह ने किया. कार्यशाला सभा का संचालन प्रियंका पासवान ने किया. धन्यवाद ज्ञापन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दयाराम ने किया. मौके पर 16 केन्द्रों से आए 30 मशरूम वैज्ञानिक, 35 प्रगतिशील उद्यमी, डॉ. ओ.पी. सिंह, डॉ. टी.एन. लखनपाल इत्यादि उपस्थित थे. मुख्य अतिथि डॉ. एस.एन. पुरी ने पुरुष एवं महिला उद्यमियों द्वारा उद्यान भवन में लगाई गई मशरूम प्रदर्शनी को भी देखा.

– यशवंत कुमार सिंह

आप का सम्पर्क अभियान

आम आदमी पार्टी की स्वराज संदेश यात्रा के तहत डॉ. विवेकानंद के द्वारा परबत्ता में सदस्यता अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि अररिया गांव, गोगरी बाजार, देवरी गांव तक आलम बाजार में भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने लोगों को स्वराज की जानकारी दी. इस अवसर पर पंचानंद यादव, बबलू कुमार, नेपाली सिंह सहित अनेकों लोग थे.■

अपने ही बिगाड़ेंगे खेल

बैठक में राजद प्रत्याशी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता

वाल्मीकि कुमार

लोकसभा चुनाव सिर पर है. दलों के घोषित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने संबंधित क्षेत्र का सघन दौरा भी शुरू कर दिया है. लेकिन बिहार की तमाम लोकसभा सीटों में दो सीट ऐसी भी हैं, जहां चुनाव की तारीख इतनी नजदीक होते हुए भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है. अब तक के इतिहास में शायद पहला मौका है, जब सीतामढ़ी व शिवहर लोकसभा क्षेत्र में कुछ दलों के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा करना पहेली बना हुआ है. शिवहर लोकसभा सीट के दृश्य तो फिलहाल सबसे रोचक दिख रहे हैं. यहां से जदयू के घोषित प्रत्याशी ने चुनाव से अपने को अलग कर लिया है. जदयू के टिकट पर चुनावी समर में पहुंचे साबिर अली के लिए भाजपा का गुणगान करना महंगा पड़ गया है. आलम यह है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें निष्कासित तक कर दिया है. अब मुख्यमंत्री के तरकश का कौन सा तीर शिवहर सीट पर निशाना साधने में कामयाब होता है, सभी को इसका इंतजार है. जहां तक भाजपा की बात है तो स्थानीय सांसद रमा देवी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं. वहीं राजद गठबंधन के तहत घोषित प्रत्याशी व पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक का दावा है कि इस चुनाव में जाति-पार्टी गौण है. मतदाता ने चुनाव में हिंदू-मुसलमान नहीं ईमानदार बन कर मतदान करने की ठान ली है. आलम है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पक्ष में मतदाताओं की एकजुटता अकल्पनीय है. 25 मार्च को सीतामढ़ी शहर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ललित आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जो गठबंधन दल के लिए संजीवनी का काम किया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजद जिलाध्यक्ष मो. शफीक खां, पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मनीष कुमार, प्रदेश कांग्रेस संगठन सचिव मो. परवेज आलम अंसारी, मो. असद, मो. मोबीनुल हक, विजेंद्र यादव, राज कुमार साह, कौशल किशोर यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ताराकांत झा, मणि भूषण कुमार, राजेश राठौर, शिव शंकर शर्मा, रामबाबू साह, सीमा गुप्ता, रानी देवी, चंद्रजीत प्रसाद यादव व अंजारुल हक तौहीद समेत अन्य थे. बैठक में सीतामढ़ी सीट के राजद प्रत्याशी व पूर्व सांसद सीताराम यादव एवं शिवहर से मो. अनवारुल हक के पक्ष में कांग्रेस व राकांपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट रहने का संकल्प लिया. सीतामढ़ी क्षेत्र के प्रत्याशी सीताराम यादव ने गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं से हुए गलती के लिए क्षमा याचना की. इस दौरान राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही ने दोनों ही क्षेत्र के प्रत्याशी को चुनावी नसीहत दी. कुल मिलाकर राजद गठबंधन ने हर हाल में दोनों ही जिलों में लालटेन की लौ जगमग करने का संकल्प लिया. इधर, नमो लहर की चर्चा पर लोगों का कहना है कि सीतामढ़ी सीट को रालोसपा नेतृत्व ने अधर में लटकाने का काम किया है. नतीजा है कि यह सीट भाजपा गठबंधन की झोली में जाने का रास्ता फिलहाल संकट में घिर गया है. कारण कि सीतामढ़ी जिला भाजपा की चुप्पी के बीच रालोसपा एवं लोजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है. रालोसपा के प्रदेश सचिव आफताब अंजुम बिहारी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहीद अली अंसारी, युवा संसद के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार कुशवाहा एवं महासचिव सुनील कुमार कुशवाहा ने रालोसपा नेतृत्व पर नीति व सिद्वांत से भटकने का आरोप लगाते हुए अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं लोजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष मोहन झा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के पूर्व प्रधान महासचिव राघवेंद्र सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोजपा नेताओं को रालोसपा द्वारा तोड़ने का आरोप लगाते हुए निंदा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया है कि गठबंधन के तहत रालोसपा प्रत्याशी के किसी भी चुनावी कार्यक्रम का लोजपा कार्यकर्ता बहिष्कार करेगा. जहां तक जदयू प्रत्याशी व सांसद डॉ. अर्जुन राय का सवाल है तो उनको इस बार अपने ही स्वजातीय पूर्व सांसद नवल किशोर राय संकट में डाल सकते हैं. कारण कि सीतामढ़ी सीट से जदयू का टिकट नहीं मिलने के बाद नवल किशोर सीतामढ़ी से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेंगे. चर्चा है कि इसको लेकर गुप-चुप तरीके से पूर्व सांसद ने क्षेत्र का सघन दौरा भी शुरू कर दिया है. जबकि शिवहर में समाजवादी पार्टी से पहुंची पूर्व सांसद लवली आनंद ने सीट पर कब्जा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है.

वैसे चुनाव का समय करीब आने के साथ ही राजनीति की दशा व दिशा में बदलाव का संकेत भी मिलना स्वाभाविक है. परंतु इतना तो तय है कि सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो चुनावी पारी खेली है, वह वक्त के हिसाब से सही माना जा रही है. कारण कि जदयू एवं भाजपा गठबंधन आपसी खींचतान से उबर नहीं पा रही है. वहीं दूसरी ओर वर्षों से टिकट मिलने की आस लगाए कांग्रेस व राकांपा कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का प्रवाह शुरू हो गया है. गठबंधन दल के प्रत्याशी से कार्यकर्ता जीत के संकल्प के बदले में सम्मान की आस लगाए हैं. फिलहाल आलम यही है कि प्रत्याशी की ताल से मतदाताओं का ताल-बेताल होने लगा है. जबकि कांग्रेस-राकांपा अपने गठबंधन दल के प्रत्याशी की बहुमत को लेकर राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हैं. अब चुनावी बयार आने वाले दिनों में किस ओर का रुख अख्तियार कर किसका घर बसाती और किसको उजाड़ती है, मई महीने में ही साफ हो पाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

चतरा में कांटे की टक्कर के आसार

अमरेंद्र प्रताप सिंह

लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं. सभी दलों के प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं. चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय दलों में से भाजपा व कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है. वहीं क्षेत्रीय दलों में से आजसू, झाविमो, जदयू व बसपा ने भी अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. चतरा लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल प्रत्याशियों के चाल-चरित्र, उनसे संबंधित दल, प्रत्याशी बाहरी हैं या क्षेत्रीय यही चर्चा का मुख्य विषय है. बताते चलें कि शुरू से ही यहां की जनता बाहरी-भीतरी का मुद्दा अलाप रही है. कुछ दिन पहले तक कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता भी क्षेत्रीय उम्मीदवार की वकालत करते नजर आते थे. लेकिन चुनाव व नामांकन की तिथि घोषित होते ही सभी कार्यकर्ता अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने में जुट गए हैं.

बताते चलें कि भाजपा ने सुनील सिंह को व राजद-कांग्रेस गठबंधन ने धीरज साहु को मैदान में उतारा है. अबतक की तस्वीर बताती है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होना है. वहीं आजसू से चतरा के पूर्व सांसद नागमणि व झामुमो से नीलम देवी, जदयू से महेश सिंह यादव व सीपीएम से बनवारी साहु ने नामांकन कर दिया है. साथ ही कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ सकते हैं. स्थानीय लोगों के मन को टटोलने पर लगता है कि व राष्ट्रीय पार्टी यानि भाजपा या कांग्रेस में से ही किसी एक का चुनाव करेंगे. क्षेत्रीय पार्टियों में आजसू के नागमणि और झाविमो की नीलम देवी दोनों जातीय समीकरण में ही संभावना देख रहे हैं. नागमणि कोइरी-कुर्मी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं वहीं झाविमो

के द्वारा यादव मतदाता को गोलबंद करने की कोशिश जारी है. नागमणि की लाख कोशिशों के बाद भी यहां की जनता उनके दल-बदल वाले चरित्र को भूल नहीं रही है. सूत्र बताते हैं कि इसका खामियाजा नागमणि को भुगतना पड़ सकता है. वहीं झाविमो की नीलम देवी व सीपीएम के बनवारी साहु स्थानीय हैं और उनकी जमीनी पकड़ भी अच्छी मानी जाती है. लेकिन अबतक के हिसाब से जनता का झुकाव राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ही देखा जा रहा है. नमो की लहर के बावजूद कांग्रेस के धीरज साहु मजबूत दिख रहे हैं. धीरज पिछला लोकसभा महज कुछ मतों से हार गए थे. उन्हें यकीन है कि इसबार जनता उन्हें जरूर जिताएगी. प्रेक्षकों की मानें तो क्षेत्र का वैश्य वोट धीरज साहु के पक्ष में जा सकता है. वहीं मुसलमान मतदाताओं का झुकाव भी साहु की तरफ ही देखा जा रहा है. यही समीकरण भाजपा के लिये परेशानी खड़ी कर सकता है. जहां मुसलमानों का वोट निर्णायक माना जा रहा है. वहीं यादव जाति से तीन-तीन उम्मीदवार होने से यह वोट बैंक विखंडित होता नजर आ रहा है. प्रेक्षकों का भी मानना है कि इस बार लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

यादवी महाभारत में कैसर की अग्नि परीक्षा

दिनेश चन्द्र यादव | कृष्णा कुमारी यादव | चौधरी महबूब अली कैसर | डॉ. विवेकानन्द

मनेन्द्र कुमार

पिछले दिनों खगड़िया जिला पूरे सूबे में चर्चा का विषय बना रहा. वजह थे विधानसभा के सचेतक व परबत्ता के राजद विधायक राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी. उन्होंने बगावत कर जदयू का दामन थामा था. उसी समय से कयास लगाए जाने लगे थे कि सम्राट आगामी लोकसभा में जदयू के प्रत्याशी होंगे या उनके पिता शकुनी चौधरी को प्रत्याशी बनाया जाएगा. लेकिन शरद यादव की जिद के कारण एक बार फिर वर्तमान सांसद दिनेश चन्द्र यादव को ही उम्मीदवार बनाए जाने से तमाम नाटकीय मोड़ का पटाक्षेप हो गया. लेकिन क्या इस बार दिनेश यादव जदयू की नैया पार करने में सफल हो पाते हैं यह राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा का विषय बना हुआ है. उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा के मंत्री पद से इस्तीफे व उनके पति विजय कुशवाहा को मधेपुरा से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाये जाने से जदयू के सामने एक और संकट पैदा हो गया है. वहीं खगड़िया विधानसभा की जदयू विधायक पूनम देवी यादव द्वारा अपनी छोटी बहन के पक्ष मे समर्थन की घोषणा से इस क्षेत्र का लोकसभा चुनाव रोचक बन गया है. भाजपा-जदयू गठबंधन टूटने के बाद कई नेताओं के इधर से उधर जाने के मामले में खगड़िया भी अव्वल रहा है. वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर को लोजपा प्रत्याशी होने से लड़ाई आर-पार की नजर आती दिख रही है. वहीं कुशवाहा समुदाय से उम्मीदवार नहीं होने पर इस समुदाय में खासी मायूसी है लेकिन उपेन्द्र कुशवाहा का जादू इस क्षेत्र में भी चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है. बताते चलें कि खगड़िया लोकसभा गोप बहुल माना जाता है. इसलिए इस क्षेत्र से अधिकतर दल इसी समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं. लेकिन इस बार के चुनाव में नरेन्द्र मोदी की लहर कई दलों पर असर डाल रही है. बात थोड़ी बीते चुनाव की भी की जाय. मालूम हो कि इस क्षेत्र में छह विधानसभा क्षेत्र हैं. मसलन अलौली, खगड़िया, परबत्ता, बेलदौर, सहरसा जिले के सिमरीबख्तियारपुर तथा समस्तीपुर जिले का हसनपुर विधानसभा क्षेत्र. इन सभी क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी दिनेश चन्द्र यादव को बढ़त मिली थी. लेकिन इस बार राजद के द्वारा जिला पार्षद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को प्रत्याशी बनाए जाने से समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है. कृष्णा यादव के पति व पूर्व विधायक रणवीर यादव कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे लेकिन अपनी दूसरी पत्नी को टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने राजद का दामन थाम लिया. और लालू ने उनकी इच्छा पूरी भी की. परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए खगड़िया संसदीय क्षेत्र पर फिलहाल जदयू के दिनेश चन्द्र यादव का प्रतिनिधित्व है. उन्होंने राजद के रविन्द्र कुमार राणा को लगभग 1 लाख 38 हजार वोटों के अन्तर से पराजित किया था. वहीं इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी महबूब अली कैसर तीसरे स्थान पर रहे थे. यदि कांग्रेस और राजद को मिले वोटों को जोड़ दे तो भी जदयू उम्मीदवार को पकड़ पाना आसान नहीं है. वहीं इसबार मतदाताओं की संख्या 1475075 है. जिसमें यादव, कुशवाहा, मुस्लिम, राजपूत सहित पचपनिया समुदायों का अच्छी-खासी संख्या है. लेकिन इस बार के चुनाव में बदलते परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो त्रिकोणिय मुकाबले की संभावना बनती दिख रही है. वहीं आम आमदी पार्टी के डॉ. विवेकानन्द चतुष्कोणीय मुकाबले के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. बात की जाय राजद उम्मीदवार कृष्णा कुमारी यादव की तो उन्होंने जिले में एक वर्ष से लगातार रणनीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया था तथा समस्याओं के समाधान के प्रति सजग भी थीं. जबकि उनके पति रणवीर यादव अपने वोट बैंक पर जबर्दस्त पकड़ रहने के कारण जीत को सुनिश्चित मानते हैं. क्योंकि माय समीकरण सहित अन्य समुदायों पर भी इनकी पकड़ मानी जाती है. यही कारण है कि इनकी पहली पत्नी पूनम देवी यादव लगातार खगड़िया का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. वहीं जदयू का जनाधार क्षेत्र में लगातार खिसकता जा रहा है. यही वजह है कि दिनेश चंद्र यादव के लिए यह सफर कांटों भरा होगा. लेकिन यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि इनकी नैया पार लग जाएगी. लेकिन राह इतनी आसान नहीं है. जदयू के अंदर की गुटबाजी उनको मुश्किल में डाल सकती है. वहीं भाजपा, लोजपा व रालोसपा गठबंधन की बात की जाए तो लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर को प्रत्याशी बनाया गया है. एनडीए गठबंधन भी यहां के अल्पसंख्यक मतदाताओं पर नजर गराये हुए है. अल्पसंख्यक समाज का भरोसा जीतने व नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा व इसके सहयोगी यहां काफी सक्रिय हो गई है. लोजपा मुस्लिम इलाकों में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अपना पैठ बनाने का प्रयास कर रही है. साथ ही कैसर इस समुदाय के कद्दावर प्रत्याशी हैं लिहाजा अल्पसंख्यक समाज के वोटों में सेंध लग सकता है. वहीं दलित व भाजपाई का वोट बैंक केसर को जीत दिलाने में सहायक हो सकता है. वहीं आम आदमी पार्टी के डॉ. विवेकानन्द को आमजनों पर आप के प्रभाव होने का विश्वास है. उनका कहना है कि जाति धर्म से हट कर लोग एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को वोट देंगे. इसी के सहारे हम मैदान में मजबूत उम्मीदवार हैं. लेकिन रोम है तो पोप का, खगड़िया है गोप का वाली कहावत पर सेंध लगती नजर आ रही है. आखिर राजद लोजपा एवं जदयू के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है.■

एक नज़र

मतदान को लेकर कार्यशाला

राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 16वीं लोकसभा चुनाव- 2014 में मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए समस्तीपुर समाहरणालय सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी व डीएम नवीन चन्द्र झा ने मीडिया कर्मियों, शिक्षण संस्थान, स्काउट गाइड, एनसीसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभाग से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए सभी से राय ली. डीएम ने बताया कि चुनाव आयोग ने पहली बार अवेयरनेस पर्यवेक्षक को चुनावी कार्य में लगाया है. तमिलनाडु से सुब्रमन्यम जिले में आ रहे हैं. इस दौरान पदाधिकारियों ने मतदान से संबंधित जानकारी दी. इवीएम प्रशिक्षक अनेयुल हक, डीडीसी रमेश कुमार शर्मा, एडीएम मोबिन अली अंसारी, एडीएम आपदा गौतम पासवान, एसडीओ सुधीर कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जेड हसन, जिला शिक्षा पदाधिकारी जयचन्द्र श्रीवास्तव, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार उत्तम, सिविल सर्जन शंकर झा, डीपीओ संजय कुमार, अवधेश प्रसाद सिंह, वीरेन्द्र कुमार सिंह, कॉलेज के प्राचार्य व मीडियाकर्मी उपस्थित थे.

– यशवंत कुमार सिंह

बनेगा पुल

गोगरी अनुमंडल के सुल्तानगंज गंगा घाट में महासेतु निर्माण जैसे पुनीत काम के लिए दुनिया हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पूर्व परिवहन मंत्री आरएन सिंह के अथक प्रयास को याद करेगी. इक्त बातें पूर्व परिवहन मंत्री सह जदयू के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामानंद प्रसाद सिंह ने कही . साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार का प्रवेश द्वार कही जाने वाली उत्तर वाहिनी गंगा घाट व अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच सेतु निर्माण के लिए बीते 5 दशक पूर्व भारत-चीन युद्ध के समय भी थल सेना के नायक ने भी उक्त सेतु निर्माण को लेकर चर्चा की थी. लेकिन आजादी के 6 दशक के बाद भी किसी दल के विधायक व सांसद ने इस कार्य को पूरा नहीं किया. उक्त गंगा घाट पर महासेतु निर्माण की भनक लगते ही बाकी दल अपने-अपने प्रयास को बताकर झूठी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं. मौके पर प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी, कल्लू बाबू, युवा नेता मिथलेश कुमार दिवाना, जयजयराम चौधरी, डॉ. राजीव सिंह, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजीव सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

कांग्रेस का दौरा

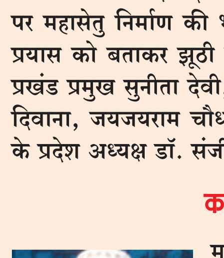

मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री व कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रभु दयाल सहनी ने बेलदौर प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक किया. उन्होंने बताया कि धरातल पर अधिकांश योजना केंद्र सरकार की है. चाहे वह वृद्धा पेंशन हो अथवा मनरेगा की योजना या अन्य बड़ी-बड़ी योजनाएं, विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार पैसा दे रही है. गरीबों के लिए हितकर योजना चलाई गई है. लेकिन बिहार की सरकार आज हवा में तीर चला रही है. उन्होंने अगुवानी-सुल्तानगंज पुल के बारे में कहा कि नेतागण अपनी-अपनी डफली बजाते हैं यदि बिहार सरकार अपनी राशि से पुल बनाती तो इसकी आवाज तो बहुत पहले से उठ रही थी. अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? केन्द्र सरकार यदि अपनी राशि नहीं देती तो आज इतनी योजना धरातल पर नहीं उतर पाती. मौके पर राकेश रंजन सिंह, सुमन यादव, नीरज कुमार मिश्र, मुन्ना सिंह, सत्यनारायण सहनी, श्रीकांत मंडल, चमन सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.

सूबे में भंडारण क्षमता नहीं

धर्मनिरपेक्षता देश की आत्मा है. इसके साथ खिलवाड़ करने वाले इस देश में न कभी कामयाब हुए हैं और न होंगे. उक्त बातें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. चंदन ने कही. उन्होंने कहा कि यूपीए की केंद्र सरकार ने पिछले नौ साल के कार्यकाल में ग्रामीण विकास एवं ग्राम जीवन में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराया है. इसमें ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, पुल पुलिया, इंदिरा आवास योजना के माध्यम से दी गई राशि शामिल है. लेकिन राज्य सरकार की सीमित प्रशासनिक क्षमता रहने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है. उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा पांच रुपये का टिकट लेकर जनता को अपने नेता का भाषण सुनने का अवसर देती है. वहीं कांग्रेस पांच रुपये में खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से चावल, तीन रुपये में गेहूं, दो रुपये में मोटा अनाज मुहैया करा रही है. बिहार इस बिल के माध्यम से 56 लाख टन अनाज प्राप्त कर सकता है. लेकिन यहां भंडारण क्षमता केवल 27 लाख टन की ही है. मौके पर शील प्रियम, प्रियरंजन, आनंद, मधुमिता, भुवनेश्वर दास आदि मौजूद थे.

याद किए गए शहीद

योगगुरु स्वामी रामदेव के निर्देश पर अररिया जिला मुख्यालय स्थित त जनारायण महाविद्यालय परिसर में पिछले दिनों भव्य योग शिविर का आयोजन भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति के द्वारा किया गया. इसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रो. कमल नारायण यादव ने की जबकि संचालन युवा अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र ने किया. इस अवसर पर पतंजलि योग समिति हरिद्वार से पधारे दीपक जी ने बाबा रामदेव के संदेश इपस्थित विशाल जनसमुदाय को देते हुये कहा कि भारत देश वीर सपूतों का देश रहा है. इस देश के वीर वांकुड़ों ने अपनी शहादत देकर भारत माता को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराया था लेकिन इन शहीदों को लेकर भारत की सरकारें संवेदनशील नहीं हैं. इस अवसर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया. प्रमुख रूप से उपस्थित होने वालों में इंजीनियर वीरेन्द्र शरण, अररिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य मो. कमाल, डॉ. एस.एन. महतो, रूपचंद बड़रिया, डा. शिवनाथ महतो, राजेश जी, शशिभूषण, महेश्वर मिस्त्री, नवलकिशोर सिंह, नन्दलाल गिरी, मदनमोहन मेहता, विशेश्वर प्रसाद, फूलचंद विश्वास, शांति कुमारी, द्रौपदी देवी, किरण जी, जगतनारायण दास, देवकला देवी, प्राचार्य इन्दु कुमार सिन्हा, रीमा जी आदि उपस्थित थे.■

– पुरुषोत्तम प्रियदर्शी

वर्कशॉप आयोजित

दिल्ली पब्लिक स्कूल गया में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तीन दिवसीय विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इसमें स्कूल के कक्षा पांच से लेकर सात तक के बच्चों ने भाग लिया. वर्कशॉप में विभिन्न क्षेत्रों के देश के नामचीन लोगों ने बच्चों को सफलता के गुर सिखाए. वर्कशॉप के दूसरे दिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी कराने वाले विशेषज्ञ का आना हुआ. कोटा से आए नीलेश गुप्ता तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल गया के काउंसलर विकास कुमार ने बच्चों के अभिभावकों से बच्चे तथा स्कूल से उनकी अपेक्षा और स्कूल के भी अभिभावकों से क्या अपेक्षा हो सकती है, इस संबंध में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी. दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिसर में 22 से 24 मार्च तक आयोजित इस स्पेशल वर्कशॉप में संगीत की विशेष शिक्षा प्रख्यात बांसुरीवादक चेतन जोशी, पश्चिमी नृत्य की शिक्षा अन्तरराष्ट्रीय कोरियोग्राफर टिटो डे, शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा तनीमा बोस, व्यक्तित्व विकास की जानकारी शिल्पी परासर, स्पोकेन इंगलिश की शिक्षा यास्मीन चौधरी, फिटनेश और योगा के संबंध में सम्पूर्णा चौधरी तथा खेल-खेल में गणित सीखें के संबंध में सौरभ गुप्ता ने बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया. विशेष वर्कशॉप की समाप्ति पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रचार्य अभिषेक कुमार ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया.■

– सुनील सौरभ

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

समस्या बोन मैरो की
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ राजीव आनंद
AROFIT Protin Powder
Protein granules enriched with Vitamin, Minerals & Carbohydrates
Levokon Levofloxacin 500 mg
ARILINE Acebrophylline 100 mg
MUSTAL Montelukast Sodium 10 mg+ Levocetirizine HCL 5 mg
ONDANOK Ondanesetron 2 mg
– प्रस्तुति : अमृता कुमारी
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिचा स्वामी, राजस्थान
उत्तर : आप CINERARIA MARITIMA REPL दिन में 2 बार दोनों आँखों में 2-2 बूँद डालें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चालू रखें। आपको स्थायी निदान मिलेगा। क्योंकि यह बाजार में अन्य आईड्रॉप से अधिक प्रभावशाली व परिष्कृत है।
प्रश्न : डॉ साहब मेरी उम्र 23 वर्ष है, गलत आदतों के कारण अत्यधिक कमजोरी है, इच्छा मात्र से ही असंयमित हो जाता हूँ। मधुरेन्द्र, देहरादून
उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : मेरी आयु 33 वर्ष है एवं मैं विवाहित हूँ पेशाब में धातक्षीणता की शिकायत है। जिससे मैं कफी चिंतित रहता हूँ। कोई अच्छा और हानिरहित उपाए बतायें। आविद, फिरोजाबाद।
उत्तर : आप निराशा मन से निकाल दें और विगोरा 5000 की 6 शीशी का कोर्स करें एवं विगोरा ऑयल से मालिश करें। यह होमियोपैथिक लिक्यूड दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
प्रश्न : मेरी उम्र 54 साल है, मैं बाबासीर का मरीज हूँ, पिछले कुछ दिनों से इच्छा होते हुए भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर
उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलेक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5x का 6 शीशी का कोर्स करें और सुबह-शाम हाई पावर मुसली आयल से दो महीने तक लगातार मालिश करें। आपको लाभ होगा।
प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 68 वर्ष है। शरीर से बिल्कूल स्वस्थ्य हूँ, लेकिन इच्छाशक्ति के रहते हुये भी शरीर साथ नहीं देता। कोई आयुर्वेदिक तात्कालिक समाधान बतायें। जगदीश प्रसाद, झरिया।
उत्तर : आप सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
प्रश्न : पिछले 7-8 वर्षों से मेरे घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहता है। दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है कोई आयुर्वेदिक उपचार बतायें। देवंती सिंह, दिल्ली
उत्तर : आप ऑर्थोविट कैप्सूल सुबह-शाम एक कैप्सूल लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालिश करें काफी लाभ होगा।
प्रश्न : मेरी उम्र 24 वर्ष है। अविकसित सीना के कारण हीन-भाव से ग्रसित हूँ। आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।
उत्तर : सीना का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।
प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण सिर पर गंजापन हो गया है, मैं इस समस्या से बहुत चिन्तित हूँ, उपाय बतायें । उपेन्द्र सिंह, कानपुर
उत्तर : बालों के झड़ने, टुटने से बचने के लिए आप केशवर्धक तेल का नियमित इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ना एवं टूटना तत्काल समाप्त हो जायेगा।
प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्ता आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून
उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।
चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

आपका शानदार घर बर्बाद ना हो !
घर बनाने से पहले आइये कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें
* क्या आप जानतें हैं बिल्डिंग मेटेरियल्स पर करीब 28 से 30 परसेन्ट टैक्स लगा रहता है। सभी अच्छी कम्पनी का सामान का वैट बिल लेने पर आपको कोई टैक्स देना नही पड़ता है। सभी अच्छी कम्पनियां सभी टैक्स पेड माल अपने डीलर या रिटेलर को सप्लाई करती है।
* आप अपना घर बनाने में अगर 25 लाख खर्च करते हैं तो उस पर करीब 7 लाख टैक्स भारत सरकार एवं राज्य सरकार को मिलता है। जो वापस आपके लिए ही सरकार खर्च करती है।
* आप बिल्डिंग मेटेरियल्स खरीदते समय वैट बिल नही लेते हैं तो आपका रुपया तो जाता ही है, आपको नकली सामान भी मिलता है, जैसे आप 20 किलो का वॉल पुटटी जिस पर कीमत रु0. 800 लिखा है उस पर कम्पनी रु0.69 एक्साईज डयूटी एवं वैट 96 रुपया टोटल 165 रु0 टैक्स कम्पनी लिए हुए रहती है। परन्तु आपके छोटी सी भूल से आप बिना वैट बिल का नकली सामान खरीद लेते हैं। जिससे जिस सामान की लाईफ 10 साल होनी चाहिए वह सामान साल भर में ही खराब होने लगता है। अपने शानदार घर को बर्बादी से बचाने के लिए सभी सामान का वैट बिल अवश्य ले लें। आपकी सावधानी से आपके घर की लाईफ कई गुणा बढ़ जायेगी।
राजस्थान के चुनिन्दा जिप्सम से बना बेहतरीन क्वालिटी का
ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस
* प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीदते समय बोरी का वजन जरुर चेक करें, क्योंकि साधरण प्लास्टर ऑफ पेरिस 20 किलो के बोरी में 16 किलो ही आता है, बिना वैट बिल का प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिटटी मिला हो सकता है। जिससे आपके फाल्स सिलींग या पी0 ओ0 पी0 का काम साधारण क्वालिटी का होगा।।।।।
* प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके पूरे घर की सुन्दर पेन्टिंग का बेस होता है, अगर वही साधारण क्वालिटी का होगा तो आपके कीमती पेन्टिंग का भविश्य क्या होगा आप खुद सोचिये ।।।।
ईटालियन ईन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण पेरिस की अपेक्षा आपके दीवारों एवं मकानों को ज्यादा सुन्दर बनाता है ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा बारीक होने के कारण यह ज्यादा फैलता है, कड़े क्वालिटी कन्ट्रोल में बना हुआ सुपर स्ट्रौंग, सुपर स्ट्रैंथ एवं सुपर कवरेज वाला भारत का सबसे बेहतरीन ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस ।
वॉल पुटटी के बारे में जानिए
वॉल पुटटी के बोरी में अधिकतर कम्पनियां रुपये का कूपन डालती है जांच करें बिना वैट बिल का वॉल पुटटी नकली हो सकता है, जिसमें केमिकल की सही मात्रा नही होती है, जबकि असली वॉलपुटटी में केमिकल 200 से 450 रुपये किलो का लगता है, एक बोरी ऑरिजीनल वाल पुटटी पर करीबन 200 रुपये टैक्स लगा रहता है जो सभी कम्पनी को देना होता है लेकिन नकली माल बनाने बाले टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन आपसे पूरा कीमत वसूल लेते हैं। आपकी जरा सी सावधानी से वैट बिल के साथ खरीदारी पर आप हमेशा असली सामान ही खरीदेगें।
Made from Imported Chemicals
ITALIAN Beauty Wall Putty
ईर्म्पोटेड केमिकल से तैयार क्वालिटी एवं पैकिंग में भारत का नं0 1 वॉल पुटटी
सबसे किफायती 40 किलो पैक
डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप
अपने फर्म का नाम पूरा पता एवं वैट नं० के साथ एस.एम.एस या मेल करें
Mob-09549663640 E-mail- shalimarpop@gmail.com *शर्तें लागू
प्रिय ग्राहक कृपया ध्यान दें
हमारी कम्पनी सभी सामान टैक्स पेड देती है, आपको अलग से कोई टैक्स नही देना है, ऑरिजीनल सामान के लिए वैट बिल अवश्य ले लें तभी आप 1 किलो सोना के लक्की ड्रा स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
लक्की ड्रॉ में 1 किलो 24 कैरेट सोना
24 कैरेट 10 ग्राम सोने का 100 सिक्का
www.iiplindia.com
अपने देश हित में, अपने राज्य हित में वैट बिल अवश्य लें
वैट बिल लेना आपका अधिकार है, ओरिजीनल सामान की पहचान है।

सताधारी दल जदयू ने इस बार मैदान में पूर्व आयुक्त केपी रमैया को मैदान में इतारा है. रमैया पिछले चार महीने से मतदाताओं और जदयू के परंपरागत मतों के बीच अभ्यास कर रहे थे. हालांकि इनका चुनाव प्रचार अभी जोर नहीं पकड़ सका है. जो अपने लिए कुर्मी अतिपिछड़ा और महादलित मतों को आधार मानते हैं.

आसान नहीं भाजपा की राह

सुनील सौरभ

लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है. बिहार की लगभग सीटों पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के तहत तमाम पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है. इसी क्रम में गया संसदीय क्षेत्र से मांझी जाति के तीन लोगों को टिकट दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन चुनावी नैया को पार लगाएगा. एक ही बिरादरी के तीन चेहरों के चुनावी समर में कूदने से यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है. अभी यह सीट भाजपा के खाते में है. भाजपा-जदयू का जब गठबंधन था, तो गठजोड़ के बूते गया संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी विजयी हुए थे, लेकिन इस बार दोनों दल जदयू और भाजपा अलग-अलग हैं.

2009 के चुनाव में राजद और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था. दोनों दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी खड़े किए थे. राजद से रामजी मांझी थे, तो कांग्रेस से संजीव प्रसाद टोनी. इस बार स्थिति अलग है. राजद और कांग्रेस का गठजोड़ हो गया, तो भाजपा और जदयू की राहें अलग-अलग हो गई हैं. तब राजद प्रत्याशी रामजी मांझी को एक लाख 83 हजार 802 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी संजीव प्रसाद टोनी को 64 हजार 900 मत. वहीं भाजपा के विजयी प्रत्याशी हरि मांझी को दो लाख 46 हजार 252 मत मिला था. इसमें जदयू का भी समर्थन वोट शामिल था. इस बार राजद-कांग्रेस गठबंधन भाजपा प्रत्याशी को सबक सिखाने के मूड में हैं.

2004 के लोकसभा चुनाव में जब राजद का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो उस समय राजद प्रत्याशी राजेश कुमार मांझी को जीत मिली थी और उन्हें चार लाख 64 हजार 829 मत मिला था. जबकि जदयू से समर्थन के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी बलवीर चांद को तीन लाख 61 हजार 895 मत ही प्राप्त हुआ था. 1999 में भाजपा के विजयी प्रत्याशी रामजी मांझी को तीन लाख 19 हजार 530 मत मिला था. आज वही रामजी मांझी राजद प्रत्याशी हैं. 1999 में दूसरे स्थान पर राजद के राजेश कुमार रहे थे. इन्हें दो लाख 98 हजार 747 मत मिले थे.

पिछले ढाई दशक के लोकसभा चुनाव पर ध्यान दिया जाए, तो गया संसदीय क्षेत्र में दो दलों के बीच ही सीधी लड़ाई रही है. त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं के बराबर हुई है. स्पष्ट है कि नरेन्द्र भाई मोदी के गुजरात मॉडल और हिंदूवादी छवि की बहती बयार के बावजूद

गया सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सफलता की राह आसान नहीं है. एनडीए से जदयू के अलग हो जाने और दूसरी ओर कांग्रेस के राजद के साथ हो जाने से इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कड़ी चुनौती का सामना करना पडेग़ा. लोजपा तथा रालोसपा के गठजोड़ से शायद ही गया की तस्वीर बदल पाए. जदयू प्रत्याशी के रूप में बिहार के कबीना मंत्री जीतन राम मांझी भी भाजपा प्रत्याशी को पटखनी देने को तैयार हैं. राजनीति के माहिर खिलाड़ी जीतन राम मांझी गया जिले के बोधगया-बाराचट्टी से कई बार विधायक रह चुके हैं. फिलहाल जहानाबाद के मखदुमपुर से विधायक हैं.

ऐसे तो पिछले कई लोकसभा चुनाव में एक बार भाजपा तो दूसरी बार राजद को यहां से सफलता मिल चुकी है. इसका कारण चाहे जो रहा हो. हालांकि 1971 के बाद से गया संसदीय सीट एक तरह से भाजपा (जनसंघ) की परंपरागत सीट मानी जाती रही है. सिर्फ 80 और 85 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामस्वरूप राम को सफलता मिली थी. ईश्वर चौधरी कई बार सांसद रहे, कृष्णा चौधरी, रामजी मांझी, हरि मांझी यहां से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजयी होते रहे हैं. यहां के चुनाव में दलों का गठबंधन और समीकरण भी बहुत काम आता है. इस बार भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद हरि मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं दूसरी ओर राजद-कांग्रेस गठबंधन के साथ अपना मजबूत वोट बैंक के बूते अपने पुराने प्रत्याशी रामजी मांझी पर दांव खेला है. स्वभाविक है कि इस बार भी गया में लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला होगा, लेकिन जदयू के प्रत्याशी जीतन राम मांझी इस मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास करेंगे. लेकिन अभी से बनते-बिगड़ते चुनावी समीकरण के बीच मतदाताओं का रुख क्या होगा, यह मतदान के समय ही स्पष्ट होगा.

गया संसदीय क्षेत्र का दलों व जातिगत वोटों के समीकरण का जोड़-घटाव किया जाये, तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले राजद इस बार मजबूत स्थिति में है. जातीय आधार को देका जाय, तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक वोट गया संसदीय क्षेत्र में है. दूसरे स्थान पर यादव और मुस्लिम वोट आता है. अगड़ी, वैश्य तथा अन्य जातियों का मत चौथे-पांचवें स्थान पर आता है. तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी के अनुसूचित जाति के एक ही समुदाय से आने के कारण बंटवारा निश्चित है. लेकिन इतना तय हैं कि इन सबके बावजूद इस बार गया से भाजपा के सांसद हरि मांझी की राह आसान नहीं है. गया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में शेरघाटी से जदयू के विनोद यादव, बाराचट्टी (सुरक्षित) से जदयू की ज्योति मांझी, बोधगया (सुरक्षित) से भाजपा के श्यामदेव पासवान, गया टाउन से भाजपा के डा. प्रेम कुमार, बेलागंज से राजद के डा. सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा वजीरगंज से भाजपा के वीरेन्द्र सिंह विधायक हैं. लंबे समय से गठबंधन में शामिल होने के बाद अलग-अलग हुए दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की टकराहट का लाभ अगर राजद प्रत्याशी को मिल जाये, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी. अब देखना है 10 अप्रैल को मतदान के बाद 16 मई चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा की बाजी कौन मारता है.■

feedback@chauthiduniya.com

सवर्णों के सहारे सासाराम के योद्धा

ममता चौहान

वर्ष 1952 से लेकर अब तक देश के महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में सुमार रहा सुरक्षित सीट सासाराम से इस बार संसद की राह किसी के लिए आसान नहीं है. हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी स्पीकर मीरा कुमार के राह में अगर कांटे ही कांटे हैं तो भाजपा उम्मीदवार छेदी पासवान की भी राह आसान नहीं है. पासवान अपनी कमजोरी दूर करने में रात दिन लगे हैं और इसमें उनको सफलता भी हाथ लग रही है. कुछ घटनाओं को लेकर दोनो ही उम्मीदवारों से कहीं न कहीं सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी है. देखना यह है कि यह नाराजगी 10 अप्रैल से पहले कैसे दूर हो पाती है. ऊपर से राजद के साथ कांग्रेस के हुए गठबंधन के बाद यादव मतदाताओं की स्थिति भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है. ऐसे हालात में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. वैसे रविदास, कुशवाहा, और अल्पसंख्यक मतों को आधार मानकर चुनावी मैदान में उतरीं मीरा कुमार यादवों, ब्राम्हणों और राजपूतों को मनाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं पर नरेंद्र मोदी की हवा के कारण उन्हें कोई फायहदा होता नहीं दिख रहा है. उतनी ही मेहनत छेदी पासवान राजपूत व ब्राम्हण मतदाताओं पर करते दिख रहे हैं. जिनके पास पासवान, वैश्य सहित भाजपा के परंपरागत मत पहले से पड़े हुए हैं. इसी बीच मीरा कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंची उनकी भतीजी और स्वर्गीय सुरेश राम की पुत्री मेधावी कीर्ति ने नामांकन से पहले एक अलग फिजा तैयार की थी. जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा विवादस्पद तरीके से टिकट बंटवारा के कारण समाप्त हो गया. मेधावी कीर्ति द्वारा तैयार की गई फिजा को लोग कांग्रेस का नुकसान समझ रहे थे. जिससे अब स्पीकर मीरा कुमार के खेमें में लोग थोड़ी राहत की सांस लेते दिख रहे हैं. बसपा ने अब बलेश्वर भारती को अपना

उम्मीदवार बनाया है जो पहले भी सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अब नए सिरे से चुनावी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे उनके अभियान पर असर पड़ेगा. उधर छेदी पासवान के मैदान में आने से रविदास और पासवान मतदाताओं की खेमाबंदी स्पष्ट दिख रही है. सताधारी दल जदयू ने इस बार मैदान में पूर्व आयुक्त केपी रमैया को मैदान में उतारा है. रमैया पिछले चार महीने से मतदाताओं और जदयू के परंपरागत मतों के बीच अभ्यास कर रहे थे. हालांकि उनका चुनाव प्रचार अभी जोर नहीं पकड़ सका है. जो अपने लिए कुर्मी अतिपिछड़ा और महादलित मतों को आधार मानते हैं. सचमुच में अगर यह तीनों वर्ग जदयू को वोट करता है, तो लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है. जो अभी नहीं दिख रही है. फिलहाल कांगेस की मीरा कुमार और भाजपा के छेदी पासवान के बीच सीधी टक्कर की संभावना बनी हुई है. एन वक्त पर जदयू व बहुजन ने एंट्री मार दी तो किसी भी प्रत्याशी के लिए संसद की राह कठिन हो जाएगी. इस चुनाव में राजपुत, ब्राहम्ण और यादव के साथ भूमिहार मतदाताओं की चुप्पी हर प्रत्याशी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. मतदाताओं के एक वर्ग में पिछली बार राजद उम्मीदवर के रूप में चुनाव लड़ चुके ललन पासवान के मैदान में नहीं रहने की कसक भी है. छेदी पासवान के पक्ष में युवा वोटरों का लगाव उन्हें राहत दे रहा है. देखना है मीरा कुमार और छेदी पासवान के बीच मची यह जंग क्या नतीजा देता है.■

feedback@chauthiduniya.com

उदय सिंह को भितरघात का ख़तरा

नीरज कुमार सिंह

पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का चुनाव 24 अप्रैल को होने जा रहा है. चुनाव सिर पर है लेकिन संसदीय क्षेत्र में जोड़-तोड़, भितरघात और गोलबंदी चरम पर है. लोग दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर गोलबंद होते नजर आ रहे हैं. यह नजारा सबसे अधिक भाजपा में दिख रहा है. यही वजह है कि नाराज और असंतुष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं द्धारा भितरघात की राजनीति की चर्चाओं का बाजार गर्म है. मालूम हो कि पूर्णिया संसदीय सीट से वर्तमान भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं. इसी सिलसिले में वे सीमांचल में नमो लहर उत्पन्न करने के उद्देश्य से विगत 10 मार्च को नरेन्द्र मोदी की रैली भी करा चुके हैं. दूसरी तरफ पूर्णिया में असंतुष्ट और नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं की फौज दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. जिसको भुनाने में पूर्व भाजपा विधायक व वर्तमान जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा लगे हुए हैं.

भाजपा के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अमरनाथ तिवारी को उतारा है, जबकि जदयू ने भाजपा के बागी विधायक संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा है. हालांकि वे बायसी विधानसभा के विधायक हैं और यह क्षेत्र किशनगंज लोकसभा में आता है. पूर्णिया में नए जातिगत, राजनीतिक समीकरण के सहारे जदयू के लोगों व भाजपा के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं द्धारा हवा दिए जाने से वे जमकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उनका ऐसे लोगों के घर-घर जाने का दौरा लगातार चल रहा है. वहीं पूर्व सांसद व वर्तमान में मधेपुरा से राजद प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कट्टर समर्थक कार्यकर्ता पूर्णिया के मुस्लिम एवं यादव वोटरों को कुशवाहा के पक्ष में गोलबंदी रोकने को लेकर जुटे हुए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के कथित समर्पित कार्यकर्ता पार्टी लाइन से अलग हटकर पूर्णिया सांसद के प्रति समर्पण की भावना दिखाकर विपक्षी प्रत्याशी से मिलकर भितरघात कर रहे हैं, वहीं कुछ असंतुष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर जानकारी दी कि हमलोगों ने विगत दो लोकसभा में उदय सिंह के प्रति समर्पण की भावना दिखाई जिससे इनकी जीत हुई. लेकिन बदले में जो सम्मान हमलोगों को मिलना था और विकास कार्यो में जो हमारी सहभागिता होनी चाहिए थी वह आज तक नहीं हुई. आगे नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से मुगलकाल में अकबर के दरबार में करीबी और निजी सलाहकार को रत्न की उपाधि मिली हुई थी उसी तरह से पूर्णिया सांसद के दरबार में पांच रत्न हैं. अगर क्षेत्र के आम जनता की कोई समस्या रहती है तो कार्यकर्ताओं को सांसद से मुखातिब होने के पहले इन पांच रत्नों से पहले मुखातिब होना पड़ता है. अगर कोई कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को सांसद के पास रखना भी चाहे तो पहले समस्याओं को उन लोगों को बताना पड़ता है. बिना इन लोगों की अनुमति के हमलोग अपनी समस्याओं को ना तो सांसद के पास रख सकते हैं और ना ही मिल सकते हैं. ऐसे में आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए कार्यकर्ताओं के लिए भी सांसद तो दूज के चांद की तरह हैं. कुछ कार्यकर्ताओं का कहना था कि 2004 के लोकसभा चुनाव में उदय सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपाई बने, कार्यकर्ताओं को उनसे काफी अपेक्षा थी, इस चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग उनको मिला और पूर्णिया उदय के नारे को सफल बनाने के लिए उन्हें विजयी दिलाई. लेकिन विगत दो चुनाव जीतने के बाद भी यहां के अधिकतर भाजपा कार्यकर्ता इपेक्षित हैं. चुनाव कार्यकर्त्ताओं का यह हाल है तो क्षेत्र की आम जनता की सुधि लेने का सवाल कहां से खड़ा होता है? उदाहरण पेश करते हुए इनका कहना था कि गुलाबबाग, खुश्कीबाग समेत पूर्णिया पूर्व प्रखंड में भाजपा को वोट देने वाले अधिकतर मतदाता हैं लेकिन कर्मठ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र भ्रमण कर ऐसे मतदाताओं का सुधि लेने का कार्य सांसद द्धारा कभी नहीं किया गया. साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र की विकास योजनाओं में एवं उनके क्रियान्वयन में कार्यकर्ताओं का आम सहभागी बनाया जाता है और उनका अहम योगदान होता है जब कार्यकर्ता ही सांसद से उपेक्षित हों तो क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठना लाजिमी है. आज उन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्व भाजपा विधायक व वर्तमान जदयू प्रत्याशी भाजपा कार्यकर्ताओं के घर-घर पर पहुंचकर जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं. मालूम हो कि संतोष कुशवाहा पूर्व में सांसद उदय सिंह के करीबी थे. उदय सिंह की कृपा से ही उनको भाजपा का टिकट मिला था और उनके सहयोग से ही विधायक बने थे. लेकिन आज उदय सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर मैदान में हैं. पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में हुए विगत दो लोकसभा चुनाव की चर्चा अगर की जाए तो वर्ष 2004 में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह 65 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीते थे. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में लगभग साढ़े तेरह लाख मतदाता वाले इस सीट पर संसद उदय सिंह ने 1,86,227 मतों के अंतर से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी शांति प्रिया (पप्पू यादव की मां) को हराया था, जिसमें लोजपा प्रत्याशी शंकर झा को 21,754 एवं बसपा प्रत्याशी नवीन कुमार सिंह 21,281 मत मिले थे. इस चुनाव में कुल 7,04,752 मत पड़े थे. जिसमें उदय सिंह को कुल 3,62,952 मत एवं शांति प्रिया को 1,76,725 मत मिले थे. वर्तमान में अगर नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं. वैसे मोदी लहर में सांसद की नैया पार भी हो सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

07 अप्रैल–13 अप्रैल 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

कांग्रेस को मझधार में छोड़ गए मिस्त्री

कांग्रेस में हर तरफ भगदड़ मची है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने का बीड़ा उठाये घूम रहे यूपी के चुनाव प्रभारी और गुजरात के नेता मधुसूदन मिस्त्री को राज्य की जिम्मेदारी मझधार में छोड़कर गुजरात में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को भेज दिया गया है. मिस्त्री सरीखे अन्य बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को लावारिस छोड़ दिया है. कांग्रेस नेतृत्व के मस्तक पर भी हार की चिंता साफ झलक रही है. देखना दिलचस्प होगा कि मिस्त्री का पलायनवाद कांग्रेस के मंसूबे पर कितना खरा उतरती है?

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अवसाद से नहीं उबर पा रही है. दमदार नेतृत्व के अभाव में नेताओं–कार्यकर्ताओं का मनोबल शेयर बाजार की तरह गिरता जा रहा है. राहुल–सोनिया को यूपी की सुध लेने की फुर्सत नहीं है. इस बार तो प्रियंका भी अपनी मां–भाई का बेड़ा पार लगाने के लिये ज्यादा मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही हैं. संगठन हासिये पर है. पार्टी में भगदड़ मची है. कई बड़े और पुराने कांग्रेसी हताशा की स्थिति में घर में बैठ गये हैं या पार्टी से नाता तोड़कर किनारा कर चुके हैं. कांग्रेस की हार का डर ही था, जो इस बार से अन्य राज्यों की तरह यूपी से भी दस जनपथ से टिकट मांगने कोई नहीं गया. किसी ने बीमारी का बहाना बना कर पल्ला झाड़ लिया, तो तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं दिखाई, जो मजबूरी में उतरे भी तो इनके हौसले मैदान में उतरने से पहले ही पस्त दिख रहे हैं. अभिनेता से नेता बने राजब्बर जैसे कुछ प्रत्याशी मैदान बदल कर बाजी मारने के चक्कर में लगे हैं. वर्षों से यूपी कोटे से केन्द्र सरकार में मलाई मारने वाले श्रीप्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे बड़े नाम भी पार्टी की नैया पार लगाना तो दूर, अपनी हार को लेकर आशंकित हैं. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभी तक कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है. ऐसे तमाम कारणों से कांग्रेसी मुंह छिपाने को मजबूर हो रहे हैं.

बड़बोले बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेता और केन्द्रीय मंत्री, जो लगातार असंसदीय बयानबाजी करके सुर्खियां बटोर रहे थे, चुनावी मौसम में इनका पता ही नहीं चल रहा है कि वह किस मांद में छिप कर बैठ गये हैं. नेता तो नेता, नेतृत्व भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगा है. अगर ऐसा न होता तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने का बीड़ा उठाये घूम रहे यूपी के चुनाव प्रभारी और गुजरात के नेता मधुसूदन मिस्त्री को राज्य की जिम्मेदारी मझधार में छोड़कर गुजरात में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को नहीं भेज दिया जाता. मिस्त्री को गुजरात चुनाव लड़ने के लिये इन्हीं राहुल गांधी ने भेजा है, जिन्होंने पहले मिस्त्री के कंधों पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी डाली थी. इसी तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री भी लखनऊ की जिम्मेदारी छोड़कर फैजाबाद चुनाव लड़ने चले गये हैं.

उत्तर प्रदेश में दस अप्रैल को वोट पड़ने के साथ ही छह चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनावी तैयारियां भगवान भरोसे चल रही हैं. दूसरे दलों की तुलना में कांग्रेस ही ऐसा राजनीतिक दल है, जो तैयारियों के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है. यहां न तो वार रूम ढंग से काम कर रहा है और न ही कंट्रोल रूम. जो नेता यहां बैठते भी हैं, वे अपनी मनमर्जी के मालिक हैं. राहुल गांधी असम–मेघालय और अन्य सुदूर इलाकों में तो जनसभा करने जा रहे हैं, लेकिन यूपी में प्रचार के लिये

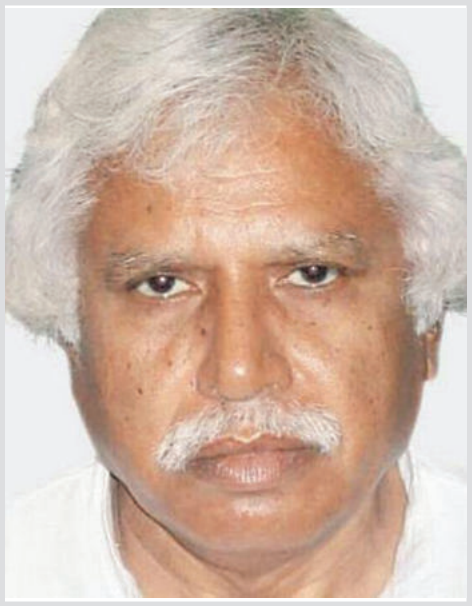

जरूरत के अनुसार समय देने में कतरा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है. मोदी लहर में कांग्रेस का तम्बू उखड़ने वाला है. ऐसे में राहुल गांधी अपने सिर हार का ठीकरा क्यों फोड़ेगें? वैसे भी 2012 के विधानसभा चुनाव में जो हश्र कांग्रेस का हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है. तब भी राहुल वन मैन आर्मी की तरह यूपी में जीत के बड़े–बड़े दावे कर रहे थे. भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस ने अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी के हवाले यूपी को कर दिया है.

बहरहाल, बात कांग्रेस के प्रदेश संगठन की दुर्दशा की ही की जाये तो इसका यह हाल इसलिए हुआ है, क्योंकि बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को लावारिस छोड़ दिया है. प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी हैं, पहले तो यूपी की जगह दिल्ली में ही व्यस्त रहे और जब इन्हें बड़ोदरा से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का हुक्म सुनाया गया तो वह अपनी इज्जत बचा कर भाग गये. वैसे भी मिस्त्री समझ गये थे कि इनके पास यहां करने को कुछ खास नहीं था.

कांग्रेस में मिस्त्री का बड़ा कद है. इनकी पूरी हनक है, लेकिन यूपी में कुछ नहीं कर पाये. देश भर में कांग्रेस के जितने भी टिकट फाइनल हो रहे हैं, इसकी सूची में मधुसूदन मिस्त्री के हस्ताक्षर रहते हैं. वह राहुल के विश्वास पात्र हैं, इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इन्हें यहां काम करने की पूरी छूट नहीं मिली थी. अब तो इन्हें बड़ोदरा से टिकट मिल गया है. इस कारण भविष्य में वे प्रदेश कांग्रेस पर शायद ही ध्यान दे पाएंगे. प्रदेश अध्यक्ष डॉ निर्मल खत्री खुद फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं. इसलिए वह अपने क्षेत्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं. वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष राजेशपति त्रिपाठी अपने बेटे ललितेश त्रिपाठी को मिर्जापुर से लड़ाने में व्यस्त हैं. इसलिए वे भी संगठन के लिये समय नहीं निकाल पा रहे हैं. आज की तारीख में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय केवल प्रवक्ताओं के भरोसे चल रहा है. कोई बड़ा नेता मुख्यालय पर बैठने को तैयार नहीं हो रहा है.

प्रवक्ताओं की अपनी मजबुरियां हैं. कहने को तो प्रदेश कांग्रेस में करीब दर्जन भर प्रवक्ताओं की टीम है, लेकिन दिल्ली व प्रदेश के बीच समन्वयन और संवाद की कमी के कारण इनको भी काम करने में मुश्किल आ रही है. प्रवक्ताओं को किस विषय पर क्या बोलना है, कोई गाइडलाइन नहीं मिली है. कांग्रेस आलाकमान यूपी का टिकट फाइनल कर देता है और प्रदेश कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी नहीं होती. कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता पार्टी की हलचल और कार्यक्रमों तक की जानकारी के लिये अक्सर मीडिया पर निर्भर रहते हैं. दिल्ली से राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो जाता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को इसकी भनक ही नहीं लगती है. कांग्रेस के प्रत्याशी तक खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं. वह अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल–सोनिया और अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं की सभा कराना चाहते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है. अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऐसी कोई टीम नहीं बनी है, जो विरोधी दलों द्वारा की जा रही आचारसंहिता के उल्लंघन की शिकायतों को जिलों से प्राप्त कर चुनाव आयोग तक पहुंचाये. किसी प्रत्याशी के सामने यदि कोई कानूनी बाधा आती है, तो भी ऐसी कोई टीम नहीं है, जो इसे दूर करने में प्रत्याशियों की मदद कर सके.

कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इसको जन–जन तक कैसे पहुंचाया जायेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र के वायदों का क्या हुआ. इसका जबाव देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं है. कांग्रेसियों को राहुल गांधी का प्रचार अभियान भी समझ में नहीं आ रहा है. इनकी बातें जमीनी कम, हवा–हवाई ज्यादा है. ठीक वैसे ही, जैसा यूपी के विधानसभा चुनाव में राहुल करते देखे गये थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

खिसक रहा है बसपा का जनाधार

रेनु शर्मा

हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में अंदरूनी गुटबाजी के कारण बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है. प्रदेश सरकार में बसपा कोटे के परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश और विधायक हरिदास के निलम्बन के बाद माना जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक प्रभावित होगा. इस कारण जिले में बसपा कार्यकर्ताओं में मायूसी है. लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने भाजपा छोड़ कर पार्टी में आये देहरादूनवासी डॉ. अंतरिक्ष सैनी को डेढ़ साल पहले ही हरिद्वार से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था. इनको ही पार्टी संगठन की भी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा क्षेत्र संयोजक मनोनीत किया गया था. मुस्लिम और दलित गठजोड़ की लालच में कांग्रेस छोड़ कर बसपा में आये हाजी इस्लाम डॉ. अंतरिक्ष पर इक्कीस साबित हुए और इनके स्थान पर इस्लाम को रातोंरात बसपा सुप्रीमो द्वारा हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया. हरिद्वार के पूर्व विधायक अंबरीश कुमार के भी बसपा में शामिल होकर चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो हाजी इस्लाम भी टिकट को बचाने में ही पूरी ताकत लगाने मे जुटे हैं. बसपा के प्रदेश नेतृत्व की सुरेंद्र राकेश और हरिदास से सीधी लड़ाई ने इस समय जनाधार घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन दोनों को कांग्रेस के पक्ष में खुल कर आने से इनकी लोकसभा चुनाव में भूमिका को सहज ही समझा जा सकता है. राजनीतिक समीक्षकों की राय में इस अवधि में बसपा के मत्रियों एवं विधायकों की कार्यशैली चर्चाओं में है. प्रदेश बसपा नेतृत्व को भी यह सब रास नहीं आया तो इनके बीच ठन गई. बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे सुरेंद्र व हरिदास को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. पीडीएफ के बैनर तले दोनों विधायक कांग्रेस के साथ खुल कर खड़े हैं. इसका सीधा नुकसान बसपा को हो रहा है. बसपा का जनाधार हरिद्वार जिले में लगातार खिसक रहा है. रुड़की में देखा जाये तो मुस्लिम–दलित गठजोड़ भी क्षेत्र में लगातार कमजोर हुआ है. 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को रुड़की सीट पर दस हजार से कुछ कम तो 2013 के निगम चुनाव में बसपा प्रत्याशी को महज 4200 मत मिले थे. 2007 के बाद जिले में भाजपा व कांग्रेस दोनों ने ही बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है. इसका सीधा नुकसान बसपा को हो गया है. लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में संगठन और विधायकों के बीच छिड़ी जंग बसरपा को कहीं भारी न पड़ जाए. बसपा के सामने अब यह मिथक बनाए रखना भी बड़ी चुनौती बन गया है कि बसपा के वोटरों पर नेताओं के आने–जाने का असर नहीं पड़ता और वह नेताओं की बजाय नीले झंडे व हाथी निशान पर अटूट भरोसा रखते हैं. बसपा कोटे

से प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र राकेश, विधायक दल के नेता हरिदास और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मेघराज जरावरे के बीच छिड़ी जंग दोनों विधायकों के निलंबन के बाद सड़क तक आ गई है. सुरेंद्र राकेश और हरिदास समर्थक हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कई जगह प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर इनके पुतले तक फूंकने लगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी बसपा हाईकमान इस मामले को शांत करता नहीं दिख रहा और तो और निलंबन ने प्रदेश में टकराव को बढ़ा ही दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी देश में संभवत: अकेली राजनीतिक पार्टी है, जिसका सामाजिक आधार मुश्किल से खिसकता है. दो विधायकों के करीब–करीब बागी हो जाने से बाद से लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन पर कुछ असर तो पड़ ही सकता है. पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र राकेश को 36828 मत यानी 46.9 फीसद मत मिले थे. झबरेड़ा विस क्षेत्र में बसपा के ही हरिदास को 22781 वोट यानी 32.9 फीसद मत मिले थे. इस तरह दोनों के संयुक्त वोट 59609 बैठते हैं, जो मतों की खासी संख्या है. इन दोनों विधायकों को बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी से अलग भी कर दिया है. ऐसे में इन दोनों विधायकों के कुल वोटों में आधे भी इनके व्यक्तिगत प्रयास से मिले वोट हों तो बसपा के लिए यह शुरुआती झटका हो सकता है. ऐसे में बसपा को इनके वोटों को समेटने के लिए कड़े प्रयास करने होंगे. यही नहीं, दो विधायकों के लोकसभा चुनाव के काम से अलग होने के समूचे प्रदेश में भी वोटरों पर असर पड़ सकता है. यह भी तथ्य है कि मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी संगठन के साथ ही हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हें 24706 यानी विधानसभा क्षेत्र के 34 फीसद वोट मिले थे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बसपा में छिड़ी संगठन और विधायकों के बीच की जंग लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाती है और बसपा इसके बारे में क्या यह मिथक बनाए रख पाएगी कि बसपा का वोटर इसी के साथ रहता है, चाहे नेता कहीं भी खिसक जाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

भाजपा, सपा एवं बसपा की सियासी पैंतरेबाजी तेज

दशरथ प्रसाद यादव

अब तो तय हो गया है कि हिन्दू राष्ट्रवाद एवं समाजवाद अथवा धर्मनिरपेक्षता बनाम तथाकथित साम्प्रदायिकता के बीच विकास भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला उत्थान, स्वास्थ्य, सुराज, सशक्त लोकतन्त्र का स्थान नहीं है. पहले जहां गोरखपुर फैजाबाद और काशी को हिन्दू राष्ट्रवाद से जोड़कर देखने व परखने की प्रवृत्तियां रही हैं, वहीं समाजवाद एवं विशेष रूप से दलित उत्थान के साथ अन्त्योदय एवं सर्वांगीण विकास के सपनों के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आज लुप्त प्राय है. इसमें बड़े तौर या उछाले गये नामों के बीच जनता के मध्य जाकर एक अस्पष्ट सन्देश देने का प्रयास करते हुए जहां सभी सियासी दल उत्तर प्रदेश में बहुत बनाने की नीयत से राजनीतिक गोटियां डाल रहे हैं, उसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस किसी को भी कहीं से प्रत्याशी या समर्थन लेने में गुरेज नहीं दिख रहा है. मोदी बनाम मुलायम सिंह या हिन्दू राष्ट्रवाद बनाम समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता का संघर्ष उसी समय शुरू हो गया था, जब मुलायम सिंह ने आजमगढ़ से प्रचार अभियान शुरू किया और मोदी काशी में और बाद में गोरखपुर तक आये और इसका पीछा करते हुये मुलायम सिंह भी गोरखपुर के इसी मानबेला मैदान में हुंकार भरी, जहां मोदी ने छप्पन इंच के सीने की ललकार को आवाज दी थी.

वर्तमान में यह ज्यादा समीचीन है कि अपने जनाधार को बनाये रखने के लिये भाजपा मोदी जैसे दिग्गज नेता को काशी से मैदान में उतार दिया है और जैसा कि मीडिया में आ रहा है मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़कर इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिये तैयार है. इसी बीच दाद में खाज अमानत में खयानत के रूप में अथवा एक नई दिशा और नई सोच को बढ़ावा देने के लिये अरविन्द केजरीवाल काशी से और मायावती जी फूलपुर से मैदानेजंग में हाथ आजमाने के लिये तैयार ही हैं. ऐसे में गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ एक ओर और मोदी जी दूसरी ओर से मुलायम सिंह के आगे-पीछे हैं तो केजरीवाल और मायावती तीनों को सन्तुलित करने के लिये काफी समर्थ दिख रहे हैं.

भाजपा ने त्रिगत कांग्रेसी सांसद जगदम्बिका पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो भाजपा ने कुशल रणनीति के तहत इन्हें डुमरियागंज से ही भाजपा प्रत्याशी बना दिया. इससे बस्ती और गोरखपुर मंडल के बस्ती डुमरियागंज में सन्तकबीरनगर महराजगंज एवं कुशीनगर संसदीय क्षेत्रों में कमोबेश प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है. डुमरियागंज से तो प्रत्याशी को उतारकर कांग्रेस ने अपना काम तो किया, लेकिन इनका स्थानीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है. विरोध तो जगदम्बिका पाल का भी हो रहा है, लेकिन इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता. बसपा की ओर से अपनी गति पूर्व सांसद सभाले हुये हैं तो सपा में भी कोई बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद जी को थोड़ा लाभ अवश्य मिल सकता है. वैसे यदि मुलायम सिंह के समाजवादी सोच के लोग इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण के लिये मजबूत स्थिति में कम हैं, लेकिन राष्ट्रवादी एवं सांस्कृतिक सोच के लोग अवश्य एक साथ जुड़ते नज़र आ रहे हैं. भाजपा ने इस जुड़ाव को बलिया में भरत सिंह को उतारकर, सलेमपुर में रवीन्द्र कुशवाहा को गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ महराजगंज से पंकज चौधरी, देवरिया से कलराज मिश्र के उतारने के साथ ही बस्ती से युवा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी संतकबीरनगर से शरद त्रिपाठी एवं केसरगंज से सपा के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है. वैसे बलिया, बस्ती, डुमरियागंज ही नहीं, देवरिया में भी भाजपा में अन्तर्कलह भी देखने को मिला है और पुतले फूंकने की कार्यवाही भी की जा रही है. सपा की प्रतिद्वंद्विता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अच्छी है, पर बलिया में चन्द्रशेखर जी के पुत्र और वर्तमान सांसद नीरज शेखर, सलेमपुर से कुशवाहा, गोरखपुर से राजमति निषाद देवरिया से, बालेश्वर यादव पडरौना से, राधेश्याम सिंह महराजगंज से और कुंवर सिंह बलिया से ही तो निर्णायक स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के आजमगढ़ आ जाने से इन प्रत्याशियों का पैरामीटर अवश्य बढ़ेगा और इसका लाभ सन्तकबीर नगर में भालचन्द्र, बस्ती में बृजकिशोर सिंह डिम्पल तथा डुमरियागंज से माता प्रसाद पांडेय को होगा.

आप पार्टी ने जिन नामों की घोषणा की है, वे वास्तव में आम हैं. अपनी क्षेत्रीय पहुंच एवं आप पार्टी की छवि को लेकर वे किसी भी प्रत्याशी को क्षति तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच अपनी पहचान कायम रखने ताकत किसी में नहीं है. बसपा का जनाधार घटा नहीं है. इससे बस्ती में रामप्रसाद चौधरी डुमरियागंज में मुकिम, सन्तकबीर नगर में कुशल तिवारी के कुशल नेतृत्व का लाभ और भी बढ़ जायेगा, यदि मायावती जी फूलपुर से चुनाव लड़ जायें. वैसे मीडिया की खबर यह है कि अब वे कहीं से भी प्रदेश में संसदीय चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगी. मायावती पूर्वांचल पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास करेंगी. भाजपा ने काशी में मोदी को उतारने के साथ ही क्षेत्रीय दल अपना दल को मिलाने के साथ छोटे जाति के मतों को अपनी ओर यदि आकृष्ट कर लिया तो काशी से इनका दमखम बरकरार रह सकता है. कांग्रेस के साथ प्रचार में पिछड़ने का गम इसलिये भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रत्याशी काफी पहले हैं और आप पी एन सिंह को छोड़कर जुझारू होने के बावजूद भोला पांडेय, श्याम कुंवर, संजय जायसवाल तथा डुमरियागंज से पटेल एवं सन्तकबीर नगर से पांडेय की स्थिति महत्वहीन सी रही तो है. पूर्वांचल में निर्दलीय ताकतवर प्रत्याशी कोई नहीं है, इसीलिये क्षेत्रीय सन्तुलन को बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी ज्यादा पैठ जो पार्टी बना सकेगी, उसे उतना ही लाभ होगा, लेकिन समझदार मतदाताओं के बीच अब एक ऐसी रेखा खिंच रही है, जो राष्ट्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाकर ही विश्लेषित की जा सकती है.

पूर्वांचल के राजनीतिक दंगल में कोई किसी के कन्धे पर हाथ रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को डर सता रहा है कि किसके दांव पर कौन चित होगा. मतदाता यदि मोहरा नहीं बना तो जिस अगुवाई की अपेक्षा का राष्ट्रीय पार्टियों ने पूर्वांचल की राजनीति को इस स्तर पर पहुंचाया है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि इन्हें अभी बहुत कुछ करना होगा, जबकि प्रदेश की सपा एवं बसपा को थोड़ी सी मेहनत करने पर अधिक लाभ मिल सकना संभव है. अभी यह काल के गर्त में है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन आगाज जोरदार हो रहा है, तो अंजाम भी जोरदार ही होगा. ■

BJP

चुनाव निशान

वर्तमान में यह ज्यादा समीचीन है कि अपने जनाधार को बनाये रखने के लिये भाजपा मोदी जैसे दिग्गज नेता को काशी से मैदान में उतार दिया है और जैसा कि मीडिया में आ रहा है मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़कर इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिये तैयार है. इसी बीच दाद में खाज अमानत में खयानत के रूप में अथवा एक नई दिशा और नई सोच को बढ़ावा देने के लिये अरविन्द केजरीवाल काशी से और मायावती जी फूलपुर से मैदानेजंग में हाथ आजमाने के लिये तैयार ही हैं. ऐसे में गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ एक ओर और मोदी जी दूसरी ओर से मुलायम सिंह के आगे-पीछे हैं तो केजरीवाल और मायावती तीनों को सन्तुलित करने के लिये काफी समर्थ दिख रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा के लिए अब भी खंडूडी है जरूरी

राजकुमार शर्मा

स्वच्छ छवि और कड़क प्रशासक के साथ सैन्य पृष्ठभूमि के भुवनचंद्र खंडूडी भाजपा के लिए अब भी जरूरी हैं. इसी वजह से जनरल को मोदी भी अपनी पहली पसंद मानते हैं. यही वजह है कि युवाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति के बावजूद भाजपा ने पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से खंडूडी पर ही दांव खेलने को मुफीद माना. अब तक के राजनीतिक हालात पर नज़र डालें तो राज्य की पांच संसदीय सीटों में टिहरी की राज-परिवार की सीट के बाद जनरल खंडूडी की ही दूसरी सीट है, जिसे मोदी के मिशन 2014 के लिए सबसे सुरक्षित मानी जा रही है. 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बूते मिशन 272 प्लस में जुटी भाजपा के लिए एक-एक सीट महत्वपूर्ण है. देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के मद्देनजर पार्टी ने स्वच्छ और ईमानदार छवि के प्रत्याशियों को खासा महत्व दिया है. पहले केंद्र सरकार में भूतल परिवहन मंत्री और फिर राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर खंडूडी की साफ-सुथरी छवि ने पार्टी में इनकी स्वीकार्यता बनाए रखी है. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी खंडूडी के कामकाज के प्रशंसक रहे हैं. यही वजह है कि युवाओं को टिकट में तवज्जो देने की पार्टी की रणनीति पर भी खंडूडी भारी पड़े. पार्टी ने इस बार ऐलान किया था कि उम्रदराज नेताओं पर दांव नहीं खेला जाएगा. इस वजह से माना जा रहा था कि खंडूडी को टिकट देने में इनकी उम्र बाधा बन सकती है. पार्टी ने अधिक उम्र के बावजूद खंडूडी पर भरोसा जता कर खंडूडी है जरूरी के नारे की पुन: पुष्टी कर दी है. इसके साथ ही सैन्य बहुल उत्तराखंड में खंडूडी की सैन्य पृष्ठभूमि पर पार्टी पहले से ही भरोसा करती रही है. राज्य में सेवारत और पूर्व सैनिकों और अर्द्धसैनिकों की अच्छी-खासी संख्या है. सेवानिवृत्त मेजर जनरल खंडूडी लंबे अरसे से इस सीट पर पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वर्ष 1991 से वर्ष 2004 तक खंडूडी तीन बार इस सीट पर जीत का परचम लहरा चुके हैं. इस सीट पर भाजपा की ओर से भेजे गए पैनल में अनिल बलूनी और मोहन सिंह रावत गांववासी का नाम भी शामिल था. नरेंद्र मोदी खेमे से नजदीकी के चलते अनिल बलूनी की दावेदारी ने जोर पकड़ा. वहीं मोहन सिंह रावत गांववासी ने तो बाकायदा अपनी दावेदारी पेश भी की. यही नहीं, टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने नाराजगी भी जताई. सच्चाई यह भी है कि खंडूडी की छवि और कद के आगे उक्त दोनों की दावेदारी स्वयं ध्वस्त हो गयी. इस बार के चुनाव में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को भांप कर कांग्रेस के दिग्गज नेता सतपाल महाराज ने जनरल खंडूडी के हाथों हार का मुंह देखने से अच्छा भाजपा शरणम् गच्छामि का रास्ता चुन लिया. महाराज ने इसके लिए जातिवादी (ठाकुरवादी नेता) राजनाथ सिंह का दामन थाम कर संघ परिवार से गलबहियां कर लिया. गढ़वाल लोकसभा के वर्तमान सांसद सतपाल महाराज द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी इस सीट को लेकर कांग्रेस हाईकमान गंभीर हो गयी है. भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वी.सी. खंडूडी जनरल के मुकाबले जनरल गंभीर सिंह नेगी को उतार कर लोहा का जबाब लोहा से देने पर काम हो रहा है. कांग्रेस संख्या बल और खींचतान को देखते हुए किसी मंत्री को उतारने का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी पर ध्यान केंद्रित हो गया है. महाराज के जाने के बाद जनरल नेगी के साथ कई दौर की वार्ता भी मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष की हो चुकी है. जनरल नेगी ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि वे मैदान में आने को तैयार हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि सतपाल महाराज के भाजपा में जाने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गढ़वाल लोकसभा सीट को बहुत गंभीरता से लिया है. ऐसे में वे चाहते हैं कि यहां से कोई बड़ा चेहरा मैदान में होगा तो इसके लिए काम करना आसान होगा. जनरल नेगी सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं. महाराज के कांग्रेस छोड़ने से पहले ही नेगी का नाम भी संभावित प्रत्याशियों में शुमार हो चुका था. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस सीट पर अच्छा परिणाम ला पायी तो न केवल भाजपा, बल्कि महाराज को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा. माना जा रहा है कि गढ़वाल सीट पर पूर्व सैनिकों की तादाद व भाजपा प्रत्याशी के खुद रिटायर्ड जनरल होने के चलते कांग्रेस के सामने जो चुनौती है, वह किसी बड़े चेहरे को ही उतारने की है. इसमें अब तक जो भी नाम चर्चाओं में हैं, इनमें जनरल नेगी का ही नाम सबसे उपयुक्त माना जा रहा है. कांग्रेस से कई अन्य लोगों ने दावेदारी की है. इनमें नेगी को ही वजनदार माना जा रहा है. ■

महराज के सिर संघ की काली टोपी

रेनु शर्मा

कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद संघ परिवार पहले महराज के सिर पर सजने वाली गांधी टोपी को उतरवा कर संघ की काली ठोपी पहनाने की फिराक में है. सतपाल महाराज संभवत: कभी भी संघ की शाखाओं में नहीं गए, न कभी अपने सिर पर काली टोपी लगाई, फिर भी संघ इनके विशेष रूप से हिन्दुत्ववादी चेहरे पर फिदा है. अभी तक स्पष्ट रूप से यह तय नहीं हो पाया है कि महाराज को कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर इन्हें केवल पार्टी के प्रचार अभियान में ही लगाया जाएगा. इससे ऐसा लग रहा है कि संघ महाराज को अपने खास मिशन के तहत कुछ खास बिन्दुओं पर महाराज को लगा चुका है. माना जा रहा है कि खास मिशन के कुछ बिन्दुओं पर महाराज ने कसरत भी शुरू कर दिया है. संघ परिवार कांग्रेस को समाप्त करने के लिए महराज को विभिषण की भूमिका में प्रयोग करने की तैयारी में है. इस खास मिशन के अंतर्गत कई ऐसे महत्व-पूर्ण बिन्दु हैं, जिन पर एक बार फिर से संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को एक साथ मिलकर बैठक करनी है. अभी संघ और पार्टी के केंद्रीय नेता उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. महाराज को पूरी तरह से फ्री हैंड देने में कुछ समय लगने की संभावना है. तत्काल तो महाराज ने जिन बिन्दुओं पर कसरत करना शुरू किया है, इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर एक विशेष खाका तैयार करना है, ताकि यदि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो किस तरह से आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास किया जाए. इसके पीछे छिपा हुआ राज यह है कि प्रदेश में आई आपदा के बाद संघ ने आपदा पीड़ितों की मदद को लेकर प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास का एक मॉडल पेश किया था. राज्य सरकार ने इस मॉडल पर किसी तरह का कोई विचार ही नहीं किया. संघ एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि यदि महाराज को फिलहाल इस मिशन के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जाए तो इसका लाभ पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव होने में अभी समय है और महाराज ने कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि न ही केंद्र और न प्रदेश की सरकार ने आपदा पीड़ितों की मदद की है. प्रदेश में आपदा पीड़ितों की संख्या ज्यादा है और पीड़ितों का गुस्सा सरकार के प्रति लगातार बना हुआ है. दूसरा मिशन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन को लेकर है. महाराज ने कई बार भरोसा दिलाया कि पहाड़ पर रेल चढ़ाकर ही दम लेंगे, सफलता नहीं मिली. लिहाजा, लोगों में गुस्सा है. महाराज को अब फिर नए सिरे से पर्वतीय लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि भाजपा के आते ही वे इस सपने को हर हाल में पूरा करेंगे. इस पर भी संघ और महाराज के बीच सहमति बन गई लगती है. सतपाल महाराज अब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी की तरक्की एवं प्रदेश का विकास कैसे हो, निश्चित रूप से इनका सहयोग पार्टी लेगी. इनके पास काफी लंबा अनुभव है और इसका लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जरूर मिलेगा. प्रदेश की समस्याओं से महाराज अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए सुलझाने में वे काफी मददगार साबित होंगे. ■

राज्य सरकार ने इस मॉडल पर किसी तरह का कोई विचार ही नहीं किया. संघ एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि यदि महाराज को फिलहाल इस मिशन के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जाए तो इसका लाभ पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव होने में अभी समय है और महाराज ने कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि न ही केंद्र और न प्रदेश की सरकार ने आपदा पीड़ितों की मदद की है.

काशी की कुश्ती में मोदी को घेरने की तैयारी

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

काफ़ी अरसे बाद पूर्वांचल में इस बार विकास की फ़सल लहलहाने के लिए तैयार है. वजह है लोकसभा चुनाव का लोकलुभावन मौसम. इस मौसम में धर्म एवं संस्कृति की राजधानी काशी सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियों में है. मिल्लत, आस्था और संस्कृति के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान रखने वाली नगरी काशी इस बार सियासत के अखाड़े के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. कभी लाल बहादुर शास्त्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी, राजनारायण, वीर बहादुर सिंह, चन्द्रशेखर जैसे कई दिग्गज नेताओं के कारण पूर्वांचल का सियासी पारा पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता था. वही दौर एक बार फिर लौट आया है, जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से ताल ठोंकी है. मोदी के मैदान में उतरते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी अपनी दावेदारी ठोंकते हुए काशी से चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है. कांग्रेस पार्टी भी यहां से बड़ा दांव खेल सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों पर विश्वास करें तो कांग्रेस यहां से दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार सकती है. काशी में चुनावी कुश्ती के दांव-पेंच यहीं से खत्म नहीं होते, बल्कि क़ौमी एकता दल के बाहुबली विधायक मोख्तार अंसारी भी पिछली बार की तरह इस बार भी वाराणसी को ही अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए दावा ठोक रहे हैं. समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने साथी कैलाशनाथ चौरसिया को सबसे पहले अखाड़े में उतार रखा है. हांलाकि अंदर से ख़बर ये भी आ रही है कि नरेन्द्र मोदी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी 'आप' को समर्थन दे सकती है.

काशी के अलावा पूर्वांचल का सियासी पारा आज़मगढ़ की वजह से भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के यहां से लोकसभा लड़ने की अटकलों पर अब मुहर लग गई है, वहीं मायावती ने बसपा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुलायम का पीछा करते उतारने की क़वायद रची है. मुलायम ने काशी में मोदी को घेरने के लिए आज़मगढ़ से चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है. दोनों ही जगहों से कई दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने की वजह से पूर्वांचल बरसों बाद फिर चर्चा में है. पिछले कई चुनावों में पूर्वी उत्तर प्रदेश मोख्तार अंसारी, अतीक़ अहमद, धनंजय सिंह, विजय मिश्र और रमाकांत यादव जैसे बाहुबलियों की दावेदारी से चर्चा में रहता था. चुनाव में इनके हारने-जीतने से जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय नेताओं की आमद से जनता की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं. सब अपनी-अपनी पसंद के उम्मीदवारों को विजयी रथ पर सवार करने के लिए प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. वोटरों का मानना है कि जीत चाहे जिसकी भी हो, पर पूर्वांचल का बरसों से रुका हुआ विकास पटरी पर लौट आएगा. देश की राजनीति में कई क़द्दावर नेताओं को पनपाने वाले पूर्वांचल को आज तक वो मुक़ाम नसीब नहीं हो सका, जिसके यहां के बाशिन्दे हक़दार हैं. मोदी, केजरीवाल और मुलायम के पूर्वांचल से चुनाव लड़ने की अटकलों पर मुहर लगते ही वोटर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है. अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसकी नैया पार लगाएगी और किसे डुबोएगी, लेकिन अगर बन रहे चुनावी समीकरणों पर ग़ौर करें तो आज़मगढ़ पूर्वांचल में सपाइयों का सबसे मज़बूत क़िला रहा है. हालिया विधानसभा चुनाव में भी सपा ने यहां अपनी धाक जमाई है. लिहाज़ा, मुलायम सिंह यादव यहां क़िला फ़तेह कर लें तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है. वहीं दूसरी और काशी कुश्ती में मोदी के खिलाफ़ चक्रव्यूह रचा जा रहा है. देश की राजनीति को नई दिशा देने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल जहां मोदी के खिलाफ़ लगातार ज़हर उगल रहे हैं तो वहीं मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रहे क़ौएद विधायक मोख्तार अंसारी शंट खींचे हुए हैं. कांग्रेस क़यासबाजियों और अटकलों के बीच चर्चा में है. ख़बर है कि दिग्गी राजा चुनावी अखाड़े में कूदे तो ठीक, नहीं तो खानापूर्ति के लिए कोई मैदान में खड़ा हो जाएगा. यही हाल सपा का भी है. पार्टी ने सबसे पहले से अपने उम्मीदवार कैलाशनाथ चौरसिया को मैदान में उतार रखा है, जो मोदी और केजरीवाल के मुक़ाबले कहीं टिकते नज़र नहीं आते. इससे अटकलों का दौर और तेज़ होता जा रहा है कि कहीं सपा और कांग्रेस 'आप' को इंटरनली सपोर्ट तो नहीं कर रही हैं?

खैर, आज़मगढ़ में मुलायम सिंह यादव और नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के बीच ज़बरदस्त मुक़ाबला होने के समीकरण बन रहे हैं. वहीं वाराणसी संसदीय क्षेत्र से मोदी बनाम केजरीवाल की रोमांचक जंग देखने को मिलेगी. ■

BJP

वाराणसी संसदीय क्षेत्र से 1952 से 2009 तक के सांसद

वर्ष	सांसद	पार्टी
1952	रघुनाथ सिंह	कांग्रेस
1957	रघुनाथ सिंह	कांग्रेस
1962	रघुनाथ सिंह	कांग्रेस
1967	सत्य नारायण सिंह	सीपीआईएम
1971	राजाराम शास्त्री	कांग्रेस
1977	चन्द्रशेखर	कांग्रेस
1980	पं. कमलापति त्रिपाठी	कांग्रेस
1984	श्यामलाल यादव	कांग्रेस
1989	अनिल शास्त्री	जनता दल
1991	शंकर प्रसाद जायसवाल	भाजपा
1996	शंकर प्रसाद जायसवाल	भाजपा
1998	शंकर प्रसाद जायसवाल	भाजपा
1999	शंकर प्रसाद जायसवाल	भाजपा
2004	डॉ राजेश कुमार मिश्र	कांग्रेस
2009	डॉ मुरली मनोहर जोशी	भाजपा

मोदी, केजरीवाल और मुलायम के पूर्वांचल से चुनाव लड़ने की अटकलों पर मुहर लगते ही वोटर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है. अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसकी नैया पार लगाएगी और किसे डुबोएगी, लेकिन अगर बन रहे चुनावी समीकरणों पर ग़ौर करें तो आज़मगढ़ पूर्वांचल में सपाइयों का सबसे मज़बूत क़िला रहा है. हालिया विधानसभा चुनाव में भी सपा ने यहां अपनी धाक जमाई है. लिहाज़ा, मुलायम सिंह यादव यहां क़िला फ़तेह कर लें तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है.

भाजपा में बदलाव की बयार

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश भाजपा में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, जो काम भाजपा के बड़े-बड़े धुरंधर नहीं कर पाये, उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी अमित शाह की रिपोर्ट पर नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया. भले ही मोदी ने पार्टी अध्यक्ष के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई हो, लेकिन प्रदेश भाजपा में बदलाव दिखने लगा है. पुरानी पीढ़ी के नेता, जो लम्बे समय से प्रदेश भाजपा के प्रमुख पदों पर कुंडली मारकर बैठे थे. जमीनी हकीकत को अनदेखा करके अनाप-शनाप फैसले लिया करते थे. मोदी की टीम के चलते इससे शायद प्रदेश भाजपा को छुटकारा मिल जाये. भला ऐसे नेताओं की क्या जरूरत, जिनके सहारे भाजपा न तो केन्द्र में मजबूत हो पाये, न ही राज्य में कोई गुल खिला सके. कहने को तो भाजपा में कथित तौर पर कद्दावर नेताओं की लम्बी-चौड़ी लिस्ट रहती थी, लेकिन यह नेता पार्टी का भला करना तो दूर, अपनी सीट भी नहीं बचा पाते थे. भाई-भतीजावाद और टांग खिंचाई की राजनीति इनके सिर चढ़कर बोलती थी. सब गुट बनाकर राजनीति कर रहे थे. केशरीनाथ त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, ओम प्रकाश सिंह, सूर्य प्रताप शाही, विजय कटियार, लाल जी टंडन आदि तमाम नेता आज भले ही टिकट न मिलने का मातम मना रहे हों, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर भाजपा आलाकमान इन नेताओं पर दांव खेलती तो इसका हश्र बुरा ही होता. विधानसभा चुनाव में इनका क्या हश्र हुआ था, यह किसी से छिपा नहीं है. यह वो नेता हैं, जो अपने बुते पर तो चुनाव जीतने की क्षमता रखते नहीं हैं, मोदी लहर में अपनी नैया पार करना चाहते थे. अगर भाजपा के मठाधीश बने यह नेता लोकसभा चुनाव के लिये इतने ही गंभीर होते तो मैदान में काफी पहले से दिखाई देने लगते. असलियत तो यही है कि यह लोग चुनाव लड़ते भी नहीं, अगर भाजपा के पक्ष में माहौल न होता. मोदी के उभार के बाद जरूर यह सब हाथ-पैर मारने लगे थे. इसी प्रकार न तो लखनऊ से मौजूदा सांसद लाल जी टंडन जीत पाते और न ही वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी की जीत सुनिश्चित हो पाती. बदलाव प्रकृति का नियम है. यह बात भाजपा में कुंडली मारकर बैठे बुजुर्ग नेताओं को अपने आप समझ में आ जाती तो संघ और आलाकमान को ऐसे नेताओं को आइना नहीं दिखाना पड़ता. सबसे कष्टदायक बात यह है कि इन नेताओं ने अपनी मठाधीशी को चमकाये रखने के चक्कर में नेताओं की नई टीम को पनपने का ही मौका नहीं दिया. यूपी में सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार होती तो शायद मोदी को अपना मिशन पूरा करने के लिये आयातित नेताओं पर भरोसा नहीं करना पड़ता. यह बात सही है कि करीब दो दर्जन बाहरी नेताओं को भाजपा ने टिकट थमाया है, लेकिन इसके लिये यही उम्रदराज नेता जिम्मेदार हैं. बात जहां तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और रालोद जैसे भाजपा विरोधियों की है तो इनको भी पता है कि बीजेपी में जो बदलाव हो रहा है, इसका असर इनके ऊपर भी पड़ेगा. भाजपा विरोधी सभी दलों के नेता चाहते थे कि यूपी में भाजपा उभर नहीं पाये, क्योंकि यहीं से केन्द्र का मार्ग प्रशस्त होता है. हास्यास्पद लगता है कि जब समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरा बनने को आतुर मनोज पांडेय जैसे नेता और मंत्री भाजपा के देवरिया के ब्राह्मण प्रत्याशी कलराज मिश्र और कानपुर के बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी की आड़ लेकर भाजपा को ब्राह्मण विरोधी करार देने की साजिश रचते हैं. कलराज मिश्र देवरिया से और जोशी कानपुर से चुनाव लड़कर खुश हैं, लेकिन सपा को यह बात नहीं पच रही है. वह ब्राह्मणवाद के नाम पर दोनों के उत्पीड़न का राग अलापना बंद ही नहीं कर रही है. इसके सुर में कांग्रेस भी सुर मिला रही है. सच्चाई यही है कि आज की तारीख में जिन नेताओं को किनारे किया गया है, वह जमीनी लड़ाई लड़ने लायक रह ही नहीं गये थे. फिर इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही क्यों न हों. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कोई भाजपा नेता होगा, जो यूपी की जनता की नब्ज टटोल पाया हो. राजनाथ ने दिल्ली का रास्ता न पकड़ा होता तो हो सकता है कि इनके माथे पर भी अब तक नाकामयाबी का दाग लग चुका होता.

उत्तर प्रदेश भाजपा के लिये उम्रदराज नेताओं के अलावा टिकट की चाह रखने वाले साधु-संत भी मुसीबत बने हुए हैं. संत समाज में भाजपा ने अभी साध्वी उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, सावित्री फूले के अलावा योगी आदित्यनाथ और साक्षी महराज को ही टिकट थमाया है. राम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा ने जिन संतों को गले लगाया था, मोदी ने उन्हें हासिये पर डाल दिया. पर संत हैं कि सियासत छोड़ना नहीं चाहते. इसी को लेकर भाजपा आलाकमान और साधु-संतो के बीच जंग छिड़ गई है. भाजपा ने संत समाज की साध्वी उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, सावित्री फुले व साक्षी महराज को क्रमश: झांसी फतेहपुर, बहराइच व उन्नाव से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन टिकट न मिलने से अयोध्या आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉ रामविलास वेदांती और स्वामी चिन्मयानंद नाराज चल रहे हैं. स्वामी अटल मंत्रिमंडल में गृह राज्यमंत्री रह चुके हैं. कहने वाले तो यही कहते हैं कि ये साधु-संत भी मोदी के सहारे अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मोदी, जो अपनी कट्टर हिन्दुत्ववादी छवि तोड़ने में लगे हैं, इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संतो को गले नहीं लगाया. मोदी काल में गोरक्ष पीठ को छोड़कर अन्य सभी साधु-संतों की पकड़ व पैठ भाजपा में कमजोर पड़ रही है. गौरतलब हो कि वर्ष 1991 के चुनाव में मंदिर मुद्दे की लहर पर सवार भाजपा ने धार्मिक प्रवचन करने वाले स्वामी चिन्मयानंद को बदायूं से, संत विश्वनाथ दास शास्त्री को सुल्तानपुर से, स्वामी सुरेशानंद को जलेसर से तथा सच्चिदानंद साक्षी महाराज को मथुरा से उतारा था. सभी संत जीत भी गये थे, लेकिन धीरे-धीरे भाजपा नेतृत्व ने साधु-संतों से किनारा करना शुरू कर दिया. इस दौरान गोरखपुर की गोरक्ष पीठ को छोड़ सभी ने अपना तेज गवां दिया था. पीठ के महंत दिग्विजय नाथ, इनके बाद महंत अवैद्यनाथ और इनके उत्तराधिकारी व मौजूदा सांसद योगी आदित्यनाथ को छोड़ राजनीति में स्थायी तौर पर कोई ठिकाना नहीं बना पाया. महंत अवैद्यनाथ सन 1962 और 70 में विधायक रहे. 1989 में गोरखपुर से ही हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद चुने गए. बाद में भाजपा ने इन्हें अपने साथ ले लिया. 1991 व 96 में अवैद्यनाथ गोरखपुर से भाजपा के सांसद चुने गए. इसके बाद इनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ 1998, 1999, 2004, 2009 के चुनावों में भाजपा के टिकट पर सांसद चुने जा चुके हैं. भाजपा ने योगी के साथ 2004 के चुनाव में वेदांती व चिनमयानंद को क्रमश: अमेठी व जौनपुर से चुनाव लड़ाया. पर ये दोनों सफल नहीं हो पाए. नतीजतन, 2009 में भाजपा ने साधुओं की सियासत से ही तौबा कर ली थी. इस बार से भी जिन साधु-संतों को टिकट दिया गया है, इनकी छवि धार्मिक कम, सामाजिक ज्यादा है. चाहे उमा भारती हों या फिर आदित्यनाथ योगी और साक्षी महराज जैसे संत. ■

उलेमाओं ने किया मुलायम का गुणगान

संदीप कश्यप

हिन्दू-मुस्लिम एकता का नारा गांधी जी के बाद मुलायम सिंह यादव ने ही पेश किया. गांधी जी ने इस ताकत के बल पर अंग्रेजो को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया था. मुलायम ने फिरकापरस्त ताकतों को सिर नहीं उठाने दिया है. हम सबको ईमानदारी से इनका साथ देना है, ताकि देश मजबूत रहे और विकास में अवरोध न हो. श्री यादव के केन्द्र की सत्ता में रहने से मुस्लिमों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि हासिल होगी. ये उदगार बड़ी संख्या में लखनऊ आए अमीर-ए-जमात, आईमा हजरात, मदरसों के नाजिमें आला तथा उलेमा-ए-इकराम ने व्यक्त किए.

मुस्लिम उलेमाओं ने मुलायम और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बैठक के दौरान मुलायम के प्रति अपने मन के उदगार व्यक्त किये तो मुलायम ने उलेमाओं को आगाह करते हुए कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस लोकसभा चुनाव में मतदाता सेक्युलर ताकतों को चुनेगें या फिरकापरस्त ताकतों को. फिरकापरस्त ताकतों के सत्ता में आने से देश की एकता और हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद पर असर पड़ेगा और सामाजिक तानाबाना टूट जाएगा. इन्होंने कहा कि गुजरात में विकास का झूठ सामने आने के बाद जनता मुस्लिमों के कत्लेआम के लिए नेरन्द्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगी.

तमाम मुस्लिम नुमाइंदों से घिरे हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सरकार हमेशा कमजोर और अन्याय के शिकार लोगों के साथ खड़ी रही है. इसने समाज के सभी वर्गों के लाभ की योजनाएं शुरू की तो इसके खिलाफ कुप्रचार शुरू हो गया. किसान, नौजवान, मुसलमान और गरीब की मदद प्राथमिकता से की गई. लैपटॉप, किसान बीमा, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, कन्या विद्याधन, कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण, सभी योजनाओं में मुस्लिमों को 20 प्रतिशत का योगदान, ये ऐसी योजनाएं हैं, जिनका कहीं मुकाबला नहीं.

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही कमजोर है. इसकी 10 साल की उपलब्धियां कहीं नजर नहीं आती हैं. बसपा का भाईचारा पता नहीं कहां गुम हो गया. भाजपा चालाक और फिरकापरस्त पार्टी है, जो यूपी में मोदी के सहारे सीटें जीतकर सत्ता में आना चाहती है. इसका विकास से कोई मतलब नहीं. मुजफ्फरनगर का दंगा भाजपा ने साजिशन भड़काया था. श्री यादव ने कहा कि यूपी के चुनावों पर देश की निगाहें लगी हैं. यहां का परिणाम देश की राजनीति बदलेगा. नेताजी मुलायम सिंह यादव के रहते फिरकापरस्त ताकतें अपनी कोशिशों और साजिशों से सफल नहीं होगी. समाजवादी पार्टी इनसे सीधी लड़ाई को तैयार है. पहले वे रैलियों के मुकाबले में हार गए, फिर विकास और उपलब्धियों में भी पिछड़ गए. कांग्रेस-भाजपा दोनों की अर्थनीति एक है. बड़े पूंजी घराने इनकी मदद करने में लगे हैं.

इस मौके पर कई मुस्लिम उलेमाओं ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों फिरकापरस्ती को बढ़ावा देनेवाली पार्टियां हैं. एक दीवार के पीछे है तो दूसरी सामने खड़ी है. मुसलमान सेक्युलर ताकतों के साथ रहता आया है. समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, जो सेक्युलर किरदार को आगे बढ़ाती है. मुसलमानों को कम्यूनल चेहरे को स्याह करना है. नेताजी तथा मुख्यमंत्री से जो उलेमा और अमीर-ए-जमात मिले इनमें प्रमुख थे मौलाना गुफरान साहब, मेहंदी हसन, राजा नूर हसन, अफजाल अहमद, मुफ्ती सलीमउद्दीन, डॉ अली बख्श, हाजी मो आरिफ, मौ. मो. अहमद नदवी, मौ. असद उल्लाह नदवी, अब्दुल कादिर खान, हाफिज नूर उल्ला, मौ. सगीर साहब, हाफिज रहमत अली, शौकत अली, मो. तौकीर नदवी, कारी मो. परवेज आलम, मो. अफजल, मौ. मिफजल, हाफिज यूनुस, मौ. जसीमुद्दीन, नफीस अहमद, शकील अहमद, मो. एबाद, फखरूल हसन आदि. ■

तमाम मुस्लिम नुमाइंदों से घिरे हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सरकार हमेशा कमजोर और अन्याय के शिकार लोगों के साथ खड़ी रही है. इसने समाज के सभी वर्गों के लाभ की योजनाएं शुरू की तो इसके खिलाफ कुप्रचार शुरू हो गया. किसान, नौजवान, मुसलमान और गरीब की मदद प्राथमिकता से की गई. लैपटॉप, किसान बीमा, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, कन्या विद्याधन, कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण, सभी योजनाओं में मुस्लिमों को 20 प्रतिशत का योगदान, ये ऐसी योजनाएं हैं, जिनका कहीं मुकाबला नहीं.

feedback@chauthiduniya.com

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111